प्रकाशन तिथि : 20 जून, 2021* वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-6

राजस्थान सुजस

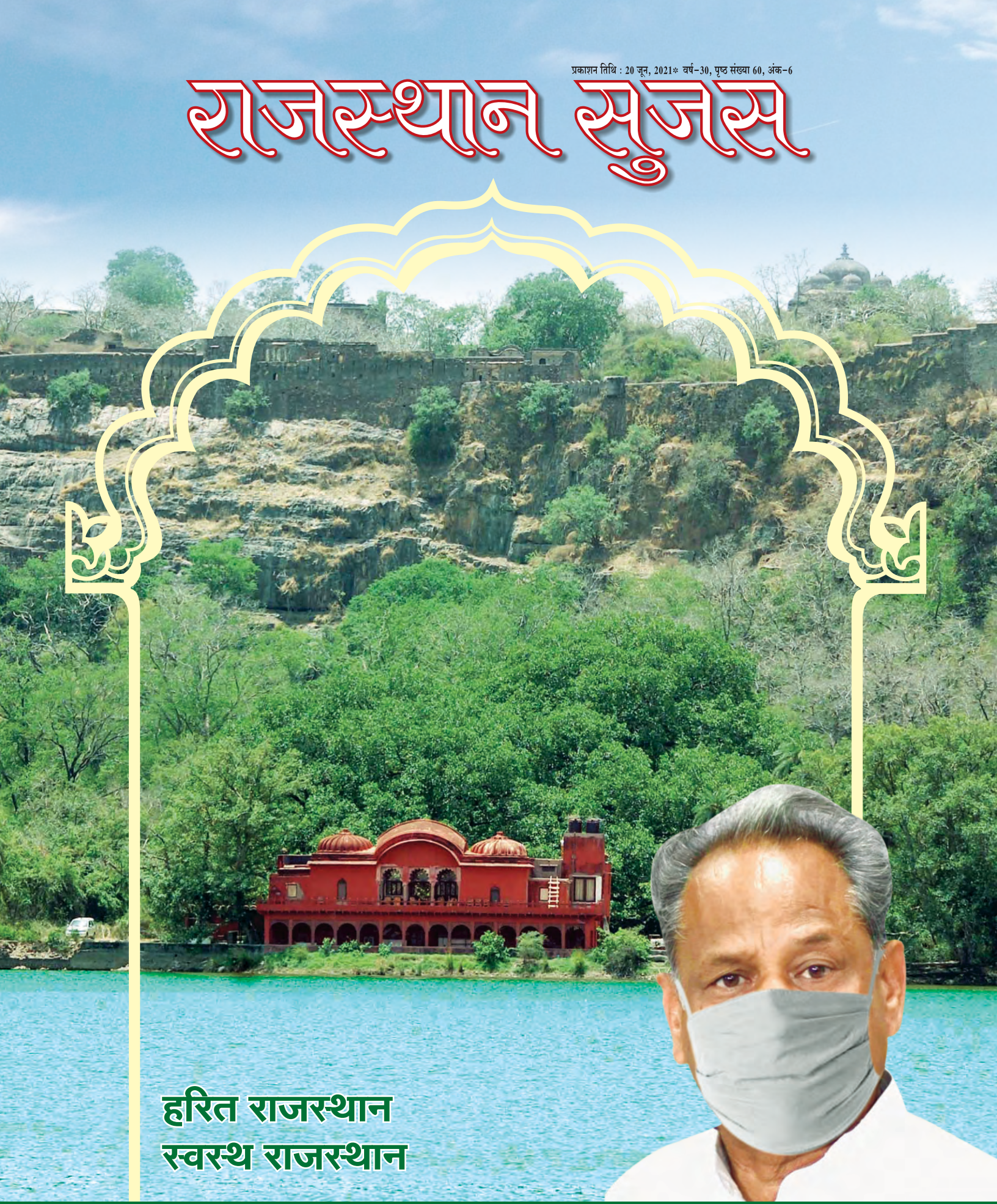

हरित राजस्थान
स्वस्थ राजस्थान

पर्यावरण विशेषांक

बीजों के लिए खेती

गर्मियों में जब माही नदी के तट खाली होते हैं तो यहां के आदिवासी काश्तकार खरबूजे की खेती करते हैं। मानसून आने से ठीक तीन महीने पहले तक माही बैकवाटर क्षेत्र में चारों तरफ खरबूजे की खेती के कारण हरियाली का साम्राज्य दिखाई देता है। ताज्जुब की बात है कि ये काश्तकार खरबूजे की खेती फलों के लिए नहीं अपितु इनके बीजों के लिए करते हैं। किसान बताते हैं कि दिन भर में एक खेत से 40 से 50 किलो बीज एकत्र कर लिए जाते हैं। बीजों को निकाल कर इन्हें खेतों के किनारे ही एक स्थान पर छलनी से छान कर सुखाया जाता है और फिर इन्हें स्थानीय बाजार में बेच दिया जाता है। ये बीज औषधीय महत्त्व के होते हैं इसलिए महंगे खरीदे जाते हैं। इन बीजों से ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए औषधि तैयार की जाती है।

– डॉ. कमलेश शर्मा
उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, उदयपुर

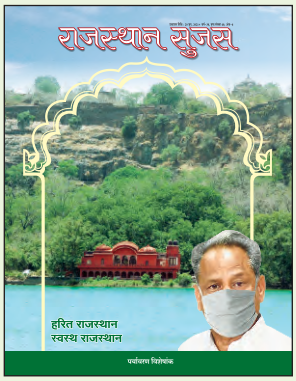

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
मुकेश आर्य

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

मुद्रण
प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302005
मो. 98292-71189
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

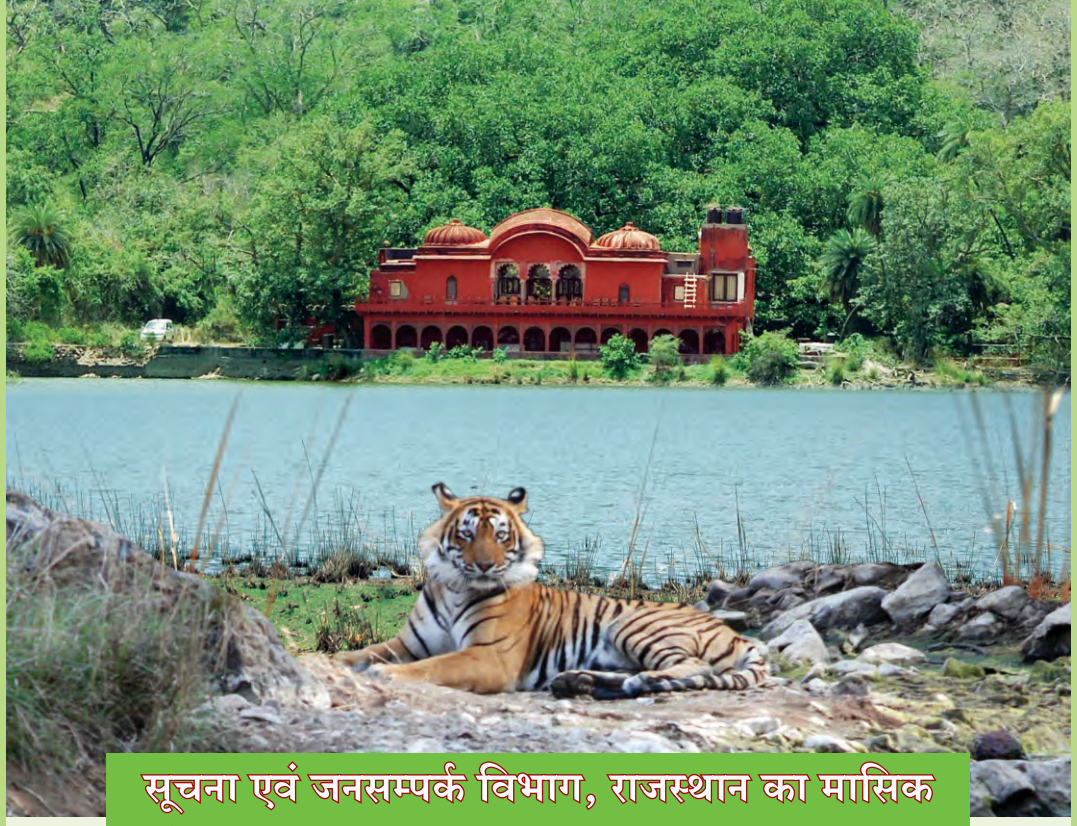

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 06 **जून, 2021**

इस अंक में

आवरण कथा

05

साक्षात्कार

16

पर्यावरण संरक्षण

23

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
कोरोना प्रबन्धन	14
Global Warming	18
Health Insurance	20
विश्व पर्यावरण दिवस	22
घर-घर औषधि योजना	24
वन्य जीव	28
सफलता की कहानी	32
चंबल बेसिन	34
चिपको आन्दोलन	39
नवीन योजना	40
सामान्य जानकारी	42
पेयजल	44
शारीरिक शिक्षा	45
स्मृति शेष	46
वृक्षारोपण	47
लोकरंग	48
खेल खिलाड़ी	49
इतिहास पुरुष	50
मेरा गांव - मेरी जिम्मेदारी	51
प्रतिक्रिया	58
शिलान्यास	59
धरोहर	60

फोटो–फीचर

30

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

सामयिकी

15

बातचीत

17

हनुमानगढ़ विशेष

52

उत्कृष्ट कोरोना प्रबन्धन

जन भागीदारी एवं राज्य सरकार के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम

कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में शहरों के साथ गांव भी प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने महामारी के फैलाव को रोकने के व्यापक प्रयास करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर संवेदनशीलता का परिचय दिया। लोगों ने भी अनुशासन निभाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इन समन्वित प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। सुखद बात यह रही है कि लोग भी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए। लोगों ने गांव, ढाणी, मोहल्ला व नगर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। इन सभी से राज्य में उत्कृष्ट कोरोना प्रबन्धन से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ''मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी'' अभियान की शुरुआत की। कोरोना को हराने के लिए इस अभियान ने जन आन्दोलन का स्वरूप लिया। एकजुट होकर प्रदेशवासियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसके फलस्वरूप हम और आप कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर पाए। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत आज के इस विकट दौर में बचाव ही उपचार है, की भावना को अपनाना अपरिहार्य है। महामारी से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों एवं कोविड प्रोटोकॉल की पालना को ही परोपकार समझना आज की महत्ती आवश्यकता है।

''राजस्थान सुजस'' मई, 2021 अंक में नवाचार करते हुए पत्रकारिता एवं जनसंचार की विभिन्न विधाओं को शामिल कर प्रकाशित किया गया। प्रबुद्धजन एवं वरिष्ठ पत्रकारगण ने इन नये प्रयासों को सराहा एवं सुजस के लिए इसे नई दिशा बताया। लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। पाठक प्रतिक्रियाएं ही सुजस के लिए उत्साहवर्धक एवं नवीन प्रयासों के लिए प्रेरणास्पद हैं। इसके लिए सभी सुधी पाठकों का सुजस की पूरी टीम की तरफ से आभार। पाठकों की प्रतिक्रियाएं हमें आगे भी मिलती रहेंगी, ऐसा हमें विश्वास है।

सुजस का यह अंक वन एवं पर्यावरण पर आधारित है। ''मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी'' पर आवरण कथा है। वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित नवीन योजनाओं और अन्य ज्ञानपरक जानकारियों को इस अंक में समावेशित किया गया है। साथ ही लोक रंग, खेल खिलाड़ी, लोक जीवन, धरोहर जैसे स्थाई स्तम्भ में भी रोचक जानकारी दी गई है। इस बार के अंक में पाठकों के अनुरोध पर अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपरक आलेखों का प्रकाशन किया गया है। नई सोच व नये संकल्प के साथ हम राज्य सरकार के इस मुख पत्र **राजस्थान सुजस** को प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों तक भी पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। यह हमारी नई शुरुआत है। आशा है, हमारा यह प्रयास विद्यालय शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ नई पीढ़ी के लिए सार्थक साबित होगा।

सादर अभिवादन के साथ,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी

अभियान बना जन आंदोलन

– संजय सैनी
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए 'मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी' अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की गई। इसके तहत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उप सभापति, सभापति, डिप्टी मेयर, मेयर, विधायक तथा संसद सदस्यों का आह्वान किया गया।

दुनिया के लिए कोरोना बड़ा घातक रहा। 2019 में चीन के वुहान सिटी से शुरू हुई इस बीमारी ने धीरे-धीरे दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही दिनों में यह महामारी में बदल गई। महामारी इस कदर फैल गई कि मानव जाति पर घातक संकट छा गया। इस महामारी की पहली लहर में बड़े शहरों में हालात काफी बिगड़ गए। शुरुआती दौर में तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आया। कोरोना की दूसरी लहर के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में घातक प्रभाव देखने को मिले रहे हैं।

राजस्थान की बात करें तो यहां मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया। अप्रेल-मई में शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ने लगे। गांवों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी।

'मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी' अभियान शुरू किया

इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए 'मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी' अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की। इसके तहत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद् सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उप सभापति, सभापति, डिप्टी मेयर, मेयर, विधायक और संसद सदस्यों का आह्वान किया। मुख्यमंत्री का आह्वान है कि सभी जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा के संकल्प निभाएं। वे गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला निगरानी समितियां बनाएं, घर-घर सर्वे कराएं, सारे आयोजन मेल-मिलाप बंद रखें, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाएं, हल्की खांसी, जुकाम, बुखार पर मरीज को आइसोलेशन में रखें, चिकित्सक को दिखाएं,

स्वयं भी जागरूक हों, परिवार और समाज को भी जागरूक करें, कोविड से बचाव के लिए बनाये गये प्रोटोकाल की पालना करवाएं और लक्ष्मण रेखा खींचकर सुरक्षा चक्र बनाएं। इस प्रकार राजस्थान में सभी के सहयोग से कोरोना को मात देने के लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता फैलाने का कार्य पूर्ण तत्परता के साथ किया जा रहा है। जल्द ही इसका असर गांवों में देखने को मिला।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विलेज कमेटी ''मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारी'' अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने को कहा। साथ ही विलेज कमेटी द्वारा जिन कोविड संक्रमित रोगियों के घर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं हैं उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर से कराई जाए। तीसरी लहर की तैयारी अभी से करें। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार इस प्रकार करें कि आमजन को इलाज के लिए जिला स्तर पर नहीं आना पड़े। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ऑक्सीजन बेड, सिलेण्डर, कंसन्ट्रेटर एवं कोविड इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

चिकित्सा विभाग ने बरती सतर्कता

चिकित्सा मंत्री ने डोर-टू-डोर सर्वे को गुणवत्तापूर्ण एवं वास्तविक करने पर भी जोर दिया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कार्य योजना बनाकर उसे समय पर मूर्त रूप देने के निर्देश दिये। कोरोना रोगियों के उपचार में संसाधनों की कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी विभाग अपने दायित्वों को जिम्मेदारी से पूरा करें। उन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी लेते हुए चिकित्सा विभाग को विशेष ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में आईएलआई सर्वे के दौरान रैपिड टेस्ट के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ब्लॉकवार मोबाइल वैन की व्यवस्था की जाए। चिकित्सकों की टीम तैनात कर गंभीर लक्षणों वाले रोगियों को समय पर अस्पताल में भर्ती कर नजदीकी सम्पर्क वाले लोगों को आइसोलेट करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के के लिए प्रभावित व्यक्ति को चिह्नित कर समय पर उपचार किया जाए तथा टेस्ट बढ़ाकर विलेज हेल्थ कमेटी को सक्रिय कर लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करें।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की अभी से तैयारी शुरू करें। कोरोना की दूसरी लहर में जो हमें चुनौतियां मिली हैं, उससे सीखते हुए हमें आगे की तैयारियां सकारात्मक सोच से करनी है। सरकारी अस्पतालों में बेड एवं ऑक्सीजन दोनों की क्षमता बढ़ाकर इस प्रकार कार्य करें कि तीसरी लहर की चुनौती का हम मुकाबला कर सकें।

कोटपूतली से शुरू हुआ अभियान प्रदेश में मॉडल बना

कोरोना की प्रथम लहर में राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की काफी प्रशंसा हुई थी। वैसे ही जयपुर के कोटपूतली से 'मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारी' काफी हद तक कारगर सिद्ध हुआ। कोटपूतली पुलिस व प्रशासन की ओर से मुहिम छेड़ी गई। मुहिम के तहत पुलिस और प्रशासन की ओर से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को जागृत करने का कार्य किया गया। ग्रामीण परिवेश के लोगों को इस मुहिम से जोड़कर कोरोना को मात देने का प्रयास किया गया। अमूमन जब पुलिस का नाम आता है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन कोटपूतली पुलिस की ओर से इस मॉडल को लेकर किए जा रहे कार्य की जितनी तारीफ की जाए वह कम है।

कारगर साबित हुआ अभियान

मॉडल के अनुसार पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने गांव के प्रत्येक घर के मुखिया और आमजन को इस बात के लिए प्रेरित किया कि राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बेवजह बाहर निकलने से रोका जाए। किसी भी व्यक्ति में संक्रमित होने का अंदेशा हो तो उसे गांव में ही निगरानी में रखा जाए। इस मॉडल गांव में होने वाले कोरोना विस्फोट को रोकने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल की। इसमें ग्रामीणों का पूर्ण रूप से सहयोग भी मिला। साथ ही साथ गांव में होने वाले विवाह सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को समझाइश के माध्यम से रोकने का काम भी किया गया। इसके चलते गांव-गांव जाकर मुखिया, सरपंच, उपसरपंच व वार्ड पंचों और अन्य बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर सभी को जिम्मेदारियां बांटकर इस मॉडल की शुरुआत की, जो काफी हद तक कारगर साबित हुई। यह मॉडल राजस्थान में विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मॉडल के जरिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद को और गांव को सुरक्षित रखने के लिए सभी को जागरूक कर रहा है।

ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग

राज्य सरकार ने पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करते हुए देशभर में उदाहरण पेश किया है। तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग की जा रही है। किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा की। प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर का सामना करने की प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये हैं। देश में कोरोना के विभिन्न वैरिएंट्स होने तथा तीसरी लहर और अधिक घातक होने की बातें सामने आ रही हैं। इसे लेकर देश-दुनिया में हो रहे शोध और अध्ययन को ध्यान में रखते हुए रणनीति भी तैयार की जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का एक

रिसर्च ग्रुप बनाकर निरंतर ऐसे शोध और अनुसंधानों का अध्ययन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी कोरोना वैरिएंट्स को लेकर भी शोध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में देश-दुनिया में सेवाएं दे रहे राज्य के प्रवासी चिकित्सकों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की आगामी आशंकाओं के मद्देनजर ऐसे स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं, जिनके आधार पर भविष्य में लॉकडाउन लगाने, अनलॉक करने, बेड की संख्या बढ़ाने और मानव संसाधन सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता और टाइमलाइन का निर्धारण करने में आसानी हो। राज्य स्तर पर कोविड प्रबंधन की योजना तैयार करने के साथ-साथ जिला स्तर पर भी 'माइक्रो प्लानिंग' की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलोपैथी के साथ-साथ लोगों का आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी विश्वास है। इनका भी समुचित उपयोग करने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सभी जिलों में टेस्टिंग और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया है। चिकित्सा विभाग तीसरी लहर को ध्यान में रखकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ कर रहा है। प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार लॉकडाउन के बाद सभी जिलों में संक्रमण की स्थिति की जानकारी लगातार ले रहे हैं। पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से कमी आई है। कुछ जिलों में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है। केवल 7 जिलों में ही पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से ऊपर है। जो निरन्तर घट रही है। प्रदेशभर में अब आईसीयू एवं वेंटिलेटर बेड आसानी से उपलब्ध हैं।

पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य ढांचे को कर रहे हैं मजबूत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मुकाबले और तीसरी लहर की भयावह आशंका के चलते राज्य सरकार पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के संकल्प को मूर्त रूप देने में भामाशाहों और उद्योगपतियों का सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश के पांच जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर में ऑक्सीजन प्लांट्स और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को

सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएचसी और सीएचसी स्तर तक आवश्यक मेडिकल उपकरणों और सुविधाओं के विस्तार में मिल रहे सहयोग से मानवता की सेवा की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी कोविड महामारी के खिलाफ पिछले डेढ़ साल से हर स्तर पर जंग लड़ी जा रही है, जिसमें समाज के सभी वर्ग भागीदार हैं। राज्य सरकार संक्रमण के प्रसार को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसमें स्थानीय भामाशाहों, उद्यमियों तथा आम नागरिकों का भी साथ मिला है।

कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया में लोगों की मानसिकता को बदल दिया है। इस दौर में मानवता ही हम सभी का धर्म है। एक-दूसरे से सहयोग और पीड़ित मानवता की सेवा की भावना से ही इस जंग को जीता जा सकेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकारें मिलकर इस लड़ाई से बेहतर मुकाबला कर सकती हैं।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए लगभग 400 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिह्नित कर उनमें स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन चिकित्सा केन्द्रों में आईसीयू एवं ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन प्लांट तथा पाइपलाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था आदि सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत बच्चों में संक्रमण को रोकने और उनके इलाज के लिए भी आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा कि खांसी एवं जुकाम के लक्षण वाले रोगियों के घर-घर व्यापक सर्वे ने महामारी की दूसरी घातक लहर से प्रदेशवासियों को बचाने में कारगर भूमिका निभाई है। इसके जरिए गांव-ढाणी तक बसे लाखों परिवारों को दवा किट पहुंचाए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित किया गया । अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दूसरी लहर में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए लगातार सख्त निर्णय किए। लोगों ने भी आगे बढ़कर कोविड अनुशासन को अपनाया, जिससे संक्रमण की चेन तोड़ने में हम कामयाब हुए हैं।

विधायक श्री अमीन खान, श्री मेवाराम जैन, श्री मदन प्रजापत एवं श्री रूपाराम ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान कोविड के खिलाफ लड़ाई में हर पायदान पर आगे है।

भामाशाहों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को चिकित्सा सुविधाएं, आवश्यक मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने तथा भोजन व्यवस्था आदि में यथासंभव सहयोग किया है। स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के कारण बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के अस्पताल ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के आह्वान पर राजस्थान का हर वर्ग एवं तबका सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में उनका समूह राज्य सरकार को हर आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जयपुर सिटीजन फोरम (जेसीएफ) के चेयरमैन श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए तुर्की से एयर लिफ्ट कर ऑक्सीजन प्लांट जयपुरिया अस्पताल में स्थापित किया गया है। जेसीएफ संगठन द्वारा रक्तदान तथा अंगदान को बढ़ावा देने के प्रयास किये गए।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी के सीईओ श्री प्रशांत जैन ने कहा कि जीवन बचाने के लिए लड़ी जा रही इस जंग में जेएसडब्ल्यू समूह कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार को पूरा सहयोग उपलब्ध करेगा।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी श्री के. श्रीकांत ने बताया कि पावर ग्रिड के द्वारा जैसलमेर के जिला अस्पताल में 850 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड राजस्थान में उत्पादित सौर ऊर्जा को अपनी ट्रांसमिशन प्रणाली के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच रहा है।

शासन सचिव चिकित्सा श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया तथा सिक्योर मीटर्स के श्री सुकेत सिंघल ने भी सम्बोधन दिया। मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी, विभिन्न विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री कुंजीलाल मीणा, स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा सहित संबंधित जिलों के कलक्टर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, सीएमएचओ एवं पीएमओ आदि अधिकारी भी वीसी से जुड़े।

लोकार्पण

1. वेदांता फील्ड हॉस्पिटल (अस्थाई), सी. सै. विद्यालय, बाड़मेर (100 बेड) (वेदांता समूह द्वारा)
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देताणी, गडरा रोड (30 बेड) (चिकित्सा विभाग द्वारा)
3. जिला अस्पताल, जैसलमेर में 850 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा)
4. राजकीय आरडीबीपी जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में 200 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट (जेसीएफ द्वारा)
5. एसएसबी सेटेलाइट हॉस्पिटल, अम्बामाता, उदयपुर में 36 सिलेण्डर प्रतिदिन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट (सिक्योर मीटर्स के सहयोग से)

6. श्री केके सेटेलाइट हॉस्पिटल, हिरणमगरी, उदयपुर में 36 सिलेण्डर प्रतिदिन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट (सिक्योर मीटर्स के सहयोग से)
7. एमजी हॉस्पिटल कैम्पस, भीलवाड़ा में 36 सिलेण्डर प्रतिदिन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट (सिक्योर मीटर्स के सहयोग से)

शिलान्यास

1. आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और वार्ड राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा)
2. ऑक्सीजन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा)
3. ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (नगर विकास न्यास द्वारा)
4. ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (राजस्थान रिफाइनरी द्वारा)
5. दो ऑक्सीजन प्लांट्स राजकीय नाहटा अस्पताल, बालोतरा (नगर परिषद द्वारा)

विशेष विमान भेजकर मंगवाई वाइल्स

प्रदेश में ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष विमान भेजकर इंजेक्शन वाइल्स मंगवाई। दो विशेष विमानों से एक हजार और 1 हजार 350 वाइल्स प्राप्त हो चुकी हैं।

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि 11 मई से भारत सरकार द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन लिपोसोमोल एंफोटेरिसिन-8, 50 एमजी का आवंटन किया जा रहा है। प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने के लिए लगातार चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने 4 जून को पहली बार एक साथ 13 हजार 350 मात्रा राजस्थान राज्य को आवंटित कर दी गई।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि दवा मंगाने के लिए तीनों स्तरों पर कार्य किया गया है। राज्य सरकार ने एक विशेष विमान दिल्ली से भेजा जो मुम्बई से 1000 वाइल के बॉक्स लेकर जयपुर पहुंचा। इसके अलावा एक अलग विमान से 1350 वाइल भी प्राप्त हो चुकी हैं। शेष 9000 वाइल्स विशेष कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में पहुंची। इस तरह प्रदेश को 14 हजार 350 वाइल प्राप्त हुई।

आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक श्री आलोक रंजन ने स्टेट हैंगर पर वाइल्स प्राप्त की। आरएमएससीएल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 10 हजार लिपिड एंफोटेरिसिन इंजेक्शन के क्रय आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। पोसाकोनाजोल टेबलेट जिसका उपयोग स्टेप डाउन थेरेपी और अल्टरनेट चिकित्सा में होगा उसके लिए 5 हजार टेबलेट पहले ही एसएमएस चिकित्सालय जयपुर एवं संभागीय मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवा दी गई हैं।

श्री रंजन ने बताया कि इसके अलावा 10 हजार पोसाकोनाजोल टेबलेट एवं 10 हजार इंजेक्शन के भी क्रयादेश जारी किए गए हैं। राजस्थान को कुल 29 हजार 350 पोसाकोनाजोल टेबलेट आवंटित हुई हैं जिनमें से 12 हजार 802 प्राप्त हो गई हैं। आरएमएससीएल द्वारा कुल 59 हजार 750 मात्रा के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

घरेलू नल कनेक्शन में महिला मुखिया को मिलेगी वरीयता

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किये जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने को वरीयता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। शेष सदस्यों में 25 प्रतिशत पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं 25 प्रतिशत गांव के कमजोर वर्ग (एसटी-एससी) के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन के प्रबंधन में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा और वे सशक्त बनेंगी।

उल्लेखनीय है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत होती है, वहां महिलाओं एवं किशोरियों को दैनिक उपभोग का पानी लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन मिलने से ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरियों को इन कठिनाइयों से निजात मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने में वरीयता देने का फैसला लेने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन का नेतृत्व प्रदान करना और ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षाएं निरस्त

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने तथा तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि इस महामारी से समाज के अन्य वर्गों के साथ-साथ विद्यार्थी वर्ग भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। चिकित्सा विशेषज्ञ संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए बनेगा पैकेज

पहली लहर के समय जिन 33 लाख असहाय, निराश्रित एवं श्रमिक परिवारों को 3 हजार 500 रुपए प्रति परिवार की सहायता प्रदान की गई थी। उन्हें संबल देने के लिए इस वर्ष की एक हजार रुपए की दूसरी किस्त इसी जून माह में जारी कर दी जाएगी। इन परिवारों को एक हजार रुपए इस वर्ष की पहली किस्त अप्रेल माह में ही दी जा चुकी है।

बैठक में मंत्रिपरिषद ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन डोज की वेस्टेज का प्रतिशत 2.08 है, जो कि वैक्सीन वेस्टेज की राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा वैक्सीन खराबी की अनुमत सीमा 10 प्रतिशत से काफी कम है। वैक्सीनेशन के साथ-साथ कोरोना के खिलाफ जंग के सभी मानकों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।

बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, वैक्सीनेशन, ब्लैक फंगस को रोकने के उपायों एवं तीसरी लहर की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन तथा जन अनुशासन लॉकडाउन की प्रभावी पालना के कारण बीते करीब 20 दिनों में एक्टिव रोगियों की संख्या में तेजी से कमी लाने में मदद मिली है।

संक्रमण की दूसरी लहर के पीक पर राज्य में एक्टिव रोगियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई थी, जो अब घटकर 37 हजार के स्तर पर आ गई है। रिकवरी रेट भी 95 प्रतिशत से अधिक हो गई है। ऑक्सीजन की खपत 400 मीट्रिक टन प्रतिदिन से घटकर 222 मीट्रिक टन प्रतिदिन के करीब हो गई है। म्यूकोर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के उपचार के लिए 37 निजी एवं राजकीय अस्पतालों को अधिकृत किया गया है।

बैठक में बताया गया कि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। जिसके तहत पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं का प्रबंधन किया जा रहा है।

विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कोविड की चुनौती के बावजूद विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं। घोषणाओं को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता से जो भी वादे किए गए हैं, उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के लिए सरकार समर्पण भाव के साथ जुटी हुई है। पूरा प्रयास है कि आमजन की तकलीफें दूर हों और राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छुए।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले में विभिन्न 20 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण तथा 113 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 15 कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें विकास की धुरी हैं, इसलिए राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेशभर में सड़कों के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहे। हमारा यह भी प्रयास है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। राजस्थान में विगत वर्षों में सड़कों का तेजी से विकास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का दायरा बढ़ा है, इसका लाभ यहां की जनता को मिल रहा है। राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष जोर दे रही है। कोविड के इस चुनौतीपूर्ण दौर में जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।

राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना संक्रमण में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासी कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना करें। मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। अन्यथा प्रदेश में अब तक के प्रयास बेकार हो जाएंगे। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं रहती है कि जनता को लॉकडाउन की तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन जीवन रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भविष्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। थानों में उचित माहौल में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्षों का निर्माण, अनिवार्य एफआईआर

रजिस्ट्रेशन जैसे फैसलों से आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसका शिलान्यास हो गया है और दिसम्बर, 2022 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बनने से कृषि विभाग के अधिकतर काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि आधुनिक रोडवेज बस स्टैण्ड का शिलान्यास होने से जोधपुरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

कृषि राज्यमंत्री श्री भजनलाल जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी राजस्थान में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। एम्स, आईआईटी, पुलिस एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रिफाइनरी जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदली है।

विधायक श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री पुखराज गर्ग, श्रीमती मनीषा पंवार एवं श्री महेन्द्र विश्नोई ने जोधपुर में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से जोधपुर की तस्वीर बदल गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, निरोगी राजस्थान, इंदिरा रसोई जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य के पुलिस थानों में बनाए जा रहे स्वागत कक्षों, एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की नीति सहित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की देशभर में सराहना की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर संसाधनों में बढ़ोतरी कर रही है। फरियादियों की सुगम एवं सहज सुनवाई के लिए थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने नागौरी गेट पुलिस थाने के नवनिर्मित भवन तथा महामंदिर, उदयमंदिर और मंडोर पुलिस थाने में स्वागत कक्ष और पर्यटक पुलिस थाने के संबंध में जानकारी दी। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि जोधपुर की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पावटा मंडी क्षेत्र में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण प्रस्तावित है। इसका भवन तीन मंजिला होगा। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी।

प्रमुख सचिव गृह श्री अभय कुमार ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विजन और गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि कोविड जैसी विषम परिस्थितियों एवं राजस्व अर्जन में बड़ी कमी के बावजूद प्रदेश में विकास कार्यों को निरंतर गति देने के साथ ही कई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी मूर्तरूप दिया जा रहा है।

प्रमुख सचिव कृषि श्री भास्कर ए सावंत ने मंडोर मंडी में प्रस्तावित किसान कॉम्प्लेक्स तथा प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री राजेश यादव ने करीब 56 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली 13 सड़कों के संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना (MKBKY)

कोविड-19 महामारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को 'मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' के तहत तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक ढ़ाई हजार रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी। अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक की पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुई कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को 'अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना' का लाभ मिलेगा। कोविड महामारी से प्रभावित निराश्रित युवाओं को 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी। इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए दो हजार रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सरकार सतर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक रही और इसके कारण लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राज्य सरकार इसे लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों तथा उनके परिजनों को उचित उपचार और मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून से केन्द्र सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण शुरू होगा। प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए प्रभावी योजना तैयार कर इसे अभियान का रूप दें, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में राजस्थान ने अब तक उत्कृष्ट प्रबंधन किया है।

कोरोना अनुशासन की पालना में कोताही नहीं बरते

मुख्यमंत्री ने लोगों को कोरोना अनुशासन की पालना में कोताही नहीं बरतने की अपील करते हुए कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए निरन्तर मास्क पहनने, उचित दूरी रखने सहित सभी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करना अतिआवश्यक है। जनता का अनुशासन ही आने वाले दिनों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की पालना में हमारी लापरवाही जीवन रक्षा और आजीविका दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

एसएमएस अस्पताल में जीन सिक्वेंसिंग लैब की स्थापना

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेहतरीन प्रबंधन किया है और अब तीसरी लहर को ध्यान में रखकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में जीन सिक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जा रही है। इससे वायरस के म्यूटेंट का जल्द पता चल सकेगा और ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल तैयार करने में आसानी होगी। मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर में परामर्श के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। सभी जिला चिकित्सालयों में भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श की व्यवस्था की गई है।

कोविड प्रबंधन को देशभर में मिली सराहना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना का बेहतरीन ढंग से मुकाबला किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और कोविड प्रबंधन को देशभर में सराहा गया है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए घोषित किया गया पैकेज सरकार का संवेदनशील कदम है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे परिवारों को शीघ्र चिह्नित करें, जिनमें कोविड के कारण बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है।

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, वैक्सीनेशन, संसाधनों की उपलब्धता एवं भविष्य की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि विगत दिनों में प्रदेश में संक्रमण के स्तर, एक्टिव केसेज एवं मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। प्रदेश में 12 मई को कोविड से 164 मौतें हुई थीं, जो 12 जून को घटकर 16 रह गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में देशभर में अव्वल रहा है। हमारे यहां वैक्सीन का वेस्टेज केवल 1.3 प्रतिशत रहा।

ऑक्सीजन के क्षेत्र में राजस्थान को बनाएंगे आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर योजनाबद्ध

रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के जिस संकट का सामना पूरे देश-प्रदेश ने किया, उसे देखते हुए राज्य के जिला अस्पतालों से लेकर सीएचसी एवं पीएचसी स्तर तक के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने, पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने के साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे आने वाले वक्त में यदि तीसरी लहर आती भी है, तो प्रदेश के राजकीय अस्पताल उससे मुकाबले के लिए पहले ही तैयार हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने 14 जून को जोधपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे करीब 39 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 33 करोड़ रुपए की लागत के 13 कार्यों का लोकार्पण एवं 6 करोड़ रुपए की लागत के दो कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण की पहली लहर तथा इसके बाद की घातक दूसरी लहर के समय राजस्थान ने जिस प्रकार का कोरोना प्रबंधन किया उसकी सराहना पूरे देश में हुई है। चाहे वह सघन कांटेक्ट ट्रेसिंग का भीलवाडा मॉडल हो या सामाजिक जागरूकता के लिए नो मास्क-नो एंट्री अभियान। कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने के लिए सूखे राशन तथा भोजन सामग्री के पैकेट वितरण का कार्य हो या गांव-ढाणी तक बसे 16 लाख परिवारों तक दवा किट पहुंचाने का सफल अभियान, हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी।

श्री गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलें। अब सिर्फ जालोर, राजसमंद तथा प्रतापगढ़ ही ऐसे जिले हैं, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। हमारी कोशिश रहेगी कि इन जिलों में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर हों।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 400 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की योजना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है।

इसके साथ ही नवजात गहन चिकित्सा इकाई (नीकू), शिशु गहन चिकित्सा इकाई (पीकू), कमजोर एवं कुपोषित नवजातों के उपचार के लिए स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमारी तैयारियां पूरी रहें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जब-जब भी प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब-तब प्रदेश के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।•

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

राज्य सरकार द्वारा
कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को
2000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

विधवा महिलाओं के लिए

कोविड-19 से पति की मृत्यु होने से विधवा हुई महिलाओं को इस प्रकार आर्थिक सहायता दी जाएगी —

- **1 लाख रुपये** एकमुश्त राशि
- **1,500 रुपये प्रति माह** विधवा पेंशन
- विधवा महिलाओं के बच्चों को **1,000 रुपये प्रति बच्चा, प्रति माह** और विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2,000 रुपये

अनाथ बच्चों के लिए

कोरोना महामारी से माता-पिता दोनों की या एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को **'मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना'** में केन्द्र सरकार की योजना के अलावा लाभ —

- अनाथ बालक/बालिका को तत्काल **1 लाख रुपये**
- 18 वर्ष की आयु तक **प्रति माह 2,500 रुपये**
- 18 वर्ष पूरे होने पर **5 लाख रुपये**
- 12वीं तक आवासीय विद्यालय या छात्रावास से निःशुल्क शिक्षा
- कॉलेज छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश
- कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधाओं के लिए 'अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना' का लाभ
- युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्राथमिकता से बेरोज़गारी भत्ता

इनके लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है

कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा ज़रूरतमंदों को दी गई अन्य सहायता...

33 लाख से ज़्यादा
ज़रूरतमंद परिवारों को पांच किश्तों में कुल रु. 5,500 की सहायता राशि सीधा बैंक खातों में

खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं वितरण, राज्य सरकार द्वारा लगभग **325 करोड़ रुपये** का अतिरिक्त भार वहन

खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर विशेष श्रेणी के लगभग **67 लाख** लोगों को निःशुल्क गेहूँ व चना वितरण

शताब्दी के सबसे कठिन समय में राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है

आइये मिलकर कोरोना को हराएं, इसे फिर लौट कर न आने दें
घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें
औरों से 2 गज की दूरी रखें
साबुन से हाथ धोते रहें या सैनेटाइज़ करें

कोरोना या सरकारी सेवाओं से जुड़ी किसी समस्या के लिए 181 पर फ़ोन करें

बेहतरीन प्रबंधन से

राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू

– राजीव जैन
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान सरकार के बेहतरीन प्रबंधन के चलते कोरोना की दूसरी लहर को काबू कर लिया गया है। राज्य में संक्रमण की दर अब घट गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की निगरानी में जिस तरह से कोरोना की पहली लहर का सामना किया गया, उसी तरह से दूसरी लहर का समय रहते उनका बेहतरीन प्रबंधन देखने को मिला। इसी का नतीजा है कि संक्रमण दर घटी और संक्रमितों को बेहतर इलाज की सुविधा भी मिली।

मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों से लगातार रायशुमारी कर संक्रमण दर घटाने के उपाय किये। इसमें जनअनुशासन पखवाड़े से लेकर कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे सख्त कदम भी उठाये गये। आम जनता ने भी राज्य सरकार के फैसलों पर पूरी तरह से अमल कर कोरोना संक्रमण दर घटाने में आगे आकर मदद की। इसके चलते ही प्रदेश में संक्रमण दर अब काबू में आई है और अस्पतालों में रोगियों का दबाव भी कम हुआ है।

सभी वर्गों से लगातार रायशुमारी

प्रदेश में अप्रेल के मध्य में कोरोना का फैलाव जिस तेजी से हुआ उससे प्रदेश की जनता सहम गई। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की किल्लत शुरू हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की बागडोर संभालते हुए संक्रमितों को राहत देने के कदम उठाये। सरकार ने प्रदेश भर में जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, उससे कोरोना संक्रमितों को उपचार के दौरान ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कोविड डेडिकेटेड बेड्स के साथ ही, बड़ी संख्या में कोविड केयर सेंटर स्थापित किये।

दूसरी लहर अधिक घातक

कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा घातक साबित हुई। इसमें संक्रमितों में ऑक्सीजन लेवल घटने और फेफड़ों में नुकसान की सर्वाधिक समस्या सामने आई। इससे ही ऑक्सीजन की कमी की परेशानी उठी। सरकार ने ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये और समय रहते इसकी कमी को दूर किया। मुख्यमंत्री गहलोत का पूरा फोकस आम आदमी को राहत देने का रहा। इसके लिए उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी दरों पर अंकुश लगाने के कठोर कदम उठाये। सभी तरह के उपचार और जांचों की दरें निर्धारित की। इससे भी संक्रमितों के परिजनों को राहत मिली। सरकार ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए कई स्तर पर हेल्प लाइन शुरु कर सभी जगह निगरानी की व्यवस्था की। इसका नतीजा रहा कि लोगों को इलाज में कहीं परेशानी महसूस नहीं हुई। सरकार ने जरुरी दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर भी नकेल कसी और उनकी समय रहते ही धरपकड़ भी की।

देश भर में राज्य की सराहना

देश भर में कोरोना प्रबंधन में राजस्थान के कामकाज को खासी सराहना मिली है। कोरोना की पहली लहर में भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल की देश भर में तारीफ हुई और दूसरे प्रदेशों ने इस मॉडल को अपनाया। पहली लहर में जहां एक दिन में कोरोना के 3200 मामले सामने आये थे वहीं दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक रही और एक दिन में 18 हजार से भी ज्यादा केस सामने आये। सरकार ने पिछले डेढ़ साल में चिकित्सा संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम भी उठाये। इस दौरान करीब 3500 डॉक्टर, 12500 एएनएम, जीएनएम व 7800 से ज्यादा सीएचओ, रेडियोग्राफर्स और लैब टैक्नीशियंस की भर्ती की गई। प्रदेश में करीब 6 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अगुआई में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्थाओं के संचालन में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भी हर स्तर पर निगरानी रख कहीं भी ढील नहीं होने दी। तीसरी लहर के लिए तैयारी विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना भी जताई है। इसको लेकर भी सरकार ने अभी से पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा लिये गये हैं। प्रदेश के 350 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें सभी जरूरी उपचार सुविधाओं को अभी से बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिये हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल व्यवहार अपनाने के साथ ही टीकाकरण में तेजी लाना बेहद जरूरी कदम है। मास्क की अनिवार्यता को मुख्यमंत्री सर्वोपरि मानते है। इसके उल्लंघन पर उन्होंने जुर्माना राशि बढ़ा दी है। टीकाकरण को तेज गति देने में राजस्थान देश भर में अव्वल चल रहा है। मुफ्त टीकाकरण की घोषणा भी राजस्थान ने कर रखी है। टीकों की उपलब्धता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना प्रबंधन में सरकार ने असहाय, निराश्रित और श्रमिक परिवारों का पूरा ध्यान रखा। पहली लहर में ऐसे करीब 33 लाख परिवारों को 35 हजार रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इन्हें संबल देने के लिए इस वर्ष भी जून में एक हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया। •

अभी से करें तीसरी लहर की तैयारी

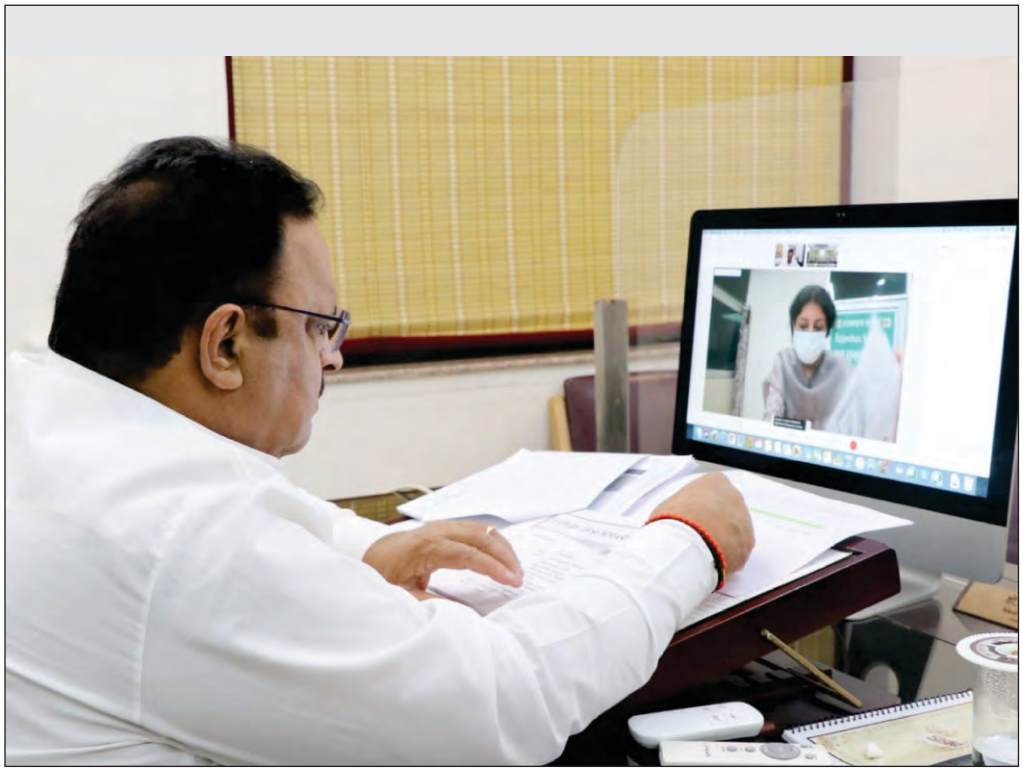

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने 22 मई को टोंक के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में वीसी के माध्यम से टोंक जिले में कोविड संक्रमण रोकथाम के प्रबन्धों की माइक्रो प्लानिंग कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारी अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। कोविड संक्रमित रोगियों के घर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं होने पर उनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था विलेज कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से करवाई जाए। तीसरी लहर की तैयारी अभी से करें। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार इस प्रकार करें कि आमजन को इलाज के लिए जिला स्तर पर नहीं आना पड़े। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ऑक्सीजन बेड, सिलेण्डर, कंसन्ट्रेटर एवं कोविड इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

गांवों मे ही मिले सुविधा

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि गांवों में प्रशासन, चिकित्सा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा इस तरह का वातावरण तैयार किया जाए कि ग्रामीण खुलकर अपने आईएलआई (खांसी, जुकाम, बुखार) लक्षणों को डोर-टू-डोर सर्वे टीमों को बताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे को समय पर पूरा कर कोविड़ लक्षणों वाले रोगियों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाओं, संसाधनों की कालाबाजारी नहीं हो तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

वैक्सीन की आएंगी लगभग 13 लाख डोज

प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 9 जून से वैक्सीन मिलना प्रारंभ हो गई। अलग-अलग खेपों में लगभग 12 लाख 70 हजार वैक्सीन प्रदेश को मिलेगी।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के लिए कुल 30 लाख 57 हजार 720 वैक्सीन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन आएगी। इनमें से 24 लाख 49 हजार 380 डोज कोविशील्ड व 6 लाख 4 हजार 340 डोज कोवैक्सीन की होगी। अब तक अलग-अलग खेपों में लगभग 17 लाख 87 हजार 720 वैक्सीन डोजेज राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं। लगभग 12 लाख 70 हजार वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त वैक्सीन के अनुसार वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

डॉ. शर्मा ने कहा कि केंद्र ने अब तक 1 करोड़ 83 लाख 67 हजार 940 वैक्सीन राज्य सरकार को दी हैं। इनमें से 2 लाख 15 हजार वैक्सीन हमने आर्मी और लगभग 1 करोड़ 79 लाख वैक्सीन जिलों में वितरित कर दी गईं। उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ 76 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश को केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलती रही तब तक राज्य वैक्सीनेशन में देश में नंबर 1 पर रहा। मई माह में जब वैक्सीन कम मिलने लगी तो वैक्सीनेशन कम होने लगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने एक दिन में 5 लाख 81 हजार वैक्सीन भी लगाई। हमारी क्षमता एक दिन में 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की है। •

हर घर का अभियान बनेगी "घर-घर औषधि योजना"

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घर-घर औषधि योजना की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसरण में राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु औषधीय पौधों का वितरण किया जाना है। योजना के तहत आमजन को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन पौधों को अपने घर-आंगन में लगाकर आमजन न केवल अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का रक्षण कर सकेंगे, बल्कि राजस्थान की समृद्ध औषधीय परंपरा का संरक्षण करने में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दें सकेंगे।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम बिश्नोई का पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य विकास पर दृष्टिकोण।

जनसम्पर्क अधिकारी, अनिल कुमार शाक्य द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश

घर–घर औषधि योजना क्या है ?

घर-घर औषधि योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उस दूरगामी सोच का परिणाम है, जिसके तहत आमजन को घर पर ही औषधीय पौधों से घरेलू उपचार की सुविधा मिल सकेगी। पूरे देश में अपनी तरह की यह अनूठी योजना है, जिसे राजस्थान सरकार की ओर से शुरू किया जा रहा है। इस एक योजना के क्रियान्वयन से ही कई उद्देश्य पूरे होंगे। जैसे घर-आंगन में औषधीय पौधे लगाने से आमजन का स्वास्थ्य रक्षण सुनिश्चित हो सकेगा, वहीं इन पौधों का संरक्षण भी संभव होगा। जैव विविधता संरक्षण में सहयोग मिलेगा। शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों और घरों में पौधे लगाने से प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

आमजन को पौधे कैसे मिल सकेंगे ?

राजस्थान सरकार की इस महत्त्वपूर्ण योजना के तहत आमजन को वन विभाग की पौधशाला से औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य के प्रत्येक नागरिक तक 4 औषधीय पौधों को पहुंचाया जाएगा ताकि मानव स्वास्थ्य रक्षण और व्याधिक्षमत्व को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही आमजन को चिकित्सा हेतु बहु उपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में भी बताया जाएगा ताकि राजस्थान में पाई जाने वाली वन औषधियों और औषधीय पौधों का संरक्षण हो सके।

पौधों के संरक्षण के लिए आमजन को जागरूक कैसे करेंगे ?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शुरू की जा रही इस योजना का मूल उद्देश्य यही है कि औषधीय पौधों के चिकित्सीय उपयोग के साथ-साथ इनके संरक्षण और संवर्धन के भी प्रयास किए जाएं। इसके लिए आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रमाण आधारित और ज्ञात जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सक भी आमजन को जागरूक करने में सहयोग करेंगे।

योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा ?

घर-घर औषधि योजना का क्रियान्वयन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग नोडल विभाग होगा। घर-घर औषधि योजना को जन अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा ताकि इससे राज्य का प्रत्येक परिवार और नागरिक लाभान्वित हो सके। जिला स्तर पर भी योजना के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा बनाई है। इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी। टास्क फोर्स में जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाएं, विभिन्न राजकीय विभाग, संस्थान, विद्यालय और औद्योगिक घरानों का भी सहयोग लिया जाएगा।

योजना से आमजन को क्या लाभ होगा ?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही घर-घर औषधि योजना को प्रभावी करने का निर्णय लिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि घर पर ही आमजन को औषधीय उपचार की सुविधा मिल सके। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य रक्षण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी योजना कारगर रहेगी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध रहा है। घर-घर औषधि योजना के माध्यम से इस विविधता और गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिल सकेगा।•

आम जन को जोड़ने हेतु हर स्तर पर प्रयास

तकरीबन डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद वैश्विक महामारी कोविड-19 का खतरा बरकरार है और अभी तक इस बीमारी की कोई अचूक दवा नहीं बन पाई है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि दवा के साथ-साथ कोविड-19 से लड़ने के लिए जनता की सामूहिक भागीदारी भी आवश्यक है। इसी लक्ष्य और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा और जांच योजना के साथ घर-घर औषधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती श्रेया गुहा से बातचीत

संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क, अरुण जोशी द्वारा की गई बातचीत के महत्त्वपूर्ण अंश

घर-घर औषधि योजना से आमजन को किस प्रकार जोड़ेंगे ?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही जन कल्याणकारी सरकार का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार आम जनता को सुविधाएं और राहत प्रदान की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 के बजट में घर-घर औषधि योजना शुरु करने की घोषणा की। इस योजना से आमजन को जोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स गठित की गई है। जनता की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जायेगा, जिसमें सोशल मीडिया, प्रकाशन, लेख इत्यादि का उपयोग किया जाएगा।

इस योजना में वन विभाग की भूमिका क्या रहेगी ?

घर-घर औषधि योजना को मूर्त रूप देने में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राजस्थान सरकार ने वन विभाग को घर-घर औषधि योजना के सफल क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वन विभाग को योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। वन विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार के लिए औषधीय पौधे राज्य में स्थापित विभिन्न विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्य विभाग भी इस योजना को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और वन एवं पर्यावरण मंत्री की भी मंशा है कि योजना से राजस्थान का प्रत्येक परिवार और नागरिक लाभान्वित हो सकें।

योजना की रूपरेखा क्या है ?

इस योजना का प्रारूप ऐसा रखा गया है जो सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। योजना के जरिए पर्यावरण संरक्षण होगा। औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं इनसे जुड़े परंपरागत ज्ञान को भी आमजन तक पहुंचाया जायेगा। योजना के जरिये जब हर घर में औषधीय पौधे पहुंचेंगे तो आमजन को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ से प्राप्त होने वाली औषधियां घर पर ही उपलब्ध होंगी। योजना में प्रत्येक परिवार को चार प्रकार की औषधीय प्रजातियों के दो-दो पौधे (तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ) इस वर्ष सहित पांच वर्षों में तीन बार वन विभाग की पौधशालाओं से नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना में औषधीय पौधों का प्रत्येक घर में संरक्षण होगा, इसलिए सर्वहित को ध्यान में रखकर योजना को लागू करने पर जोर है।

योजना पर भी तक कितना काम हो चुका है ?

घर-घर औषधि योजना के पहले चरण में वन विभाग की समस्त पौधशालाओं में औषधीय पौधों की चारों प्रजातियों के पौधे तैयार किये गये हैं। द्वितीय चरण में इन पौधों का वितरण राज्य के 50 प्रतिशत परिवारों को किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत पौधों का वितरण दो चरणों में यथा माह जुलाई एवं अक्टूबर में किया जाना प्रस्तावित है।

इस संबंध में लगातार ऑनलाइन बैठकें करते हुए संबंधित अधिकारियों से योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली जा रही है तथा उनकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम विश्नोई के मार्गदर्शन में विभाग का पूरा फोकस इस योजना के सफल क्रियान्वयन पर है।

प्रदेश भर में इस योजना की मॉनिटरिंग कैसे होगी ?

इस योजना की मॉनिटरिंग के लिये राज्य स्तर से लेकर संभाग और जिलास्तरीय टास्क फोर्स द्वारा योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग के अधिकारियों को अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है ताकि समय रहते योजना से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां और आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। वर्तमान में सभी जगहों पर योजना से जुड़ी हुई गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। वन विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के तालमेल से घर-घर औषधि योजना को प्रदेश भर में मॉडल योजना के रूप में लागू करने का प्रयास किया जाएगा, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके।•

Rajasthan : Facing Successfully Challenges of Environmental Degradation

- Sanjeev Srivastava
Former India Editor of BBC World Service & Sr. Journalist

As we remind ourselves of the challenges posed by global warming and environmental degradation, we would do well to go back two decades and see how Rajasthan turned a recurring adversity into a sustainable, meaningful and socially relevant policy intervention initiative which has since been replicated across the country.

The state of Rajasthan used to be associated with images of vast stretches of arid desert, astonishing want of water and repeated bouts of drought that wreaked havoc on lives and livelihoods. In 2000, the monsoons failed in Rajasthan for the third successive year. 60% of the State's population was affected. Over 3% of the households in the State were reduced to starvation, based on estimates put together by economists. Besides, 40% of cows in the State had perished. Roughly one person from every family migrated out for work. It was a crisis the like of which Rajasthan has not seen before as we had never seen such a direct impact of environmental imbalance on human life.

But the state was fortunate to have at that time Shri Ashok Gehlot as chief minister, a sensitive and progressive leader who was committed to the welfare of the poor, backward and downtrodden. Shri Gehlot's belief got cutting edge support and a policy framework from a thriving and committed civil society tradition in the state.

Along with the legacy of drought, the state of Rajasthan also had a legacy of civil society organizations and social movements playing the role of a moral compass in a State with shifting political priorities. The State had witnessed sustained Gandhian movements for causes such as women's rights, access to minimum wage and community ownership of resources. In 2001, Akal Sangharsh Samiti, a network of over 57 organizations from across the state organized jan manchs, jan sunvais and dharnas across the State to put public pressure on the State Government to extend the Food for Work programme so that it could serve as a minimum source of support to the families affected by drought.

This led to a long and sustained advocacy for an Employment Guarantee Act by the Soochna Evum Rozgar Adhikar Abhiyan. The demand for such a law in the State merged with a nationwide movement, and led to the passage of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in 2004 which today stands to be the largest public employment programme in the world. MGNREGA offered a unique lesson. It showed the State and the country that social security can walk hand in hand with restoring the environment and the local ecology. The

But the state was fortunate to have at that time Shri Ashok Gehlot as chief minister, a sensitive and progressive leader who was committed to the welfare of the poor, backward and downtrodden. Shri Gehlot's belief got cutting edge support and a policy framework from a thriving and committed civil society tradition in the state.

MGNREGA works are largely focused on land and water resources, which include: water harvesting and conservation, soil conservation and protection, irrigation provisioning and improvement, renovation of traditional water bodies, land development and drought proofing.

Over the past 5 years of its implementation, nearly 70% of the programme's funds have been spent on natural resource management works. 322 drought proofing works, 675 flood control works, 5000 micro-irrigation works, 2250 land development works, 12000 water conservation and harvesting works, 3000 traditional water bodies have been restored under MGNREGA in the past year alone. These works have played the dual role of providing basic income security to the poorest sections of society, particularly dalits, adivasis, women, while also contributing to protection and restoration of the local ecology by increasing ground water levels, enhancement of soil organic matter, reduction in soil erosion, pasture restoration, increasing the land area under cultivation and forest cover.

MGNREGA has contributed to building resilience to cope with current climate risks and also build long-term resilience to projected climate change. The positive impacts of MGNREGA on the environment have been studied and recorded by innumerable national and international research studies. The rights- based framework of MGNREGA that gives rural households the right to demand employment, be paid a minimum wage, decide on the works that should be undertaken under MGNREGA in their village has led to a organic movement for protecting the environment that is based on peoples' will.

Sixty percent of the total employment generated under MGNREGA in Rajasthan over the past 5 years, has been done so by women. In Rajasthan therefore, we have seen that efforts to protect the environment are not led by fancy announcements of carbon emission targets set in air conditioned halls but are driven and sustained by the hard work of women, dalit and adivasis of the State. Realising the importance of the programme in providing livelihood to poor, the Union Government was forced to enhance the financial allocation to the progamme to its highest ever, as it realized that MGNREGA was the only instrument they had to alleviate the widespread distress caused by an ill planned lockdown.

This was clearly understood by the political leadership in the State. The financial impetus led to a dramatic rise in the number of households who worked under MGNREGA by 36%, as compared to 2019, through the launch of a statewide "Kaam Maango Abhiyan" by the Chief Minister. In 2020, over 12.3 lakh households completed 100 days of work under the programme, the highest ever in the State of Rajasthan since the launch of the programme.

In a world devastated by the coronavirus, let us commit to honour our environment meaningfully. Rights based legislations like the MGNREGA offer us invaluable lessons on how democratic participation can form the essential bedrock of efforts to protect and restore the environment. •

Chiranjeevi Health Insurance Scheme:

A PASSPORT FOR FAMILY HEALTH CARE

- Prakash Bhandari
Sr. Journalist

The last 15 months because of the corona virus pandemic paralysed economies, devastated families and communities and rendered millions of people jobless. But Rajasthan under the leadership of the Chief Minister Shri Ashok Gehlot has become the first state in the country to provide health cover insurance to take initiative to combat corona.

The year 2020 would remain one of the worst year of the new millennium. As it changed the world through a dreadful corona virus for which the medical world had no vaccine when it spread globally. The world suffered immensely globally and lakhs of people lost their lives. The dreadful disease stunned the entire world. The impact of the Covid-19 was far more devastating than the Second World War.

The spread of corona virus paralysed economies, devastated families and communities and rendered millions of people jobless. But Rajasthan under the leadership of the Chief Minister Shri Ashok Gehlot has become the first state in the country to provide health cover insurance to take initiative to combat corona.

The Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Beema Yojana is a state-sponsored health scheme. This universalized health care scheme has became a novel scheme and one of its kind in the country. A unique scheme that was free for the poor and most affordable for the rest. Shri Gehlot had a dream, like Martin Luther King- the dream of ensuring that nobody in the state ends up spending their life time precious savings ending up on paying hospital bills.

The insurance cover of Rs five lakh will be free for the beneficiaries of the National Food Security Act, small and marginal farmers, contract workers, destitute families that receive ex gratia payments from the state government. For the others, the cover will come at an annual premium of only Rs 850. All beneficiaries will be entitled to cashless hospitalisation in 1,092 government hospitals and 336 private in the state. Medical expenses five days prior to hospitalisation and 15 days after discharge will also be covered. The state government has already paid Rs 50 crores as the initial premium.

Though there is Central Government run Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) also which also provides a cover of Rs. 5 Lakh, but this theme currently covers only 5.97 million families, over about 40 percent of the state population.

Rajasthan under Shri Ashok Gehlot has gone a few steps ahead of PMJAY and has extended the coverage to the general category, from the lower middle income group and beyond, thereby becoming the first state to ring in universal healthcare for its people.

The State government has added free coverage for 1.5 million families of small and marginal farmers and 300,000 contractual employees. State government employees and others covered under separate health policies will also gradually be included in the scheme.

The impact of the scheme has been tremendous and the large number of registration in crores shows that the people have responded enthusiastically for this scheme despite lockdown. Shri Gehlot has been pushing the scheme in every public function and all his online appearances.

Health care has always been the top agenda of Shri Gehlot and has always been to open various health schemes including expanding the Central government's schemes. Shri Gehlot ensured strengthening the public healthcare system and making it accessible. In his first term as chief minister (1998-2003), he introduced free treatment, including surgeries, for below poverty line families; in 2011, he introduced free medicines for all at

state healthcare centres. The budget for the free medicine was put at Rs. 972 crores which were three times more than the Centre's allotment. More than Rs. 230 crores were spent on free medical tests at all levels of care in FY21, a Covid year.

Beneficiaries need a Janadhaar card which is a verified digital instrument linked to 28 government benefits, including subsidies, scholarships and pensions) to avail of the Chiranjeevi scheme.

The Chiranjeevi Health Insurance Scheme is unique in many ways as its not for an individual, but for the entire family. Normally, the age factor is very important for health insurance and normally the insurance companies do not give insurance coverage to aged persons. But neither the age factor nor the numbers of family matters under the Chiranjeevi Yojana. Even a newborn and the aged member of the family would get equal benefits under the scheme. If a person is suffering from a disease prior to registration under the Chiranjeevi Scheme,it would not be a disadvantage. Under this scheme Rs. 40,000 coverage has been provided for identified diseases, while for the diseases of serious nature the coverage would of Rs. 4.50 lakh. Over 1576 various diseases has been included under the package.

Dr. Raghu Sharma, the minister for Medical and health said that the focus of the Chief Minister was to build a healthy state and no individual should suffer for want of healthcare. The Chiranjeevi Yojana is a revolutionary step that other states should emulate.

The Chiranjeevi Yojana is based on the willingness on the part of the government to provide health care to all. This is the reason why this scheme has proved to be unique in the country.

During UPA government under Prime Minister Dr. Manmohan Singh & Chairperson Smt. Sonia Gandhi, the process of providing social security was initiated. This era could be termed as an era of social empowerment which was a unique step to empower the country's populace with social security. Empowerment become the watchword under which the Right To Information, Right To Education, Food Security, Rural jobs under MGNREGA were introduced to benefit the people, The MGNREGA proved to be a boon during the COVID 19 as crores of people who had lost jobs were benefitted under the MGNREGA plan.

Dr. Raghu Sharma apprised that the ambitious Chiranjeevi Yojana would cost the exchequer Rs. 3500 crores and under this scheme, the beneficiaries will be treated for heart, cancer, dialysis, and Covid-19 like 1576 diseases. The beneficiaries would get the treatment facility in the state's 765 hospitals and 330 recognised private hospitals.

Prior to the launch of the Chiranjeevi scheme, the Chief Minister widened its ambit to target sections of the population not covered under PMJAY. The state decided to give health care coverage by bearing expenses of Rs 1,662 per policy and the number of beneficiaries to 11 million families. Rajasthan is due to receive only Rs 376 crore from the Centre in its budgeted spend of Rs 3,500 crore on the Chiranjeevi scheme.

The universalisation of the state-sponsored health care scheme is surely one of the big programme launched by the Rajasthan government which stands seventh in GSDP and 21st in per capita income. At Rs 16,269 crore for 2021-22, the state expenditure on public healthcare was about 7 per cent of its total budget expenditure as against the national average for states of about 5.5 per cent.

Even as the chiranjeevi scheme was being finetuned and firmed up, Shri Gehlot decided to widen its ambit to target sections of the population not covered under PMJAY (those covered under the food security Act.), which increased the premium to borne by the state to Rs 1,662 per policy and the number of beneficiaries to 11 million families. Rajasthan is due to receive Rs. 376 crore from the Centre in its budgeted spend of Rs 3,000 crore on the chiranjeevi scheme.

This healthcare scheme is particularly meaningful looking to the resources at the disposal of State Government and would a long way in the strengthening the human resource of the state.

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून

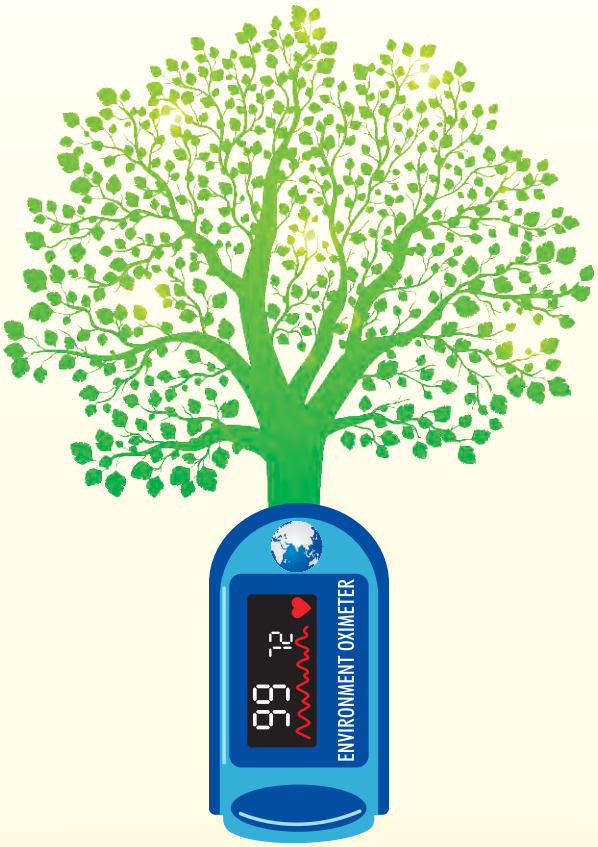

कोरोना महामारी ने समझाया हमें पर्यावरण का महत्त्व

"स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है। यह बात सदियों से हमारे पूर्वज मानते और अपनाते रहे हैं। परन्तु समय के साथ विकास की महत्त्वाकांक्षा में मानव जाति ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई। जिसका आभास हमें कोरोना महामारी के दौरान हुआ है।

हमें स्वच्छ पर्यावरण को पुनः स्थापित करना होगा। कोरोना से जंग हम तभी जीत पाएंगे,जब हम स्वच्छ पर्यावरण में प्रकृति के संग रहेंगे।"

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

पेड़-पौधे हैं ऑक्सीजन प्राण वायु के विपुल भण्डार
प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र का जीवन आधार

पर्यावरण विभाग, राजस्थान

बिन संरक्षण सब सून

– श्रुति शर्मा
आई.एफ.एस.

छाया : सविता चौहान

वन और पर्यावरण। इन दो शब्दों के सामने आते ही सबसे पहले आपके मन में क्या छवि उभरती है? इस सवाल का सीधा सा जवाब ये होगा कि बहुत सारे पेड़-पौधे, फल-फूल, जड़ी-बूटियां, हरियाली, पशु- पक्षी, नदियां, झरने आदि। कल्पना के घोड़े और दौड़ाएं तो पहाड़ों से घिरा चित्र भी सामने आ जाएगा, लेकिन कभी सोचा है कि इन सबके अलावा वन और पर्यावरण मिलाकर एक पूरी दुनिया बनाते हैं। ऐसी दुनिया जिसके बिना किसी दूसरी दुनिया की कल्पना मुमकिन नहीं।

सही मायने में वन और पर्यावरण की उपलब्धता ना हो तो जीवन का अस्तित्व मुश्किल है। किसी भी तरह का जीवन पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। दुनिया में वन धरती का तकरीबन 30 प्रतिशत हिस्सा हैं। प्रकृति की ओर से मानव जाति को उपलब्ध करवाई गई बेहद महत्त्वपूर्ण सुविधा वन एवं पर्यावरण ही है।

इसी क्रम में देखें तो जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश के पंच तत्वों से मिलकर ही मनुष्य का जीवन शुरु हुआ है। जीवन समाप्त होने पर वह इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है। इस सब के बावजूद वन और पर्यावरण संरक्षण की ओर उदासीनता निरंतर बनी हुई है। कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने और मानव जीवन की कई जरूरतों को पूरा करने के बावजूद वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरुकता नहीं है। लगातार कटते जंगल इसका उदाहरण हैं। जंगल कटने से उसमें रहने वाले पशु-पक्षी तो कम हुए ही हैं, साथ ही साथ वनों से प्राप्त होने वाली उपज भी लगातार कम हो रही है जबकि पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में लोग प्रकृति और वनों का सम्मान करते थे। इनका संरक्षण करते थे। इसलिए मानव समाज के चारों ओर हरियाली थी। पेड़-पौधे थे। घर-आंगन में पशु-पक्षी थे। स्वस्थ वातावरण था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। चारों ओर रहने वाले पेड़-पौधों के स्थान पर अब ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी हैं। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मॉल्स हैं। हरियाली लगातार सिकुड़ रही है। जंगल काटकर इमारतें और फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। वन और पर्यावरण क्षेत्र के नष्ट होने का असर मानव जीवन पर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश मनुष्य इससे अनजान बने हुए हैं।

वर्तमान में फैक्ट्रियों और सड़कों पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं से जहां एक ओर हवा प्रदूषित हो रही है, वहीं दूसरी ओर नदियों में डाले जा रहे कल-कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। घर, ऑफिस और वाहनों में लगे एयर कंडीशनर्स के बढ़ते उपयोग से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।

ये सब ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर अंकुश लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साथ ही इस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि वन और पर्यावरण से खिलवाड़ करने की बजाय किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं। जागरुकता की भावना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने अधिक पेड़-पौधे आस-पास होंगे, पर्यावरण उतना ही संरक्षित रहेगा। घर-आंगन के साथ-साथ आसपास भी पेड़-पौधे लगाये जाने आवश्यक हैं ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। घर-परिवार में भी ऐसी जागरुकता को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि बच्चे इस परंपरा को अपनाते हुए आगे बढ़ा सकें।

घर-घर औषधि योजना प्रदेश के हर घर का अभियान है

तुलसी

– डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
आई.एफ.एस.

राजस्थान के नागरिकों का स्वास्थ्य रक्षण तथा राज्य में औषधीय पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से देश में अपनी तरह की अनूठी योजना कार्यान्वित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021 में बजट घोषणा की गई है कि राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए 'घर–घर औषधि योजना' शुरु की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे। इसे आगे बढ़ाते हुये मंत्रिमंडल द्वारा घर–घर औषधि योजना के राज्यव्यापी क्रियान्वयन का निर्णय हुआ है। कुल मिलाकर अगले पांच वर्ष में राज्य के सवा करोड़ परिवारों को लगभग 30 करोड़ पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उगाकर वितरित किये जायेंगे।

राजस्थान के वनों एवं वनों के बाहर हरियाली वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की औषधीय प्रजातियों की उपलब्धता रही है, जिनका प्रयोग आदिकाल से आयुर्वेद तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षण एवं चिकित्सा के लिये होता आया है। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जीवन–शैली में परिवर्तन जैसे कारणों से स्थानीय लोग अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते रहते हैं। आयुर्वेद तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान व वनों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतों और निजी जमीनों के समीप उगाने हेतु सहायता करने से राजस्थान राज्य के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य ध्येय है। इस योजना से राजस्थान में पाई जाने वाली वनौषधियों एवं औषधीय पौधों का संरक्षण भी होगा।

योजना का उद्देश्य

घर–घर– औषधि योजना एक साथ कई उद्देश्यों को समेटे हुये है। राज्य में औषधीय पौधों को उगाने के इच्छुक परिवारों को स्वास्थ्य रक्षण हेतु बहु–उपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधाशालाओं में उपलब्ध कराये जाएंगे। लोगों के स्वास्थ्य रक्षण और व्याधिक्षमत्व बढ़ाने तथा चिकित्सा हेतु बहु–उपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये जन चेतना का विस्तार होगा। औषधीय पौधों के प्राथमिक उपयोग तथा संरक्षण–संवर्धन हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रमाण–आधारित जानकारी उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन व वन विभाग, जन–प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों, विद्यालयों, और औद्योगिक घरानों इत्यादि का सहयोग लेकर जन–अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा।

कार्यान्वयन

योजना के अंतर्गत राज्य में स्वास्थ्य रक्षण हेतु बहु–उपयोगी औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा वन विभाग की 565 पौधाशालाओं में तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य रक्षण और व्याधिक्षमत्व बढ़ाने तथा चिकित्सा हेतु बहु–उपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में जन चेतना का प्रसार और औषधीय पौधों के प्राथमिक उपयोग तथा संरक्षण–संवर्धन हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। विभिन्न विभागों के सहयोग से इस योजना के तहत एक वृहत प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा। प्रचार–प्रसार हेतु सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। राज्य, जिला, और ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। प्रचार–प्रसार अभियान में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

घर–घर औषधि योजना को वन विभाग व जिला प्रशासन के नेतृत्व में माननीय जन–प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों, विद्यालयों, और औद्योगिक घरानों इत्यादि का सहयोग लेकर जन–अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा। योजना 5 वर्षो के लिये लागू की जायेगी। प्रथम वर्ष में योजना की सफलता के आधार पर आगामी वर्षों में योजना को बढ़ाकर सभी घरों/परिवारों में लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा। राज्य के सभी लोगों को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा।

अश्वगंधा

इस वर्ष राज्य भर में वन महोत्सव की थीम घर–घर औषधि योजना रहेगी। राज्य के समस्त जिलों और वन मंडलों के अधीन सभी फ़ॉरेस्ट रेंज, तहसील, ग्राम पंचायतें तथा शहरी निकायों में माह जुलाई में वन महोत्सव मनाया जायेगा। माह जुलाई से जिला प्रशासन द्वारा पौध–वितरण हेतु अभियान चलाया जायेगा। घर–घर औषधि योजना में वन विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा), उच्च शिक्षा विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) जयपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर सहित विभिन्न विश्व विद्यालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र आदि अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे।

योजना का नोडल विभाग वन विभाग होगा। जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला–स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। प्रबोधन एवं मूल्यांकन राज्य स्तर पर वन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा। वन विभाग द्वारा उपयुक्त प्रबोधन एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जायेगा। मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक तीन माह में समीक्षा करेगी।

तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय

एक प्रश्न उठता है कि परिवारों द्वारा पौधों को सीधे ही कैसे उपयोग में लिया जा सकता है? दरअसल, प्रचार–प्रसार के माध्यम से आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। कोविड–19 सहित अनेक वायरल तथा अन्य बीमारियों में लोग अपने वैद्यों से टेली–कंसल्टेशन कर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और टेलीमेडिसिन में परामर्श के अनुसार घर में उपलब्ध पौधों से स्वास्थ्य–लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों ही प्रजातियां कोविड–19 के विरुद्ध प्रभावी पायी गयी हैं। इसके साथ ही चूंकि ये चारों औषधीय पौधे एथनो–मेडिसिनल अर्थात स्थानीय पारम्परिक ज्ञान पर आधारित दादी–मां के नुस्खों का भी अंग हैं अतः पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान के आधार पर भी लोग इनका उपयोग कर सकते हैं।

घर–घर औषधि योजना के लिये तुलसी कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय ही क्यों चयनित किए गये? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर चार अलग–अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। पहला दृष्टिकोण मानव जीवन के लिए औषधीय पौधों के तुलनात्मक महत्त्व पर आधारित है। इस तुलनात्मक महत्त्व में विशेष रूप से चयनित औषधीय पौधों की मल्टीफंक्शनैलिटी भी शामिल है। मल्टीफंक्शनैलिटी या बहु–क्रियात्मकता से तात्पर्य यह है कि चयनित की गई चारों प्रजातियां अलग–अलग या एक दूसरे से विभिन्न अनुपातों में मिलकर अधिक से अधिक रोगों के विरुद्ध प्रभावी हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण में समकालीन समस्याओं को हल करने में चयनित औषधीय पौधों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा दृष्टिकोण औषधीय पौधों के पक्ष में आयुर्वेद की संहिताओं, समकालीन वैज्ञानिक शोध एवं चिकित्सा आधारित प्रमाण की उपलब्धता है। संहिताओं, साइंस और वैद्यों का प्रैक्टिस–बेस्ड एविडेंस मूलतः ज्ञान की उस त्रिवेणी को जन्म देता है जहां प्रमाण लगभग अकाट्य हो जाते हैं। इन चारों चयनित प्रजातियों के पक्ष में इसी प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं। तीसरा दृष्टिकोण जन सामान्य के मध्य स्थानीय ज्ञान या पारंपरिक ज्ञान जिसे एथनोमेडिसिन के रूप में भी जाना जाता है, से संबंधित है। इस दृष्टिकोण में औषधीय पौधों को विभिन्न रोगों के विरुद्ध प्रयोग करने के पूर्व लोगों के द्वारा वैद्य की सलाह से औषधि निर्माण की सरलता भी शामिल है। चौथा दृष्टिकोण चयनित प्रजातियों की जलवायु आवश्यकताओं से संबंधित है जिनके आधार पर यह समझा जा सकता है कि इन प्रजातियों का राजस्थान में उगाया जाना कहां तक संभव है। राज्य की नीतिगत प्राथमिकता पर हालांकि हम प्रारम्भ में स्पष्ट कर चुके हैं परन्तु यहां यह बताना उपयोगी है कि चयनित की गयी चारों प्रजातियां राजस्थान में सर्वत्र उगायी जा सकती हैं।

घर की बगिया और फ्लैट में औषधीय पौधे

एक प्रश्न है कि कुछ पौधें लोगों के गार्डन में या फ्लैट में गमलों में लगाने से इन पौधों का संरक्षण कैसे होगा? पहली बात तो यह है कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जब हमें जैव–विविधता का संरक्षण वहां करना होगा जहां हम रहते और काम करते हैं। घर से वन तक सम्पूर्ण भू–परिदृश्य में जैव–विविधता संरक्षण अनिवार्य है। सबसे पहले हमें अपने घरों में पौधों को संरक्षित करना होगा। उससे थोड़ा बाहर निकलने पर गांव और मोहल्ले के बाग–बगीचों में संरक्षण करना होगा। उससे आगे खेतों–खलिहानों में संरक्षण करना होगा। और अंत में, वनों और प्राकृतिक क्षेत्रों में संरक्षण करना होगा। केवल वनों में संरक्षण करने से जैव–विविधता का संरक्षण नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में उपयोग होने वाले लगभग 70 से 80 प्रतिशत औषधीय पौधे अभी भी वनों से प्राप्त होते हैं। यदि हम प्रत्येक घर में इन औषधीय पौधों को अपने उपयोग के लिये उगा लेते हैं तो स्वाभाविक है कि वनों से इनका विदोहन हमें कम करना पड़ेगा। जो लोग जैव–विविधता संरक्षण को केवल वनों में संरक्षण के अर्थ में समझते हैं उन्हें इन तमाम तथ्यों के प्रकाश में अपने अपने ज्ञान को अद्यतन करना चाहिये।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि विश्व की लगभग 80 प्रतिशत आबादी आज भी औषधीय पौधों पर किसी न किसी रूप में अवश्य निर्भर है। ऐसी स्थिति में यदि घरों में ही औषधीय पौधे उपलब्ध होते हैं तो स्वाभाविक है कि वनों से विदोहन की आवश्यकता कम हो जायेगी। इसलिए इन पौधों का घरों में उगाये जाने का संरक्षण विषयक महत्त्व केवल घरों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव पूरे लैंडस्केप और तमाम सारे पारिस्थितिकीय तंत्रों पर पड़ता है। आदिकाल में लोग वनों के इर्द–गिर्द निवास करते थे और वहीं से पौधे प्राप्त करते थे। जैसे–जैसे सभ्यता का आगे विकास हुआ, अब लोग अपने घर, गांव, खेत और खलिहान में पौधों को उगाते और उपयोग करते हैं। यह बहुत स्वाभाविक और शुभ स्थिति है। जहां हम रहते और काम करते हैं वहां जैव–विविधता को संरक्षित करना होगा और वहां ऐसी विविधता को संरक्षित करना होगा जिसे वर्किंग–बायोडायवर्सिटी कहते हैं। वर्किंग बायोडायवर्सिटी से तात्पर्य है उन प्रजातियों से है जिनकी औषधि और भोजन आदि के रूप में मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

औषधीय पौधों के साथ जानकारी का भी वितरण

घर–घर औषधि योजना केवल पौधे बांटने की योजना नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और संरक्षण से जुड़े उन विचारों को बांटने की भी योजना है जो औषधीय पौधों के योगदान को जन–मानस में बैठाते हैं। कोविड–19 की चिकित्सा के लिये अभी तक किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई पक्की तौर पर ज्ञात औषधि नहीं मिल सकी है। तथापि, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों की रिपरपजिंग की जा रही है और स्वाभाविक है कि आयुर्वेद में भी शोध और अनुभव आधारित रिपरपजिंग हो रही है। लगभग 4000 शोधपत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि

कालमेघ

तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय एक ओर कुछ हद तक संक्रमित होने से बचाव करते हैं और दूसरी ओर संक्रमित हो जाने पर पक्के तौर पर पैथोजेनेसिस को रोकने में सहायक हैं। वैद्यों की सलाह से इन औषधियों का प्रयोग बीमारी की तीव्रता इतनी नहीं बढ़ने देता कि व्यक्ति को जिंदगी के लाले पड़ने लगें।

औषधीय पौधे उगाने के सहज 7 सूत्र

घर में औषधीय पौधे उगाने के सात सहज सूत्र हैं जो घर–घर को सुखदायी और आरोग्य कर बनाये रखते हैं।

1. पहली बात यह है कि घरों में औषधीय पौधों की उन प्रजातियों को उगाया जाना बहुत लाभकारी होता है जो रोजमर्रा की चिकित्सा हेतु प्रयोग में आती हैं। घर–घर औषधि योजना के अंतर्गत आयुर्वेद के चार श्रेष्ठतम औषधीय पौधे तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, और गुडूची के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उगाकर जुलाई–अगस्त से नवंबर–दिसम्बर माह के मध्य वितरित किये जायेंगे। इन्हें प्राप्त कर कोई भी अपनी बगीची में या गमलों में लगा सकते हैं।

2. दूसरी बात यह है कि यदि हम इन प्रजातियों को तुरंत उगाना चाहते हैं तो तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधा के उपयोग योग्य पौधे बीजारोपण से घर की बगीची में या अपार्टमेन्ट की बालकनी या टेरेस–गार्डेन में रखे माध्यम आकार के गमलों में उगाये जा सकते हैं। गुडूची या गिलोय की कलम भी बगीची या दो से तीन फीट गहरे और बड़े आकार के गमलों में रोपित कर लताओं–बेलों को सहारा देकर चढ़ाया जा सकता है। गुडूची के तने की कलम जिसमें कम से कम तीन नोड हों, को सीधी मिट्टी में लगा सकते हैं। कलम के एक नोड को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए और कम से कम एक नोड ऊपर तने के फुटान के लिये रखना चाहिये। गुडूची की कलम प्राप्त करते समय ध्यान रखने योग्य

गिलोय

बात यह है कि वायुवीय जड़ों की कलम नहीं लगायें। इनमें फुटान नहीं होगा। राजस्थान में प्राप्त होने वाले बीजों में से अश्वगंधा के एक मुट्ठी बीजों का वजन 20 ग्राम होता है और बीजों की संख्या 8,520 होती है। इसी प्रकार रामा तुलसी में एक मुट्ठी में 22 ग्राम बीज आते हैं और इनकी संख्या 48,400 होती है। कालमेघ के एक मुट्ठी बीच में 30 ग्राम बीज आते हैं जिनकी कुल संख्या 13,500 बीज होती है। इस प्रकार अश्वगंधा में 426 बीज प्रति ग्राम, तुलसी में 2,200 बीज प्रति ग्राम तथा कालमेघ में 450 बीज प्रति ग्राम आंकलित किए गए हैं।

तीनों प्रजातियों के बीज गमलों में या मिट्टी में खुरपी से खुदाई कर 1 से 2 सेंटीमीटर गहरे बुवाई कर दीजिये, बीज ज्यादा गहरे नहीं डालें। तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधा के बीजों में थोड़ा राख मिलायें और गमले की मिट्टी या जमीन की क्यारी में ऊपर जरा सी राख की परत बुरक दें, नहीं तो चींटियां बीज ढोकर ले जाती हैं। बुवाई के पहले गमले या क्यारी की मिट्टी की सिंचाई करना जरूरी रहता है। लगभग 6 से 12 दिन के अन्दर तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधे में अंकुरण पूर्ण हो जाता है। लगभग 8 से 12 दिन में तुलसी, 6-7 दिन में कालमेघ, और 6-10 दिन में अश्वगंधे में अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होने तक बहुत हल्की सिंचाई करना चाहिये। उसके बाद आवश्यकतानुसार ही सिंचाई करना उपयुक्त रहता है। अगर बहुत से बीज गमले या क्यारी में अंकुरित हो गये हों तो आप इन्हें अंकुरण के तीन-चार सप्ताह के भीतर उखाड़कर अन्यत्र भी रोपित कर सकते हैं।

3. तीसरी बात यह है कि छोटे बाग़-बगीचों या अपार्टमेन्ट की बालकनी में रखे गमलों में तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय तो लगा ही सकते हैं पर घर-घर औषधि योजना को आप अपने स्तर पर सदैव के लिये आगे बढ़ाते हुये साल-दर-साल कुछ बहुउपयोगी पौधे उगा सकते हैं। अगर आप अपनी बगीची को इन चार महत्त्वपूर्ण प्रजातियों से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि चुनी गई औषधीय प्रजातियां ऐसी हों जो भोजन, रसायन एवं औषधि तीनों में ही प्रयुक्त होती हों, त्रिदोषशामक हों, और विविध प्रकार के रोगों के विरुद्ध चिकित्सा में प्रयुक्त हो सकें। तिजोरी में धन और बगीचे में पौधों का संग्रह धीरे-धीरे ही होता है। अतः यदि आप एक साथ औषधीय पौधों की बुवाई या रोपण न कर सकें तो अपनी बगीची या अपार्टमेन्ट की बालकनी में प्रजातियों की विविधता को समय के साथ बढ़ाते रहें और अगली पीढ़ी को औषधीय पौधे और उनके उपयोग का ज्ञान दोनों देकर संपन्न बनायें।

4. चौथी बात यह है कि यदि हमारे पास थोड़ी जमीन है तो बगिया का कुछ क्षेत्र ऐसा अवश्य हो जहां अनेक प्रजातियों के पौधे इस प्रकार लगाये जायें कि प्राकृतिक क्षेत्र का आभास हो। यदि बगीचे में अनेक औषधीय प्रजातियों के पौधे उगाना चाहते हैं तो इनमें से अधिसंख्य को बगीचे के एक कोने में बेतरतीबी से बहु-प्रजातीय रोपण करें। इस भाग में मानव दखल कम से कम करें ताकि प्राकृतिक वनों की तरह बीजोत्पादन, बीज विकीर्णन, पुनरुत्पादन जैसी पारिस्थितिकीय प्रक्रियायें समय के साथ अपने आप संचालित होने लगें। बगिया का यह सेमी-वाइल्ड हिस्सा बहुत मनोहारी, आरोग्यकर एवं उपयोगी होता है।

5. पांचवीं बात यह कि जैसा पहले कहा गया है, वन विभाग की पौधशालाओं में घर-घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी. कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे परन्तु बीज, कलम और पौधे प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। सबसे आसान तरीका परिवारों के मध्य पौधों और बीजों का आदान-प्रदान है जो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही विकसित हुआ है। उदाहरण के लिये, जब भी आप किसी परिवार की सुंदर बगीची देखें तो उनसे कुछ पौधे अवश्य मांग कर लायें और अपने बगीचे में लगायें। इसी प्रकार आप उन लोगों को भी कुछ पौधे उपहार में दें। घर की बगिया या गमलों में उग रहे औषधीय पौधे प्रमाणिक औषधि के साथ ही उत्तम बीजों का स्रोत भी हैं। अपने पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों के साथ बीजों का आदान-प्रदान हमारी पुरानी परंपरा है। यह परंपरा आज भी पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बीजों के इस आदान-प्रदान को सम्पूर्ण विश्व का समाज एक सुखद तोहफ़ा मानता है।

6. छठा, उपवन या बगीचे के आरोग्यकर, बहुउपयोगी एवं मनोहारी दृश्य का स्वास्थ्य पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन जब हम अपनी बगीची को शांत-चित्त होकर निहारते हैं तो हम में स्वयं स्वस्थ रहने और परिवार को स्वस्थ रखने की उत्कट लालसा जागती है। यह दिव्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव औषधि की तरह कारगर है। यह कथन कोरे उत्साहवर्धन के लिये नहीं, बल्कि विश्व में हरियाली और स्वास्थ्य के संबंधों पर प्रकाशित 6000 से अधिक शोध-पत्रों का निचोड़ है।

7. सातवां सूत्र, यदि अपने पास जगह की कमी है या आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो गमलों में भी अनेक प्रजातियों के पौधे उगाये जा सकते हैं। बगीचे में यदि पानी की कमी हो तो कम से कम वर्षा ऋतु में पौधों के इर्द-गिर्द थांवले बनाकर वर्षा-जल संरक्षण किया जा सकता है। सारांशतः सन्देश यह है कि घर-घर औषधि योजना मानव के स्वास्थ्य-रक्षण और जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा परोपकारी कदम है।•

सरिस्का 2005:

भारत में बाघ संरक्षण : एक महत्त्वपूर्ण कदम

– राजेश गुप्ता
आई.एफ.एस.
प्रथम टाइगर रिइंट्रोडक्शन प्रोग्राम में 2005 से 2008 तक टाइगर रिजर्व के उप निदेशक रहे

संगठित गिरोहों द्वारा किए गए अवैध शिकार से पूरी बाघ आबादी के विलुप्त होने के कारण घटित हुई सरिस्का त्रासदी हमारे लिए 2005 में अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बनी थी। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशकों की एक बैठक में, मेरी ओर इशारा करते हुए यह व्यंग्य किया गया कि, सरिस्का के मेरे दोस्त ... क्या आप जानते हैं कि शब्दकोश में 'सरिस्काइजेशन' नाम का एक नया शब्द होगा। जिसका उपयोग अवैध शिकार की वजह से बाघों को उनके आवास से विलुप्त होने की स्थिति में किया जाएगा?

यह शब्द मुझे आज तक सताता है।

मैंने साहस जुटाया और जवाब दिया कि कैसे सरिस्का की त्रासदी ने देश में बाघ संरक्षण के उपाय किए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की मदद से, सरिस्का में रणथंभौर से 28 जून 2008 को पहला टाइगर रिइंट्रोडक्शन किया गया। यह स्वतंत्र भारत का पहला टाइगर रिइंट्रोडक्शन कार्यक्रम था। सरिस्का में टाइगर रिइंट्रोडक्शन के लगभग 13 साल पूरे होने पर, यह विश्लेषण का समय है कि सरिस्का ने भारत में बाघ संरक्षण में कैसे योगदान दिया?

2005 में सरिस्का में अवैध शिकार के खुलासे से संरक्षणवादियों में हड़कंप मच गया। भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मार्च 2005 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में संरक्षण प्रयासों की समीक्षा की और स्थिति का आंकलन करने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व का दौरा भी किया। इसके बाद भारत सरकार ने सरिस्का संकट के आधार पर टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की समीक्षा के लिए 19 अप्रेल, 2005 को 'टाइगर टास्क फोर्स' का गठन किया। टास्क फोर्स ने टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के गहन विश्लेषण और बाघ संरक्षण तथा प्रबंधन में संस्थागत ढांचे में सुधार के लिए सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट ''जॉइनिंग द डॉट्स'' प्रस्तुत की।

कोई भी वन्य जीव प्रेमी और विशेष रूप से एक बाघ प्रेमी, अच्छी तरह से यह तथ्य जानता है कि 1 अप्रेल, 1973 को बाघ परियोजना के शुभारंभ से ही भारत में बाघों की निगरानी और गणना के लिए 1966 में स्वर्गीय श्री सरोज राज चौधरी द्वारा विकसित किए गए पगमार्क तकनीक का उपयोग किया जाता था। 1972 में पहली अखिल भारतीय बाघ गणना को उनके और उनके प्रशिक्षुओं द्वारा देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में डिजाइन किया गया था। इस तकनीक में, वन कर्मी बाघ के बाएं पैर के चिन्ह को फोरेस्ट ट्रैक में बनाए गए पग इम्प्रेशन पैड पर ट्रेस करते हैं एवं ऐसे सभी पगमार्क के आधार पर तथा माप की तुलना की जाकर बाघों की संख्या का आंकलन किया जाता था। इससे बाघों की संख्या का एक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होता था। यह तकनीक अगले तीन दशकों तक जारी रही और 1979 में इसमें पगमार्क प्लास्टर कास्ट को भी शामिल किया गया। इसे 2005 में सरिस्का के अवैध शिकार की घटनाओं तक उपयोग में लिया जाता रहा।

इसके बाद इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए और प्रोजेक्ट टाइगर ने भारतीय वन्यजीवन संस्थान (WII) देहरादून के साथ एक नया 4 चरण का टाइगर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल तैयार किया। इस तकनीक में बाघों का फोटो पंजीकरण (Photo Registration) अलग-अलग कैमरा ट्रैप द्वारा करके धारियों के आधार पर बाघों की तस्वीरों का आंकलन किया जाता है। इस प्रकार, सरिस्का ने टाइगर मॉनिटरिंग के लिए नए विश्वसनीय प्रोटोकॉल की शुरुआत की। जहां अस्पष्टता को सटीकता और स्पष्टता से बदल दिया गया। सरिस्का की घटना के बाद इस तकनीक के उपयोग से बाघों की संख्या पर संदेह मिट गया।

1973 में 18 हजार 278 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 9 टाइगर रिजर्व के रूप में शुरू हुआ कार्यक्रम, 2005 तक 37 हजार 761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करते हुए 28 टाइगर रिजर्व तक बढ़ गया था। सरिस्का की घटना के बाद, बेहतर परिभाषित प्रबंधन सिद्धांतों पर नए टाइगर रिजर्व बनाए गए। आज भारत में 51 टाइगर रिजर्व 73142 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.22 प्रतिशत हिस्सा है। बाघों की आबादी 2006 में 1411 थी जिसमें 2010 के आंकलन में 1706, 2014 में 2226 से 2018 में 2967 की वृद्धि दर्ज की गई। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीवन संस्थान और राज्य सरकारों के समर्पित प्रयासों के कारण सरिस्का के बाद के 13 वर्षों की अवधि के भीतर टाइगर रिजर्व की संख्या और बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है।

2005 से पहले, टाइगर रिजर्व शब्द का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में कोई उल्लेख नहीं था। कोर-बफर अवधारणा प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता था परन्तु कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर, 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में एक संशोधन कर टाइगर रिजर्व पर एक नया अध्याय IV-B जोड़ा गया। टाइगर रिजर्व, कोर एरिया, बफर एरिया, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, टाइगर कंजर्वेशन प्लान शब्द पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में आए। प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय को अधिक सांविधिक शक्तियों और स्वायत्तता के साथ टाइगर रिजर्व को प्रशासित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में परिवर्तित किया गया। वन्य जीवन से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए और टाइगर रिजर्व में विशेष रूप से खुफिया जानकारी की मदद से नियंत्रण के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया।

सरिस्का की जांच में खामी उजागर हुई। राजस्थान सरकार द्वारा 2005 में गठित राज्य अधिकार प्राप्त समिति (State Empowered Committee) रिपोर्ट के अनुसार, सरिस्का में बाघों के गायब होने में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक वन विभाग के साथ ग्रामीणों के प्रतिकूल संबंध और असहयोग था, जिसके परिणामस्वरूप खुफिया सूचनाओं को प्राप्त करने में विफलता हुई। बाघों के आवास में बसे गांवों ने संसाधनों पर जैविक दबाव डाला और इसके परिणामस्वरूप संघर्ष हुआ। राज्य सरकार द्वारा गठित एसईसी की रिपोर्ट में बाघों की उपस्थिति के बारे में शिकारियों को सूचना प्रसारित करने का भी उल्लेख है। इस प्रकार गांवों का पुनर्वासन टाइगर रिजर्व में संरक्षण का एक साधन बन गया। 2005 से पहले पिछले 30 वर्षों में, 80 गांवों और लगभग 2 हजार 904 परिवारों को देश के विभिन्न बाघ अभयारण्यों से बाहर पुनर्वासित किया गया था। यह सरिस्का से ही मिला झटका था जिसने भारत सरकार को 'गांवों के पुनर्वास' द्वारा बाघों के लिए 'आरक्षित स्थान' बनाने के सिद्धांत को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 2005 के बाद, लगभग 130 गांवों और 15 हजार 500 परिवारों को बाघों को अतिरिक्त सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए पुनर्वासित किया गया है। नतीजतन, सरिस्का प्रकरण के बाद 15 वर्षों में, प्रोजेक्ट टाइगर के पहले 30 वर्षों में पुनर्वासित किए गए गांवों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई और परिवारों की संख्या तीन गुना बढ़ गई जो अब भी प्रगतिरत है।

लाभार्थी-उन्मुख जनजातीय विकास योजनाओं (बीओटीडी) के दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्वास के लिए बजटीय आवंटन प्रति परिवार 1 लाख रुपए थे, लेकिन टाइगर टास्क फोर्स रिपोर्ट की सिफारिश के बाद, एनटीसीए ने 2008 में पुनर्वास के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए और राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया जो हाल ही में बढ़कर 15 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। इस वजह से अब ग्रामीणों को एक बेहतर आकर्षक पैकेज का प्रस्ताव मिल रहा है। सरिस्का 28 जून, 2008 टाइगर रिइंट्रोडक्शन में अग्रणी बन गया, जिसका 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) द्वारा बारीकी से अध्ययन किया गया। सक्रिय प्रबंधन सिद्धांतः टाइगर प्रबंधन में रिइंट्रोडक्शन प्रोटोकॉल एनटीसीए के मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा बन गया।

2005 में बाघ संकट के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (SMoEFCC) भारत सरकार को एक स्वतंत्र ऑडिट करने और संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया। इसके बाद देश के बाघ अभयारण्यों के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करने पर सहमति बनी।

इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्र को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है, इसका आंकलन करने के लिए एक प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन मॉड्यूल (Management Effectiveness Evaluation) विकसित किया गया था-इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह देखना था कि क्या वे अपने मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं? लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं? एमईई 2006 से 2018 तक हर चार साल के बाद 4 चक्रों में आयोजित किया गया। 2006 में 28 टाइगर रिजर्व में पहले चक्र की शुरुआत की गई थी। सरिस्का में जो कुछ भी हुआ वह बाघ संरक्षण के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत सरकार द्वारा गठित टाइगर टास्क फोर्स, राजस्थान की राज्य अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और एनटीसीए द्वारा टाइगर टास्क फोर्स के सुझावों के कार्यान्वयन ने सरिस्का संकट को देश के अन्य सभी टाइगर रिजर्व के लिए एक अवसर में बदल दिया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2005 में क्या हुआ था।

शब्दकोश में 'सरिस्काइजेशन' जैसा शब्द कभी नहीं होना चाहिए और हो तो सरिस्काइजेशन का अर्थ बाघों के प्रथम पुनर्स्थापन के संदर्भ में होना चाहिए। •

फोटो–फीचर

Indian Hare

Peafowl

Sunbird

Spotted owlet

Painted Stork

Laughing Dove

Monitor Lizard

Western swamphen

Indian roller

Rose Ringed Parakeet

Lime Butterfly

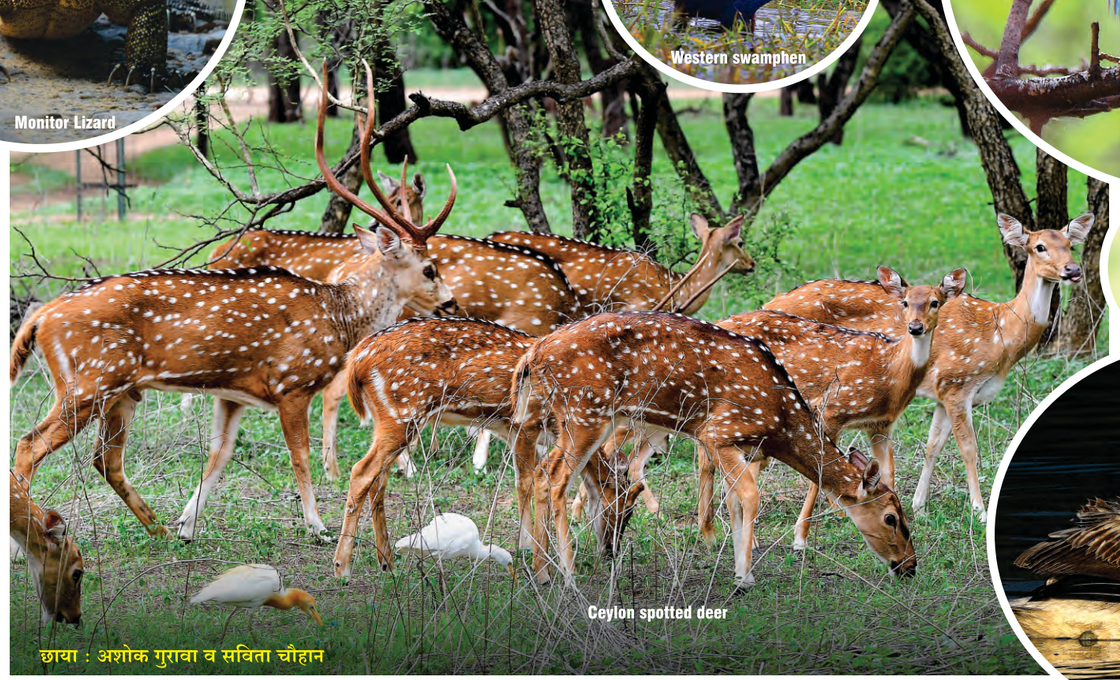
Ceylon spotted deer

छाया : अशोक गुरावा व सविता चौहान

Indian Paradise Flycatcher

Great White Pelican

Leopard (Panthera pardus)

चित्तौड़गढ़ ने दस से अधिक जिलों को दी सांसे

– प्रवेश परदेशी
जनसंपर्क अधिकारी

कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब ऑक्सीजन की त्राहि-त्राहि मची तो कई जिलों को संकट से बाहर लाने के लिए चित्तौड़गढ़ आगे आया। जिले ने न सिर्फ अपने मरीजों को, बल्कि दस से अधिक जिलों को निरंतर ऑक्सीजन पहुंचा कर हजारों लोगों को राहत प्रदान की लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था।

जिला कलक्टर श्री ताराचंद मीणा की दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय से न सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिला एक बड़े संकट से उबरने में सफल रहा। जिले के सभी प्लाण्ट में निरंतर दिन-रात काम होता रहा और ऑक्सीजन बनती रही।

विभिन्न ज़िलों से आने वाले वाहनों को असुविधा न हो इसके लिए संभागीय आयुक्त श्री राजेन्द्र भट्ट के मार्गदर्शन में जिला कलक्टर की ओर से प्रतिदिन का कार्यक्रम जारी किया जाता। इसमें हर जिले को एक निश्चित टाइम स्लॉट आवंटित किया गया। किस जिले की कौनसी गाडी किस प्लाण्ट से ऑक्सीजन प्राप्त करेगी, यह सब पहले ही प्लान कर सम्बंधित जिला कलक्टर को यथासमय अवगत कराया गया, जिससे सुविधाजनक तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई का प्रबंधन संभव हो सका।

जब ताउ'ते (तौकाते) चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी हुई, तो जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। ऑक्सीजन उत्पादन कहीं बंद न हो जाए, इसके लिए जिला कलक्टर ने ऑक्सीजन प्लाण्ट में निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रतलाम और भिवाड़ी से एक-एक और पोलीफेब चित्तौड़गढ़ से एक डीजल जनरेटर सेट मंगवा कर ऑक्सीजन प्लाण्ट में भेजे। इस प्रकार ऑक्सीजन प्लाण्ट निरंतर काम करते रहे एवं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इसके साथ ही हर चिकित्सालय में भी निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

जिला कलक्टर ने एक और पहल करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर का बफर स्टोक रखना भी शुरू किया, ताकि अचानक डिमांड बढ़ने पर किसी जिले को ऑक्सीजन दी जा सके। जब प्रतापगढ़ और बारां से अचानक अतिरिक्त ऑक्सीजन की डिमांड आई, तो जिला कलक्टर ने अपनी गाड़ियों से कई जिलों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। इसके अलावा एक और नवाचार यह हुआ कि प्रशासन ने विभिन्न माध्यमों से खाली सिलेंडर प्राप्त किए और डिमांड अनुसार प्रतापगढ़ को 250, बारां को 100, सवाई माधोपुर को 50 एवं बांसवाडा को 45 खाली सिलेंडर पहुंचाए गए, जिससे इन जिलों के मरीजों की काफी मदद हुई है।•

प्रशासन एवं ग्रामवासियों के समन्वय, त्वरित निर्णय और प्रभावी कदमों से सरोदा ने जीती जंग

– छाया चौबीसा
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

'साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएं तो मिलकर.....' इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर जिले की छोटी सी ग्राम पंचायत सरोदा में प्रशासन एवं ग्रामवासियों और विशेषकर युवाओं की मदद से त्वरित निर्णय एवं समन्वय के साथ कार्य कर वो कर दिखाया जिससे कोरोना को भी हारना पड़ा। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर उपखण्ड क्षेत्र सागवाड़ा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत सरोदा, पंचायत समिति मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसमें कुल तीन राजस्व गांव सरोदा, डामोरवाड़ा, केसरपुरा सम्मिलित है। इसकी कुल जनसंख्या 5755 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सरोदा में 4231, डामोरवाड़ा में 1075 तथा केसरपुरा में 449 है। ग्राम पंचायत सरोदा में 3 मई से पूर्व अचानक से बढ़े कोरोना संक्रमण की स्थिति में ग्राम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए पूरे समन्वय के साथ बेहतरीन कार्य किया परिणाम स्वरूप तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर तत्परता से काबू पाने में सफल हो सके।

वार्ड वाईज कमेटियां, पंचायत हेल्प लाइन की प्रभावी कार्यवाही:

ग्राम पंचायत क्षेत्र में 03 मई से पूर्व लगभग 82 लोग संक्रमित हो चुके थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए तथा संक्रमितों की संख्या में कमी करने हेतु पंद्रह दिवस तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। ग्राम पंचायत के समस्त 13 वार्डो में जन-अनुशासन पखवाड़े का पालन करवाने हेतु वार्ड पंच की अध्यक्षता में पांच व्यक्तियों की कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों ने अपने वार्ड में कोविड गाइडलाईन्स की पालना सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभाई।•

इन्दिरा रसोई योजना

– सौरभ सिंघारिया
जन संपर्क अधिकारी, राजसमंद

''कोई भी भूखा ना सोए'' के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयन्ती के अवसर पर 20 अगस्त से इन्दिरा रसोई योजना को शुरू किया था।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर आमजन को महामारी से बचाने के लिये लगाये गये जनअनुशासन रेड अलर्ट पखवाड़ा लॉकडाउन में अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की मंशानुरूप 'कोई व्यक्ति भूखा ना सोयें' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से इन्दिरा रसोई में नि:शुल्क भोजन दिया जा रहा है। जिसमें कोई भी व्यक्ति जो दिहाड़ी, मजदूर, निर्धन, ठेले वाले, अन्य कोई भी इन्दिरा रसोई में बैठकर ससम्मान भोजन कर सकता है।

13 हजार 142 फूड पैकेट का वितरण

राजसमन्द नगर परिषद द्वारा राजसमन्द में लगभग पांच सौ से सात सौ भोजन के पैकेट भी जरूरतमंद लोगों को दोनों समय दिये जा रहे हैं। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल के निर्देशानुसार राज्य में अस्पतालों, आइसोलेशन सेन्टर्स एवं कोविड केयर सेन्टर्स में उपचाराधीन कोरोना संक्रमितों को अब इन्दिरा रसोइयों में नि:शुल्क भोजन उपलब्ध है। •

मृतक के आश्रित को आवेदन के 15 दिन में मिली अनुकंपा नियुक्ति

– साक्षी पुरोहित
जन संपर्क अधिकारी, जोधपुर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता से सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मृतक के आश्रितों को उनके आवेदन पर हाथों हाथ कार्यवाही कर मृतक आश्रित के परिवारों को कठिन घड़ी में सम्बल प्रदान कर रही है।

वर्तमान सरकार द्वारा पाली नगर परिषद के एक मृतक सफाई कर्मचारी के आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन के 15 दिन पश्चात ही आश्रित को नियुक्ति पत्र देकर आश्रित के परिवार को राहत प्रदान की है। पाली नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी श्री अमृतलाल की 31 मार्च, 2021 को मृत्यु हुई तब उसके आश्रित को 90 दिनों के भीतर नौकरी के लिए आवेदन करना था। अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसकी पत्नी अंजू ने 3 मई 2021 को आवेदन किया। 18 मई को स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के क्षेत्रीय उप निदेशक श्री दलवीर सिंह ढढ्ढा ने वर्चुअल बैठक लेकर आवेदन की जांच कर आश्रित को नियुक्ति देने का निर्णय लिया और उसी दिन नगर परिषद् पाली के आयुक्त ने आश्रित अंजू को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया। इसी तरह नगर पालिका भीनमाल के मृतक सफाई कर्मचारी श्री मदन लाल की आश्रिता दरिया देवी को भी उनके आवेदन प्राप्त होने के 48 वें दिन 18 मई को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। 19 मई को नगर पालिका पीपाड़ में मृतक सफाई कर्मचारी जगदीश की पत्नी मोनू को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। श्री जगदीश की मृत्यु 31 दिसंबर 2020 को हुई थी उसकी पत्नी मोनू ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 2 फरवरी, 2021 को आवेदन किया था।

क्षेत्रीय निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विभाग ने जोधपुर संभाग की स्थानीय निकायों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति में चल रहा बैकलॉग समाप्त कर दिया है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रितों से आवेदन लेकर उन्हें शीघ्र ही नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। •

व्यापक जैव विविधता से भरपूर है चंबल बेसिन

– डॉ. प्रभात कुमार सिंघल
पूर्व संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क

देश की जैव विविधता में वनस्पति के साथ-साथ वन्यजीवों का विशेष महत्त्व है। वन्यजीव हमारे पर्यावरण को बचाने में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्यजीवों को हमारे जंगलों और अभयारण्यों में देखा जा सकता है। वन्य जीवों को बचाने एवं संरक्षित करने के लिए देश में अभयारण्यों का विकास किया गया एवं कई जगह चिड़ियाघर विकसित किए गए।

अनेक जीवों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार तक पहुंच गया जिन्हें संरक्षित करने के लिए उनके संरक्षण की विशेष योजनाएं संचालित की गई। प्रारंभ में स्थापित अभयारण्यों में से अनेक को देश में राष्ट्रीय प्राणी पार्क बनाया गया। देश का प्रथम कॉर्बेट राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 1936 में उत्तराखंड (पूर्व में उत्तर-प्रदेश में शामिल) में स्थापित किया गया। जम्मू एवं कश्मीर का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का मरुभूमि, उत्तराखंड का गंगोत्री, अरुणाचल प्रदेश का नमदाफा वन्य जीव अभयारण्य, सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास एवं इंद्रावती, गुजरात का गिर एवं पश्चिम बंगाल का सुन्दरबन देश के प्रमुख विख्यात राष्ट्रीय प्राणी पार्क हैं। ये नेशनल पार्क लुप्त होते वन्य जीवों का संरक्षण तो करते ही हैं वहीं इन्हें देखने के लिए पूरे विश्व से सैलानी आते हैं।

चम्बल नदी भारत की पहली ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी की गोद में समा जाती है। चम्बल नदी पर बांधों के बन जाने से देश को बिजली, सिंचाई और पेयजल सुविधा तो मिली किंतु नदी में रहने वाले जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया।

चंबल नदी के रेतीले तट गहरे जल में समा गए तथा कल-कल बहती हुई नदी विशाल जलाशय में बदल गई। अनेक प्रकार की मछलियां जो कल-कल बहने वाली नदी में ही रहना पसन्द करती थी, वे नष्ट हो गईं। नदी के बीच में द्वीप क्षेत्रों पर तथा नदी के रेतीले तटों पर ऊदबिलाव, मगरमच्छ तथा घड़ियाल प्रजनन करते थे, अण्डे देते थे तथा रेत स्नान एवं धूप का आनन्द लेते थे। जब रेतीले तट और द्वीप क्षेत्र नष्ट हो गये तो इन जन्तुओं का प्रजनन करना बहुत कठिन हो गया और ये भी नष्ट होने के कगार पर आ गए। मानव द्वारा इन जलचरों का लगातार शिकार किए जाने के कारण भी ये प्रजातियां तेजी से नष्ट होने की तरफ बढ़ीं। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि घड़ियाल (गैवियलिस गैगेटिकस) चम्बल से लुप्त होता जा रहा है।

चम्बल नदी के बेसिन के अभयारण्यों एवं जंगलों में बबूल, बेर, सालर, खिरनी लेबुरम, अर्जुन, धोक, बेल, महुआ, बेलेनाइटिस आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। मुख्य घाटियों में धोक ही ज्यादा मिलता है।

चम्बल नदी के किनारे कराइयों में चौसिंगा, जरख, काले हिरण, चिंकारा, चितकबरा हिरन, लोमड़ी, नीलगाय, भालू, पैंथर, टाइगर, साम्भर, नेवला, खरगोश, सियघोष, जंगली लंगूर, लाल मुंह के बंदर, बिल्ली, सियार, भालू, जंगली बिल्ली, नेवला, खरगोश आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। यहां एवियन जाती के पक्षियों की विविधता असाधारण है। चम्बल के किनारे एवं जलाशयों में स्थानीय एवं ग्रीष्म-पथ प्रवास वाले पक्षियों में सारस, टिकड़ी, नकटा, छोटी डूबडूबी, सींगपर,

जांघिल, घोंघिल, चमचा, लोहरजंग, हाजी लगलग होता है।

इसके साथ – साथ सफेद हवासील, गिर्री बतख, गुगलर बतख, छोटी सिलही बतख, सफेद बुज्जा, कौआरी बुज्जा, कला बुज्जा, सिलेटी अंजन, नरी अंजन, गजपांव, बड़ा हंसावर, टिटहरी, जर्द टिटहरी, अंधा बगुला, करछीया बगुला, गाय बगुला, गुडेरा, यूरेशियाई करवान, बड़ा करवान, छोटा पनकोवा, जल कूकड़ी, जीरा बटन, मोर, हीरामन तोता, कांटीवाल तोता, टुईयां तोता पाया जाता है। सामान्य रूप से पपीहा, हरा पतरंग, अबलक चातक, कबूतर, धवल फाखता, चितरोया फाखता, ईट कोहरी फाखता, टूटरुं, कुहार भटतीतर, कोयल, करेल उल्लू, हुदहुद, नीलकंठ, मैना, अबलकी मैना, गुलाबी मैना, अबाबील, रामगंगरा, सफेद भौंह खंजन, बैंगनी शक्कर खोरा, मुनिया, बयां, चित्रित तीतर, सफेद तीतर, सिलेटी दुम फुदकी, गौरैया आदि प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। मोर भी बड़ी संख्या में देखे जाते हैं।

शीत ऋतु के दौरान अनेक प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। राजहंस, सरपट्टी सवन, नीलसर, छोटा जल मुर्गा, छोटी लालसिर बतख, तिधलरी बतख, पियासन बतख, अबलख बतख, सुर्खाब, गेड़वाल, जमुनी जलमुर्गी, जल पीपी, जलमुर्गी, पीहो, छोटी सुरमा चैबाहा, चुटकन्ना उल्लू, कला शिरशिरा एवं सफेद खंजन आदि प्रमुख प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। चम्बल नदी क्षेत्र में लगभग 150 प्रकार की पक्षी प्रजातियां पायी जाती हैं। कीटों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं।

चम्बल घड़ियाल अभयारण्य

घड़ियाल पूरे विश्व में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सिन्ध तथा चम्बल में ही पाए जाते थे। वर्ष 1974 में सिन्ध नदी में लगभग 70 घड़ियाल थे किन्तु अस्सी के दशक में सिन्ध नदी में एक भी घड़ियाल शेष नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन जलचरों की प्रजातियों के समाप्त होते जाने का प्रमुख कारण उनके नैसर्गिक निवास स्थलों का नष्ट होना, चमड़े के लिए शिकार किया जाना तथा मछली पकड़ने के जालों में फंस जाने के कारण डूबने से मर जाना बताया।

अत: भारत सरकार ने घड़ियाल के पुनर्वास की व्यापक योजना बनाई जिसके तहत घड़ियालों एवं मगरमच्छों के अण्डों से बच्चे तैयार कर उन्हें फिर से नदियों में छोड़ा जाना सम्मिलित था। चम्बल नदी घड़ियालों के लिए बेहतर प्राकृतिक आवास है। इसके अतिरिक्त अन्य लुप्तप्राय: जीव जैसे ऊदबिलाव, गांगेय सूंस (डाल्फिन) तथा मगरमच्छ भी इसमें पाए जाते हैं।

लुप्त होते घड़ियालों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 30 सितम्बर 1978 को राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। यह अभयारण्य तीन राज्यों की सीमा क्षेत्र में आने से मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र की अधिसूचना 20 दिसम्बर 1978 को की गई। इसी प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 20 जनवरी 1979 को एवं राजस्थान राज्य द्वारा 7 दिसम्बर 1979 को जारी की गई। लगभग 600 किलोमीटर लम्बे तथा नदी तट के दोनों ओर 1 हजार मीटर चौड़े क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया। चम्बल घड़ियाल अभयारण्य का दक्षिणी छोर कोटा शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध से प्रारम्भ होता है।

कोटा बैराज के केशोरायपाटन तक के 18 किलोमीटर के मुक्त क्षेत्र को छोड़कर यह अभयारण्य पालीघाट, बटेसुरा होते हुए पंचनदा में चम्बल, पहूंज, कुंवारी और सिंध नदियों के यमुना में मिलन स्थल तक फैला हुआ है। अभयारण्य की देखरेख एवं प्रशासनिक कार्य के लिए वन विभाग के अधीन परियोजना अधिकारी का कार्यालय मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया।

चम्बल नदी में घड़ियाल संरक्षण परियोजना, 1979 से प्रारंभ की गई और 1980 में इसकी स्थापना की गई। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य मगरमच्छ प्रजातियों के संरक्षण का दुनिया में सबसे बड़ा अभयारण्य है। चम्बल नदी में 1979 से 1987 के मध्य अलग-अलग स्थानों पर तीन से चार वर्ष की आयु के लगभग एक से दो मीटर तक की लम्बाई वाले 1287 शिशु घड़ियाल छोड़े गए। ये घड़ियाल शिशु मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल प्रजनन केन्द्र से लाए गए थे।

घड़ियाल प्रजनन के लिए राजस्थान में कोटा के निकट गुड़ला में बेहतर साइट है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की इटावा रेंज में खेड़ा अजब सिंह, कसऊआ, पिनाहट रेंज के रेहा घाट, विप्रवली, चम्बल की रेतिया, बाह केन्जरा, हरलालपुरा एवं नंदगवां में घड़ियाल की प्रजनन

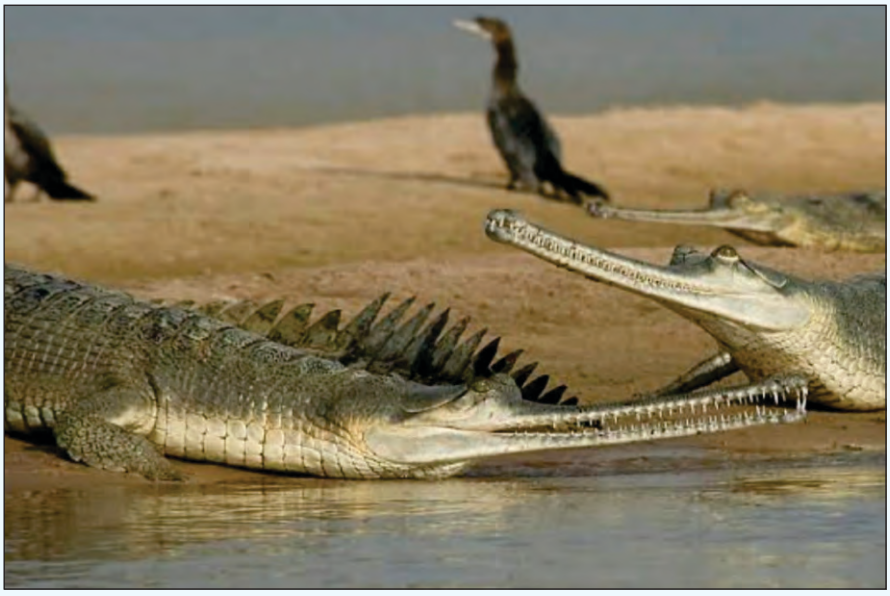

साइट्स है। इनका प्रजनन काल 15 जून तक होता है जब अंडों से बच्चे निकलते हैं। एक मादा घड़ियाल एक समय में अपने घोंसले जिसे बिल भी कहते हैं 40 से 60 अंडे देती हैं। अक्सर 15 जून के बाद मानसून का मौसम शुरू हो जाता है। बरसात से और नदी में पानी के तेज वेग से काफी अंडे बह कर नष्ट हो जाते हैं और 10 प्रतिशत बच्चे ही बच पाते हैं। रेत का अवैध खनन भी इनके जीवन को प्रभावित करता है। इन जगहों पर घड़ियालों को प्रजनन करते, अंडों से नन्हे-नन्हे बच्चे निकलते, उनकी अठखेलियां देख खास कर विदेशी सैलानी आनन्दित होते हैं।

घड़ियाल अभयारण्य को देखने के लिए उपवन संरक्षक (वन्य जीव) मुरैना से अनुमति लेनी होती है। जवाहर सागर से कोटा बैराज तक या तो नदी में नाव के माध्यम से या फिर नदी के तट पर जीप के द्वारा यात्रा की जा सकती है। चम्बल घड़ियाल अभयारण्य को नजदीक से देखने के लिए अनेक स्थानों पर व्यू पॉइंट्स बनाये गए हैं। कई व्यू पॉइंट से कोटा में उपलब्ध गाइड के साथ जलचर, किनारे के पक्षी एवं लैंड्सकैप का आनन्द और फोटोग्राफी के लिए बोट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पिनाहट, नंदगांव घाट, सेहसों एवं भरच तक वाहन से भी जाया जा सकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिकारी के माध्यम से बोटिंग की व्यवस्था की जा सकती है। अभयारण्य परियोजना क्षेत्र में नदी की गहराई में गेपरनाथ महादेव का प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है। केशोरायपाटन में भगवान कृष्ण के प्राचीन मंदिर हैं, जहां पर्यटक ग्रामीण मेलों का आनन्द उठा सकते हैं। पालीघाट से रणथम्भौर का ऐतिहासिक किला, बाघ परियोजना क्षेत्र और अभयारण्य अधिक दूर नहीं हैं। वन विभाग की सख्ती के चलते जंगल में मानवीय दबाव व अवैध शिकार पर अंकुश लगा है।

चम्बल नदी के किनारे राजस्थान के धौलपुर शहर के समीप 20 किमी दूरी पर मध्य प्रदेश के मुरैना में ईको सेंटर घड़ियाल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। यहां घड़ियाल हेचरी में चम्बल से हर वर्ष मई माह में करीब 200 अंडों को लाकर पोटेशियम परमेगनेट के घोल में धोते हैं एवं अंडों को हेचरी की रेत में दबाकर रख देते हैं। जन्म से पहले अंडे से आवाज आती है और कुछ देर में अंडा फोड़ कर घड़ियाल का नन्हा बच्चा बाहर निकल आता है। इन बच्चों को चार वर्ष तक देवरी सेंटर के विभिन्न पुलों में पूर्ण देखरेख में पाला जाता है। इन पुलों में घड़ियाल के बच्चों की अठखेलियां देखते ही बनती हैं। नदी में घड़ियाल को नजदीक से देखने का यह एक सुंदर स्थल है। नदी में छोड़ते समय इनकी पूंछ पर टैग लगा देते हैं। यह ईको सेंटर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष इसे देखने आते हैं।

बरही गांव में कछुआ संरक्षण केंद्र

चंबल बेसिन क्षेत्र में भिंड जिले के बॉर्डर पर चंबल नदी किनारे बरही गांव कछुआ संरक्षण केन्द्र को मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र की तरह विकसित किया जा रहा है। पिछले दिनों अभयारण्य से पहली बार कछुओं को केंद्र में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल 269 कछुए शिफ्ट किए गए हैं। इनमें 70 बाटागुर डोंगोका, 4 पंगसुरा टेंटोरिया, 195 बाटागुर कछुगा प्रजाति के कछुए हैं। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी के हैं। मध्य नेपाल, उत्तरपूर्वी भारत, बांग्लादेश और बर्मा में पाया जाता है।

दुनियाभर में इसका अंतिम व्यवहार आवास चंबल सेंक्चुरी है। भिंड के बरही गांव में चंबल नदी किनारे बनाए गए कछुआ संरक्षण केंद्र परियोजना के अंतर्गत सेंक्चुरी में 4 स्थान बरौली-कतरनीपुरा घाट, बटेश्वरा घाट, उसैद घाट और कनकपुरा घाट पर कछुओं के प्राकृतिक आवास हैं।

चंबल में हैं खास प्रजाति के कछुए:

बाटागुर कछुआ यह लाल मुकुट वाला कछुआ दक्षिण एशिया के मीठे पानी में रहने वाली प्रजाति है। मादा की लंबाई 56 सेमी तक होती है। वजन 25 किलो ग्राम तक होता है। नर काफी छोटे होते हैं। बाटागुर डोंगोकाः लुप्तप्राय प्रजाति का है। यह तीन धारीवाला होता है। पंगसुरा टेंटोरियाः कूबड़ निकला होता है और मेहराबदार होता है। चित्रा इंडिकाः लुप्तप्राय प्रजाति है। यह छोटे सिर और कोमल कवच वाला होता है। निल्सोनिया गैंगेटिका का ऊपरी हिस्सा कालीन की तरह होता है। यह 94 सेमी तक लंबा है। यह खुशी की बात है कि चम्बल सेंक्चुरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर खतरे में घोषित बाटागुर कछुआ प्रजाति

का कुनबा भी बढ़ रहा है। इससे चम्बल को नई पहचान मिलेगी। चम्बल नदी में एवं किनारे-किनारे कंदराओं में पाये जाने वाले इन जलीय जीवों के साथ चम्बल के सहारे-सहारे वन्यजीव अभयारण्य भी मौजूद हैं।

भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

चम्बल के किनारे अरावली पर्वत की गोद में भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रकृति एवं वन्यजीवों को देखने का खूबसूरत स्थल है। यह अभयारण्य भारत के प्रमुख अभयारण्यों में माना जाता है जिसकी घोषणा 1983 ई. में की गई थी। यह स्थल प्रकृति प्रेमियों एवं फोटोग्राफर्स के लिए पूर्ण आकर्षण लिए हुए है। अभयारण्य के 229.14 वर्ग क्षेत्रफल में बबूल, बेर, सालर, खीरनी आदि वनस्पति पाई जाती हैं। यहां वन्य जीवों को विचरण करते देखना रोमांचित करता है। यहां पैंथर, सियार, जरख, खरगोश , जंगली बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, भालू, बिज्जू, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, उड़न गिलहरी, जंगली सूअर, गिद्द, जंगली मुर्गी, मगरमच्छ, काला मुंह का बंदर, नेवला, सर्प आदि वन्यजीव एवं मोर, सारस, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं पक्षी पाए जाते हैं। अभयारण्य को देखने के लिए प्रातः काल प्रवेश करना उपयुक्त रहता है जिससे पूरे दिन वन्य जीवों और प्रकृति का भरपूर आनंद लिया जा सके। भैंसरोड़ किले में ठहरने की उत्तम व्यवस्था है।

मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय टाइगर पार्क

घना जंगल, पहाड़, झरने, पोखर, तालाब और सदानीरा चम्बल और प्रकृति की गोद में पलते सैकड़ों प्रजाति के वन्यजीव जैसा स्थान बाघों की बसावट के लिए मुकुन्दरा सुरक्षित, अनुकूल और आदर्श जगह है। इस अनूठे रिजर्व में वन्यजीव, वनस्पति, पुरा सम्पदा पर्यटकों को आकर्षित करती है। मुकुन्दरा हिल्स को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने के लिए 9 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई। जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य के कुछ भाग लगभग 199.51 वर्ग क्षेत्र को मिलाकर राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क बनाने की घोषणा की गई एवं 10 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। रणथंभौर एवं सरिस्का पहले से टाइगर रिजर्व हैं। उल्लेखनीय है कि मुकुन्दरा हिल में 1955 में दरा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 294.41 वर्ग किलोमीटर एवं बाघ परियोजना का क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है जिसमें कोर क्षेत्र 417 वर्ग किलोमीटर एवं बफर जोन क्षेत्र 342.82 वर्ग किलोमीटर है।

वनस्पति एवं जैव विविधता इसकी विशेषता है। इसमें शुष्क, पतझड़ी वन, पहाडियां, नदी, घाटियों के बीच तेंदू, पलाश, बरगद, पीपल, महुआ, बेल, अमलताश, जामुन, नीम, इमली, अर्जुन, कदम, सेमल और आंवले के वृक्ष पाये जाते हैं। यहां चीतल, भालू, पैंथर व सांभर हैं।

चम्बल नदी किनारे बघेरे, भालू, भेड़िया, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय, काले हरिन, दुर्लभ स्याहगोह, निशाचर सिविट केट और रेटल जैसे दुर्लभ प्राणी भी देखने को मिलेंगे। गागरोनी तोता मुकुंदरा हिल्स में पाया जाने वाला विशेष प्रजाति का तोता है जिसकी कंठी लाल रंग की व पंख पर लाल रंग का धब्बा होता है। इसे हीरामन तोता तथा हिंदुओं का आकाश लोचन (मनुष्य की आवाज में बोलने वाला) भी कहा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस तोते का उपयोग जासूसी करने हेतु किया जाता था। इसे वन विभाग ने झालावाड़ जिले का शुभंकर घोषित किया है। रिजर्व के सेल्जर क्षेत्र में एक हैक्टेयर में एक एनक्लोजर एवं 28 हैक्टेयर में एक अन्य एनक्लोजर सावन भादो क्षेत्र में बनाया गया है।

पर्यटक मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 25 किलोमीटर जंगल की सैर के साथ चंबल की सफारी भी कर सकेंगे। पर्यटकों को चंबल में बोटिंग करवाई जाएगी।

जवाहर सागर से भैंसरोडगढ़ तक बोट में सवार होकर चंबल के सौन्दर्य को नजदीक से निहार सकेंगे और साथ ही जंगल के दिलचस्प नजारों को आप कैमरे में कैद कर सकेंगे। यहां आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे कि आज तक आपने देखे ही नहीं होंगे। आने वाले समय में हाड़ौती पूरे देश में पर्यटन सर्किल के रूप के उभरेगा।

यह रिजर्व अन्य टाइगर रिजर्वों से कहीं अधिक खूबसूरत, बड़ा और समृद्ध है। यह पहला टाइगर रिजर्व है, जहां लोगों को जंगल और जल दोनों मार्गों की यात्रा का अवसर मिलेगा। मुकुंदरा अभयारण्य से चंबल, काली सिंध, आहू, आमझर नदियां जुड़ी हुई हैं। अभयारण्य क्षेत्र में रामसागर व झामरा नामक स्थानों पर जंगली जानवरों के अवलोकन के लिए अवलोकन ओदियां बनाई गई हैं।

जवाहर सागर अभयारण्य

जवाहर सागर अभयारण्य कोटा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है तथा कोटा रावत भाटा राज्यमार्ग पर स्थित है। जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज का भराव क्षेत्र वन्य जीवों की विहार स्थली है।

वर्ष 1975 में जवाहर सागर अभयारण्य की घोषणा की गई तथा 1980 में पुन: जवाहर सागर अभयारण्य के कुछ भाग को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य की घोषणा की गई। धोकड़ा तथा बांस के वनों से आच्छादित यह अभयारण्य तथा चम्बल नदी का सीधा खड़ा तट जैविक विविधता का विपुल भण्डार है। यह अभयारण्य 315 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में घड़ियाल, मगरमच्छ, जल-मानुष आदि जलचर एवं बघेरा, चीतल, जंगली सूअर, रीछ, लोमड़ी, सियार, नीलगाय (रोझ) चिंकारा, लक्कड़ बग्घा आदि वन्यजीव देखे जा सकते हैं।

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य

बूंदी से 15 किमी की दूरी पर है और बूंदी-नैनवा रास्ते पर स्थित है। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का आवास है। तेंदुआ, सांभर, जंगली सूअर, चिंकारा, स्लॉथ भालू, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, और लोमड़ी इस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। यह 252.79 किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2012 में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से निकलकर बूंदी के जंगलों में आया एक युवा बाघ रामगढ की खोई हुई शान को वापस लौटाने में मील का पत्थर साबित हुआ। रामगढ़ में ही इस बाघ का टी 62 नामकरण हुआ। टी 62 करीब डेढ़ साल तक रामगढ़ व बूंदी के जंगलों में रहा इससे वन अमला हरकत में आया तथा जंगल में फिर से सुरक्षा बढ़ने लगी।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान

चम्बल नदी के प्रवाह मार्ग में सवाईमाधोपुर में रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क बाघों की सर्वोत्तम क्रीड़ा स्थल है। यहां के वन्य जीवों में सबसे प्रमुख है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे यहां दिन की रोशनी में भी आराम से देखा जा सकता है। यहां बाघ के अलावा तेंदुआ, जरख, रीछ, सियार, सहेली, नील गाय, सांभर, चीतल, हिरण, जंगली सूअर, चिंकारा, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ आदि वन्य जीव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान प्राचीन काल से ही अपने पशु-पक्षियों के लिए विख्यात रहा है। रियासती काल में यह जयपुर के महाराजाओं की शिकारगाह थी। आजादी के बाद राज्य सरकार ने 7 नवम्बर 1955 को इसके 392.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को अभयारण्य घोषित किया।

बाघ परियोजना के लिए चयनित 9 बाघ रिजर्व क्षेत्रों में से रणथम्भौर भी एक है। इसे 1 नवम्बर 1980 को राणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 274.5 वर्ग किलोमीटर है। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 133.6 वर्ग किलोमीटर है। यह एक शुष्क पतझड़ी वन क्षेत्र है, जहां अरावली एवं विन्ध्याचल दोनों की पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। यहां इस समुचित क्षेत्र में पदम तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर एवं लाहपुर झीलें हैं। सवाई माधोपुर शहर से करीब 13-14 किलोमीटर दूर स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इसके खुले बरामदे में बैठकर सामने बने पद्म तालाब में वन्यजीवों को विभिन्न गतिविधियां करते हुए देख मन अति प्रसन्न होता है। पद्म तालाब के अतिरिक्त राजबाग और मलिक तालाब के आस-पास भी सैकड़ों की संख्या में चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सूअर भी घूमते हुए देखे जा सकते हैं। रणथम्भौर ने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर अपना एक अलग स्थान बनाया है, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय पशु बाघ है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी उद्यान

चंबल के बेसिन से लगता केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पर 390 से अधिक प्रजाति के पक्षियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से करीब 120 प्रजाति के प्रवासी (माईग्रेटरी) पक्षी तथा शेष आवासी (रेजीडेन्ट) पक्षी हैं। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों आवासी (रेजीडेन्ट) पक्षी यहां आकर अपने नीड़ का निर्माण करते हैं। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही एक मात्र ऐसा स्थान है, जहाँ साइबेरियन क्रेन सर्दियां बिताने आते हैं। ये करीब अक्टूबर के अंत या नवम्बर के प्रारम्भ में आते हैं और फरवरी के अंत या मार्च के प्रारंभ में साइबेरिया के लिए वापस प्रस्थान कर जाते हैं। प्रति वर्ष ओपेन बिल्ड स्टार्क, पेन्टेड स्टार्क, इग्रेट, स्पूनबिल, कार्मोरेन्ट, स्नेक बर्ड, व्हाइट आईबिस, ग्रेहीरान आदि प्रजाति के हजारों पक्षी यहां आकर अपने जोड़े बनाकर प्रजनन करते हैं। इन विभिन्न पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले कुशल कारीगरी का परिचय देते हैं।

कैलादेवी अभयारण्य

चम्बल बेसिन में करौली में कैलादेवी अभ्यारण्य भी बाघ परियोजना का हिस्सा है। पूर्व में यह बाघों की शरणस्थली रहा है जिसमें रियासतों के समय में बाघों की अच्छी संख्या पाई जाती थी। राज्य सरकार ने 1984 में यह क्षेत्र अभयारण्य के रूप में घोषित किया। प्रभावी संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए 1991 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अभयारण्य का सम्पूर्ण क्षेत्र नालों, दर्रों के साथ-साथ ऊंचा-नीचा और पथरीला है। विंध्याचल पर्वत की घाटियां, चट्टानें जो समतल एवं चपटी हैं जिनमें खोह जैसी आकृतियां पाई जाती हैं जो देखने में अत्यन्त रमणीक एवं चित्ताकर्षक हैं। यह क्षेत्र शुद्ध रूप से धोंक वन क्षेत्र है। धोंक के साथ-साथ अन्य वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जिनमें खैर, गूगल, झावेरी आदि झाड़ियां मुख्य हैं। पठारी इलाकों पर समतल क्षेत्र के नालों में प्रचुर मात्रा में घास पाई जाती है जो वन्य जीवों को समुचित मात्रा में भोजन प्रदान करती है। अभयारण्य में बाघ के साथ-साथ बघेरे, लकड़बग्घा, भालू आदि देखने को मिलते हैं। हरबीवोरस में चिंकारा, नील गाय, खरगोश, रीछ, आदि पाये जाते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।•

चिपको आन्दोलन के प्रणेता :

सुन्दरलाल बहुगुणा

क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार,
मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।

– अरविन्द सारस्वत
आर.ए.एस.

यह नारा सत्तर के दशक से हिमालय की वादियों में प्रतिध्वनित हो रहा है। देश के जन-जन को प्रेरित करने वाली इन पंक्तियों की रचना तो कुंवर प्रसून ने की है पर इसका वास्तविक मर्म समझाने में प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा की महती भूमिका रही है। जी हां, वही बहुगुणा जो विश्व स्तर पर पर्यावरण और वृक्षों की रक्षार्थ चिपको आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए विख्यात रहे हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश में कोविड-19 संक्रमण का उपचार लेते हुए 94 वर्षीय श्री बहुगुणा 21 मई, 2021 को अपनी अंतिम श्वास लेकर देवलोक को प्रयाण कर गये। देश ने एक बेहतरीन पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया।

श्री बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी, 1927 को उत्तराखंड के टिहरी तहसील के मारुदा गांव में हुआ था। उन दिनों देश में स्वतन्त्रता संग्राम अपने चरम पर था। मात्र तेरह वर्ष की अल्पायु में ही टिहरी के राजा की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में भाग लेते हुए श्री बहुगुणा ने अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया। उन्होंने लाहौर और वाराणसी से स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की एवं तदुपरांत पढ़ाई छोड़ आजादी के आंदोलन में कूद गए। देश में अधिकांश लोग बहुगुणाजी को चिपको आंदोलन की वजह से जानते हैं जो कि 1970 के दशक के आखिर में हुआ था पर सच्चाई यह है कि उन्होंने इससे पच्चीस वर्ष पूर्व से ही जन आंदोलनों में अपने को खपा दिया था।

महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध मुहिम छेड़ी। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए भी काम किया तथा साठ के दशक में शराब के खिलाफ चले आंदोलन में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित सर्वोदय अभियान में उनकी सक्रिय भूमिका रही । इसके माध्यम से वे ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। श्री बहुगुणा ने जीवनपर्यंत अहिंसक तरीके से कमजोर लोगों के लिए काम करने की ठानी और अपनी सीख को खुद के जीवन में उतारने का संकल्प लिया।

आजादी के बाद से ही हिमालय क्षेत्र में कई वन आंदोलन चल रहे थे। चिपको आंदोलन को उन आंदोलनों की सामूहिक परिणति कह सकते हैं। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले (अब उत्तराखंड) में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम 'चिपको' 'वृक्षों के आलिंगन' के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के

दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिये उनके चारों और मानवीय घेरा बनाया गया। श्री बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने सत्तर के दशक में गौरा देवी तथा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें बहुगुणा की भूमिका इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को संगठित किया और एक चेहरा देकर इसे पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। चिपको की सफलता के बाद श्री बहुगुणा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नवीन पहचान मिली।

नब्बे के दशक के शुरुआती सालों में उन्होंने 'हिमालय बचाओ' अभियान की शुरुआत की और टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन का आरंभ किया। बहुगुणा संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में बड़े बांधों और बिजली परियोजना के निर्माण के खिलाफ थे क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन झेलना पड़ता और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के भी बिगड़ने का भय था। बहुगुणाजी के कार्यों से प्रभावित होकर देश-विदेश में उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके काम को देखते हुये उन्हें प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार, शेर-ए-कश्मीर, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, आईआईटी से मानद डॉक्टरेट, पहल सम्मान, गांधी सेवा सम्मान, सांसदों के फोरम ने सत्यपाल मित्तल अवार्ड और भारत सरकार ने पद्मविभूषण से सम्मानित किया। पर्यावरण को स्थाई सम्पति मानने वाला यह महापुरुष एक प्रकार से 'पर्यावरण गांधी' बन गया।

आज जब दुनिया में उपभोग और तथाकथित विकास की नई परिभाषा गढ़ी जाने लगी है, तब सुन्दरलाल बहुगुणा के बहुत सारे विचार प्रकृति के बारे में ऐसे हैं जो दुनिया को आसन्न संकटों से निकाल सकते हैं। उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से इस बात को सत्तर-अस्सी के दशक में ही रखना शुरू कर दिया था कि बेतरतीब विकास योजनाओं से जल, जंगल और जमीन पर खतरा पैदा होने वाला है। हिमालय के बारे में उनका मानना था कि हिमालय बचेगा तो जीवन भी रहेगा। प्रकृति, पानी, पहाड़ और पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदना को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने चावल खाना छोड़ दिया था उनका मानना था कि धान की खेती में पानी की ज्यादा खपत होती है। वे कहते थे कि इससे वह कितना पानी का संरक्षण कर पायेंगे कह नहीं सकते, लेकिन प्रकृति के साथ सहजीविता का भाव हृदय में होना चाहिये। प्रकृतिपुत्र सुंदरलाल बहुगुणा जैसे यशस्वी पर्यावरण रक्षक नश्वर देह छोड़ने पर भी कभी 'मरते' नहीं। वे पर्वतों, नदियों, मिट्टी, वृक्षों की पत्तियों, फूलों और टहनियों में सदैव जीवित रहेंगे।

राज्य सरकार की अनूठी पहल

घर-घर वितरित होंगे औषधीय पौधे

– अनिल कुमार शाक्य
जनसम्पर्क अधिकारी, वन

राजस्थान में अब जन स्वास्थ्य रक्षण के साथ-साथ औषधीय पौधों का संरक्षण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही जन कल्याणकारी राज्य सरकार की अनूठी पहल के तहत राज्य के हर घर में औषधीय पौधे उपलब्ध करवाये जाएंगे। इस पहल के जरिए जहां एक ओर आमजन के स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा, वहीं वनों में पाई जाने वाली औषधियों और औषधीय पौधों का संरक्षण भी समुचित तरीके से हो सकेगा।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम बिश्नोई, वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख) श्रीमती श्रुति शर्मा के नेतृत्व में 'घर-घर औषधि योजना' को अमलीजामा पहनाया जाएगा। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।

'घर-घर औषधि योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों, विद्यालयों और औद्योगिक घरानों का भी सहयोग लेकर वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग के उप वन संरक्षक जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। प्रत्येक जिले में योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय टास्क फोर्स की ओर से प्रभावी कार्य योजना बनाकर किया जाएगा।

तुलसी

योजना के तहत पौध वितरण स्थलों का चिह्नीकरण, वितरण व्यवस्था, विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था, प्रचार-प्रसार की रणनीति, वितरण, अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्थाओं सहित सभी गतिविधियां विभागीय अधिकारियों के सहयोग से संचालित होंगी।

पांच वर्षों तक वितरित होंगे पौधे

राज्य में वर्ष 2021-22 से लेकर आगामी 5 वर्षों 2025-26 तक के लिए 'घर-घर औषधि योजना' लागू की जाएगी। 5 वर्षों के दौरान राज्य के लगभग एक करोड़ 26 लाख परिवारों (जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार) को चार प्रकार की औषधीय प्रजातियों तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे यानी कुल 8 पौधे थैलियों में दिए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को 5 वर्षों में तीन बार वन विभाग की ओर से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले वर्ष जिले के आधे परिवारों में से प्रत्येक को 8 पौधे दिए जाएंगे। अगले वर्ष शेष परिवारों में से प्रत्येक को 8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। यही प्रक्रिया चौथे और पांचवें वर्ष में दोहराई जाएगी जबकि तीसरे वर्ष में सभी

कालमेघ

परिवारों से संपर्क कर उन्हें भी 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। इस तरह कुल 5 वर्षों में तीन बार राज्य के सभी परिवारों को 8-8 यानी कुल 24 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पौधे वितरित करने के लिए बीजों और पौधारोपण सामग्री की व्यवस्था वन मंडल द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व की जाएगी।

जन आधार या आधार कार्ड से होगा संधारण

वन विभाग की पौधशालाओं में पौधे तैयार करने के बाद जिला

स्तरीय टास्क फोर्स के सहयोग से पौधे आमजन को उपलब्ध करवाए जाएंगे। पौध वितरण के समय लाभार्थी के जन आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड की जानकारी संधारित की जाएगी ताकि योजना के प्रबोधन और मूल्यांकन में आसानी हो सके। साथ ही औषधीय पौधों के वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।

वन महोत्सव में दिखेगी योजना की छाप

राज्य सरकार की इस महत्त्वपूर्ण योजना की छाप वन महोत्सव में भी दिखाई देगी। राज्यभर में इस वर्ष प्रस्तावित वन महोत्सव की थीम भी 'घर-घर औषधि योजना' रखी जायेगी। राज्य के समस्त जिलों और वन मंडलों के अधीन सभी फॉरेस्ट रेंज, तहसील, ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों में जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके पहले चरण में पौध वितरण कार्य होगा जबकि अक्टूबर से योजना का दूसरा चरण शुरु किया जाएगा। योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रबोधन और मूल्यांकन पर रहेगा जोर

'घर-घर औषधि योजना' की सफलता के लिए उसके प्रबोधन और मूल्यांकन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। वन विभाग की ओर से भी योजना के उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन और मूल्यांकन) को प्रभारी बनाया गया है।

योजना से होगा दोहरा लाभ

घर-घर औषधि योजना से आमजन को दोहरा लाभ होगा। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जीवनशैली में परिवर्तन जैसे कारणों से लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं। आयुर्वेद और स्थानीय परंपरागत ज्ञान व वनों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतों और निजी जमीनों के समीप उगाने से राज्य के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही उन्हें परंपरागत औषधियों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। इतना ही नहीं इन औषधियों के उपयोग से आमजन अपने और अपने परिवार के सदस्यों का रक्षण करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। सरकार की इस पहल से औषधीय पौधों का संरक्षण भी संभव हो सकेगा।

वर्तमान में क्यों जरूरी है औषधि योजना

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में जन स्वास्थ्य और जनहानि से बचने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सहित अन्य चिकित्सा पद्धतियों का भी इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे में घर-घर औषधि योजना का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्राचीन काल से लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों और उनसे बनी दवाओं का उपयोग करते आ रहे हैं। औषधीय पौधों के इन्हीं गुणों को

गिलोय

ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने योजना के जरिए औषधीय पौधे घर-घर पहुंचाने का निर्णय लिया है। वैसे भी राजस्थान के वनों और वनों के बाहर हरियाली वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की औषधीय प्रजातियों की उपलब्धता सदियों से रही है। इनका उपयोग भी आदि काल से आयुर्वेद और स्थानीय परंपरागत ज्ञान के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षण और चिकित्सा के लिए होता आया है। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जीवनशैली में परिवर्तन जैसे कारणों से स्थानीय लोग अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते रहते हैं। राज्य सरकार की इस पहल से आयुर्वेद तथा स्थानीय परंपरागत ज्ञान और वनों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, क्षेत्रों और निजी जमीनों के समीप उगाने में सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही विभाग की ओर से योजना का व्यापक रूप से प्रचार कार्य करने के लिए राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी में कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग भी इसमें सहयोग करेंगे।•

अश्वगंधा

पर्यावरण से जुड़े राजस्थान के राज्य प्रतीक

– शुभ्रा शर्मा
शोध अध्येता

रंगीलो राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान राज्य की हर विशेषता अनूठी है। यहां पशु-पक्षी से लेकर फूल और पेड़ों तक को राज्य प्रतीक का दर्जा दिया गया है। जिनका वर्णन निम्नांकित है-

राज्य पुष्प-रोहिड़ा

रोहिड़ा फूल को राजस्थान के राज्य पुष्प के रूप में जाना जाता है। इस पुष्प का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडूलेटा है। इसके अलावा इसे राजस्थान की मरुशोभा, मरुस्थल के सांगवान और मारवाड़ टीक के रूप में भी प्रसिद्धि हासिल है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर, 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया। प्रदेश के जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर सहित अन्य क्षेत्रों में रोहिड़ा का पुष्प पाया जाता है।

राज्य पशु-ऊंट

ऊंट को पालतू और चिंकारा को जंगली श्रेणी में राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा मिला है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है जबकि इसे छोटा हिरण के नाम से भी जानते हैं। यह एंटीलॉग प्रजाति का मुख्य जीव है। जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि वर्ष 1981 में मिली। जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है। यह शर्मीला जीव है और राजस्थान के मरु भाग में इसकी बहुतायात है।

दूसरे राज्य (पालतू) पशु के रूप में ऊंट की उपयोगिता यातायात के साधन और कृषि कार्यों सहयोगी पशु के रूप में सदियों से बनी हुई है। इसे रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जानते हैं। राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा देकर 19 सितंबर, 2014 को इसकी घोषणा की। राज्य के बीकानेर जिले में भारत की

एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर जिले और सबसे कम प्रतापगढ़ में मिलते हैं। प्रदेश में मिलने वाली प्रमुख नस्लों में गोमठ, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी शामिल हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। माना जाता है कि राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊंटों की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला और उनकी खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कूंपी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में भी ऊंटों का विशेष महत्त्व रहा है। बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह

ने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला के नाम से ऊंटों की सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को (पहले और दूसरे विश्व युद्ध में) देखते हुए इसे बीएसएफ में शामिल किया गया। इसके अलावा राजस्थान में लोकप्रिय श्रृंगार गीत गोरबंद भी ऊंटों से संबंधित है। ऊंट के नाक में डाले जाने वाले लकड़ी से बने आभूषण को गिरबाण कहते हैं।

राज्य पक्षी–गोडावन

गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा हासिल है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। शर्मीला पक्षी, सोहन चिड़िया, हुकना और गुरियान इसके अन्य नाम हैं। वर्ष 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। जैसलमेर के मरु उद्यान से लेकर सोरसन (बारां) और अजमेर के सोखलिया क्षेत्र में गोडावण मुख्य रूप से पाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकट श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। यह सर्वहारी पक्षी है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा और बेर आदि शामिल हैं। इसके साथ ही यह टिड्डे, सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है।

राज्य वृक्ष–खेजड़ी

खेजड़ी यानी शमी के पेड़ को राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा प्रांत में खेजड़ी को जंटी, तमिल भाषा में पेयमेय, कन्नड़ में बन्ना–बन्नी, सिंधी भाषा में छोकडा, बिश्नोई भाषा में शमी और स्थानीय भाषा में सीमलो भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसके पेड़ से फल के रूप में प्राप्त होने वाली सांगरी को सुखाकर सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों को लूम भी कहा जाता है, जिसका उपयोग चारे में होता है। विजयदशमी (दशहरे) के दिन शमी का पूजन करने का धार्मिक महत्व है। लोक देवता गोगाजी और जुझार बाबा के मंदिर/थान खेजड़ी के नीचे ही बने होते हैं। 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला–पुरुषों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी। इस उपलक्ष में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष इस दिन को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 में पर्यावरण हेतु अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार शुरु किया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है।•

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्त्वपूर्ण दिवस

2 फरवरी– विश्व नम भूमि दिवस
21 मार्च– विश्व वानिकी दिवस
22 मार्च– विश्व जल दिवस
18 अप्रैल– विश्व विरासत दिवस
22 अप्रैल– विश्व पृथ्वी दिवस
3 मई– विश्व ऊर्जा दिवस
5 जून– विश्व पर्यावरण दिवस
17 जून– विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस
जुलाई–अगस्त (वर्षा पर निर्भर) वन महोत्सव
11 जुलाई– विश्व जनसंख्या दिवस
16 सितंबर– विश्व ओजोन दिवस
2 से 8 अक्टूबर– वन्य जीव सप्ताह
4 अक्टूबर– विश्व प्राणी कल्याण दिवस
6 अक्टूबर– विश्व हैबिटेट दिवस
3 दिसम्बर– राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस
14 दिसम्बर– ऊर्जा संरक्षण दिवस
29 दिसम्बर– विश्व जैव विविधता दिवस
श्रावण कृष्ण अमावस्या– हरियाली अमावस्या
श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार– वन सोमवार

गांव और ढाणियों में हर घर नल कनेक्शन

– मनमोहन हर्ष
उप निदेशक, जनसम्पर्क

जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 'हर घर नल कनेक्शन' देकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यों को युद्धस्तर पर सम्पादित करने के निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पूरे प्रदेश में 'हर घर नल कनेक्शन' के लक्ष्यों को अमलीजामा पहनाने की सघन मुहिम छेड़ रखी है।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना की कार्यान्विति में अधिक सतर्कता बरतते हुए गति लाने और हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को पूरा करने पर बल दिया है, जिससे यह मिशन प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हो। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला के स्तर पर भी जल जीवन मिशन के कार्यों की समयबद्ध समीक्षा की जा रही है। डॉ. कल्ला का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल कनेक्शन' के लक्ष्यों को वर्ष 2024 तक पूर्ण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जेजेएम के कार्यों को गम्भीरता लेकर 'टीम भावना' से कार्य और निर्धारित टाइमलाइन की पालना करते हुए 'हर घर नल कनेक्शन' के लक्ष्यों को साधा जाए। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व एवं जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला के निर्देशन में प्रदेश में जल जीवन मिशन की कार्यान्विति के भागीरथी प्रयास आने वाले समय में प्रदेश के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में 'हर घर नल कनेक्शन' की सौगात से ग्रामीण जन जीवन की कायापलट करेंगे।

चरणबद्ध प्रयासों की बानगी

जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल कनेक्शन' जारी करने की पहली पायदान पर जिलों के गांवों में नल कनेक्शन से वंचित घरों के लिए ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव (डीपीआर) तैयार किए जाते हैं। इनको राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी-एसएलएसएससी) में मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

वर्ष 2021–22 का एक्शन प्लान

जल जीवन मिशन में प्रदेश के 43 हजार 362 गांवों के 1करोड़ 1 लाख 32 हजार घरों में से अब तक करीब 20 लाख में 'हर घर नल कनेक्शन' जारी किए जा चुके हैं। इसमें से 6 लाख 81 हजार नल कनेक्शन गत वित्तीय वर्ष में जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना (एन्यूअल एक्शन प्लान) में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 30 लाख 'हर घर नल कनेक्शन' देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 2022-23 में 35 लाख तथा 2023-24 में 16 लाख 75 हजार घरों में नल कनक्शेन देने की रूपरेखा तैयार की गई हौ इसके अलावा प्रदेश के 12 हजार गांवों के सभी घरों में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी इस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। गुणवत्ता प्रभावित 1950 आबादियों में भी हर घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश में इस साल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष श्रेणी के जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) धौलपुर, जैसलमेर, बारां, करौली और सिरोही में 3895 ग्राम एवं ढाणियों में 3 लाख 32 हजार 852, अकाल से प्रभावित एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों में 5020 गांवों में 10 लाख 56 हजार 450, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी 186 गांवों में 36 हजार 100 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में 4920 गांव एवं ढाणियों में 8 लाख 95 हजार 'हर घर नल कनेक्शन' देने का लक्ष्य तय किया गया है।

महिला मुखिया के नाम कनेक्शन को वरीयता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारो को जारी किये जा रहे घरेलू जल संबंधों को परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही जारी किये जाने को वरीयता देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत गांवों में स्थानीय समुदायों विशेषकर महिलाओं को जल योजनाओं के प्रबंधन में भागीदार बनाये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे प्रदेश की मातृशक्ति गांवों में जल जीवन मिशन की गतिविधियों का नेतृत्व कर सकेगी। जेजेएम के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 10 से 15 तक सदस्य शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के निर्णय के बाद जलदाय विभाग की ओर से ग्राम समितियों में 25 प्रतिशत तक पंचायत के निर्वाचित सदस्य तथा 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को शामिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा शेष 25 प्रतिशत सदस्यों में गांव के कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के प्रतिनिधियों को उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर शामिल किया जाएगा। •

महिला सशक्तीकरण के अभिनव प्रयास

– हितेश भारद्वाज
पत्रकार

देश में लगातार बढ़ रहे महिला उत्पीड़न कुछ हद तक रोकने और महिलाओं को उनके आत्मसम्मान बनाये रखने के सपने को एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका, बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सीखा कर साकार कर रही है। साथ ही साथ शिक्षा में नवाचारों के माध्यम से नौनिहालों को शिक्षा देने का कार्य कर अपने शिक्षक होने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है।

अलवर जिले के राजगढ़ उपखण्ड के खरखड़ा गांव के राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका आशा सुमन आत्मरक्षा के गुर के बूते अपनी पहचान अपने विभाग सहित पुलिस विभाग और दिव्यांग बच्चों में बना चुकी है। इस सकारात्मक प्रयास के लिए हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इन्हें जिला प्रशासन सहित राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा गया है।

अलवर पुलिस प्रशासन द्वारा महिला शक्ति कार्यक्रम में बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया, उसमें भी आशा सुमन ने भागीदारी निभाई और सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा करना सिखाया। अब आशा सुमन ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से अन्य राज्यों के लोगों को भी आत्मरक्षा का ऑनलाइन प्रशिक्षण देने में जुटी है।

दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देकर हुई सुखानूभूति–

आशा सुमन बताती है कि अपने कार्य में उन्हें सबसे अच्छी अनुभूति तब हुई, जब उन्होंने शिक्षा परिषद में दिव्यांग बच्चों को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण दिया। बच्चों को अपनी आत्मरक्षा जैसे गुड टच और बैड टच में अन्तर के अलावा किससे शिकायत की जाये, अपनी रक्षा किस प्रकार की जाये इन बातों का प्रशिक्षण दिया गया। आशा सुमन द्वारा थानागाजी में हुई घटना के बाद विभाग की परमिशन लेकर वहां जाकर बालिकाओं को आत्म रक्षा के गुर सिखाये, जिससे वे विद्यालयों से जुड़ें और भयमुक्त होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

लॉकडाउन के दौरान बनाई 208 एनिमेटेड कार्टून फिल्म

लॉकडाउन के दौरान एक-दूसरे से सम्पर्क में न आने के कारण से लोगों तक पहुंच नहीं पाई, इस दौरान उन्होंने बच्चों के लिए कार्टून फिल्में बनाई और उसमें पावर गर्ल आशा का कार्टून करेक्टर ईजाद किया, जो बच्चों को मोटिवेशन दे सके और उसके माध्यम से आत्मरक्षा करना सीख सके। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन के तहत इनके 50 से अधिक वीडियो का प्रसारण डीडी राजस्थान चैनल पर किया जा चुका है और इन्हें दीक्षा पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में इनके द्वारा आत्मरक्षा विषय पर पुस्तक भी लिखी है, जिसे इन्होंने बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। अपने विद्यालय में बच्चों के खिलौना बैंक की स्थापना के साथ-साथ उन्हें निशुल्क स्टेशनरी उपलब्ध कराने का कार्य भी आशा सुमन कर रही है।•

यादों में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया

– गोविन्द शर्मा
पूर्व सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार व हरियाणा के पूर्व राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया का गुरुग्राम के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण से 19 मई को निधन हो गया था। वे लोकप्रिय जन प्रतिनिधि रहे। स्वर्गीय पहाड़िया दलित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिये हमेशा समर्पित रहे एवं स्व. जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे ।

भरतपुर जिले के भुसावर में स्वर्गीय पहाड़िया का जन्म हुआ था। मास्टर आदित्येन्द्र जी ने जब सन् 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से उनकी भेंट कराई तो उस दौरान स्व. पहाड़िया ने बेबाक़ी से कहा था कि बाकी तो सब ठीक है किन्तु दलितों को ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। बाद में पं. नेहरू ने उन्हें 1957 में सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव लड़ने को कहा। स्व. पहाड़िया ने राजस्थान में 13 माह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में शराब बन्दी लागू की थी ।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 20 मई, 2021 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय श्री पहाड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म 15 जनवरी, 1932 को हुआ। उन्होंने एम.ए. व एल.एल.बी. तक की शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 से 1962, 1967 से 1971, 1971 से 1977 एवं 1980 में लोकसभा सदस्य रहे। 1965 से 1966, 1966 से 1967 तक वे राज्यसभा सदस्य रहे। इस दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं उपमंत्री भी रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1990 से 1992 एवं 2003 से 2008 तक क्रमशः सातवीं, आठवीं, नवीं एवं बारहवीं विधानसभा के सदस्य रहे। श्री पहाड़िया 6 जून, 1980 से 14 जुलाई, 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 3 मार्च, 1989 से 2 फरवरी, 1990 तक बिहार एवं 27 जुलाई, 2009 से जुलाई, 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में भी स्वर्गीय श्री पहाड़िया ने प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय पहाड़िया जी ने अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं समाज के वंचित वर्गों के उत्थान एवं कल्याण हेतु महत्त्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय योगदान दिया है।

''श्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी सेवाएं प्रदेशवासियों में चिरस्मरणीय रहेंगी।''

– श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री–राजस्थान

पौधारोपण अभियान-पंचवटी व मरु पंचवटी

– गुलाब बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार

छाया : डॉ. देवदत्त शर्मा

पानी की उपलब्धता वाले इलाकों में पीपल, बरगद, बेल पत्र, आंवले तथा अशोक के पौधे तथा शुष्क क्षेत्र में खेजड़ी, बोरड़ी, रोहिड़ा, जाल एवं गूंदी के पौधे लगाने वाली वृक्षारोपण की योजना का नामकरण क्रमशः पंचवटी और मरु पंचवटी के रूप में किया गया।

एक दशक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री एस.एस. बिस्सा ने विशेषकर पौधारोपण के लिए मनरेगा कार्यों की शुरुआत पंचवटी एवं मरु पंचवटी नामक अनूठी योजना से की।

दरअसल बड़े पैमाने पर इस पंचवटी वृक्षारोपण योजना को बूंदी, जालौर व नागौर में मूर्त रूप दिया गया। लेकिन इसका बीजारोपण जोधपुर में केन्द्रीय कारागृह से हुआ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समाजसेवी डी.सुब्बाराव के साथ पंचवटी का अवलोकन किया और वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के साथ अशोक का पौधा भी लगाया। पंचवटी में पांच पौधों का रोपण किया गया।

पंचवटी में पांच पौधे दस-दस मीटर की दूरी पर लगाये जाते थे। पूर्व दिशा में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में बेल पत्र, दक्षिण में आंवला तथा आग्नेय कोण में अशोक का पौधा लगाया जाता था। इनके मध्य में ध्यान अथवा विश्राम चौकी बनाई जाती थी ताकि पर्यावरण प्रेमी इसका उपयोग कर सकें। पंचवटी के साथ अभियान के रूप में लगभग एक हजार फलदार पौधे लगाये गये।

पंचवटी के समीप स्कूल नोटिस बोर्ड पर लिखा गया था कि बच्चे पेड़ों से तोड़ कर फल खायेंगे। फलों का वाणिज्यिक उपयोग नहीं होगा। आज भी इसका पालन हो रहा है। एक दशक पूर्व संचालित इस पौधारोपण अभियान के पंचवटी स्थलों पर अब पेड़ों की संख्या बढ़ गई है तथा सुरक्षा के लिए चौकीदार रखा गया है। वन विभाग ने भी इस योजना को अपना लिया। नागौर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर अलग अलग हिस्सों में सौ-सौ पेड़ लगवाये गये जिन्हें सहस्त्र वृक्ष स्थल कहा गया।

पंचवटी में शामिल पांचों प्रकार के पेड़ प्रकृति चक्र के साक्षी माने जाते हैं। जिस मौसम में ये पेड़ एवं फलीभूत होते हैं, तब उस दिशा में हवा चलती है और वृक्ष बारी-बारी से फल-फूल से लदे रहते हैं। इससे पक्षियों को वर्ष पर्यन्त भोजन सुविधा सुलभ होती है। प्राणवायु के साथ ही पेड़ लोगों को आसरा देते हैं। मरु पंचवटी थार मरुस्थल के जन-जीवन में लाभकारी भूमिका निभा रही है।

हमारे शास्त्रों की अवधारणा में एक वृक्ष को सौ पुत्रों के समान माना गया है। एक वृक्ष में लगभग एक किलोमीटर के दायरे में शुद्ध प्राणवायु फैलाने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ते प्रदूषण एवं तापमान में अभिवृद्धि के चलते सघन पौधारोपण की अनिवार्यता अनुभव की जा रही है। भूमि के एक तिहाई हिस्से में वनों के अस्तित्व को मापदण्ड माना गया है। विशेषज्ञों ने दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए एक हजार अरब वृक्षों की आवश्यकता बताई है जो वायुमण्डल में लगभग 810 अरब टन कार्बनडाई ऑक्साइड को अवशोषित कर जीने की राह को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मानसून में पंचवटी और मरु पंचवटी योजना के अनुरूप अब भी सघन पौधारोपण को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है।•

जयपुर में कला का आंगन

– बनवारी लाल यादव
जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान कला एवं सांस्कृतिक विविधता से भरा प्रदेश है। यहां की माटी में लोकगीतों की मिठास है, तो हवा में तीज त्योहारों का उल्लास। राजस्थान अपनी विविधतापूर्ण भाषा, रीति-रिवाजों और कला-शैलियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। राजस्थान की इसी विविधता को यहां के लोक-कलाकारों ने सदियों से सहेज कर रखा है। यूं तो राजस्थान के हर कोने में लोक कलाकार मिल जाएंगे लेकिन जयपुर की कलाकार कॉलोनी इन सबसे अलग ही है। राजस्थान पुलिस अकादमी के पास बसी इस कॉलोनी के कलाकारों ने ना केवल राष्ट्रीय, अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का लोहा मनवाया है, बल्कि विविध कलाओं के उपासक दिन-रात यहां कला साधना में लगे रहते हैं।

यहां की तंग गलियों और छोटे- छोटे मटमैले घरों में राजस्थानी कला के बड़े-बड़े फनकार हुए हैं। राजस्थानी लोक नृत्य कच्छी घोड़ी का अभ्यास करते हुए कलाकार हों, या फिर तेरह ताली और मजीरों की झंकार पर कदम थिरकाती महिला कलाकार...इन सभी को एक ही परिसर में पाकर कोई भी अभिभूत हो सकता है। ये कलाकार राजस्थान की कला और संस्कृति को देश और दुनिया में बढ़ावा देने और लोगों का मनोरंजन करने के लिए दिन-रात रियाज़ करते हैं। चंग और ढ़प की ताल के बीच यहां के कलाकारों ने बॉलीवुड फिल्मों से लेकर विदेशी धरा पर राजस्थान की लोक कलाओं और संस्कृति का परचम लहराया है। यहां की प्रतिभाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित अनेक राजनेताओं से कला का सम्मान पाया है। यहां के कलाकारों ने हिंदी फिल्मों में भी लोकनृत्य किए हैं।

घूमर, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी, चंग, लंगा पार्टी, रास डांडिया, मजीरा, चकरी, चरी, मयूर, गैर, भवाल, भवई, कालबेलिया और कठपुतली नृत्य यहां के कलाकारों में रचा बसा है। यहां के कलाकारों ने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, लुसाका, मॉरीशस, सिंगापुर आदि देशों में लोकनृत्यों का कमाल दिखाया है।

राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाने वाली पद्मश्री गुलाबो का भी जयपुर की इस कलाकार कॉलोनी से गहरा नाता है। कोरोना महामारी के दौर में गुलाबों ने एक लोकगीत भी तैयार किया है, जो लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। अरररर..र... मैं तो नाचूं और गाऊं, कि मैं तो नांचू और गाऊं कोरोना ने भगाऊं रे, अरररर..र.. मैं तो हाथ धोऊं और न्हाऊं, कोरोना ने भगाऊं रे...। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कलाकार कोरोना वायरस और इसके टीकों के बारे में लोगों में जारूकता फैला रहे हैं।

आधुनिक परिवेश में सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने का कार्य कलाकार करते हैं। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा, जिसमें त्याग, बलिदान और अनुशासन के आदर्श निहित हैं, वह मात्र इन लोक कलाओं में निहित हैं। मीना सपेरा ने करीब 50 देशों में अपनी कला का जादू बिखेरा है।

अमेरिका में कालबेलिया नृत्य का जलवा दिखा चुकी रामूड़ी सपेरा और सोफी सपेरा का जन्म भी इसी कलाकार कॉलोनी में हुआ। यहां से निकलकर अपनी कला का जादू देश- विदेश में बिखेरने वाले कलाकारों में कमली सपेरा, राखी पूनम सपेरा, रघू ढेला, तेजपाल नागौरी, राधेश्याम राणा, कैलाश नाथ, श्रवण नाथ आदि के नाम प्रमुख है।•

कलाकारों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को सम्बल देने के लिए उन्हें 5000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। इस संवेदनशील निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद करीब दो हजार कलाकारों को राहत मिल सकेगी। कोविड महामारी के समय में राजस्थान के कलाकारों को 5000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता कमजोर कलाकारों को सम्बल प्रदान करेगी। इससे करीब दो हजार कलाकारों को सहायता मिल सकेगी। यह सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से प्रदान की जायेगी। सरकार के मुताबिक इस वर्ष के राज्य बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान कलाकार कल्याण कोष में किया गया है।

"राजीव गांधी खेल रत्न" पुरस्कार

– एन.के. मिश्रा
पूर्व उपनिदेशक, जनसम्पर्क

भारत सरकार का खेल मंत्रालय अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलकूद को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को कुल मिलाकर हर वर्ष सात प्रतिष्ठित सम्मान देती हैं। इसके अन्तर्गत राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यान चंद, तेनजिंग नोर्गे, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन और खेलकूद में अव्वल विश्वविद्यालय हेतु मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 'राजीव गांधी खेल रत्न' पुरस्कार वर्ष 1991-92 से दिया जा रहा है। गत करीब तीन दशकों में अब तक प्रमुख 14 खेलों में 17 महिलाओं सहित कुल 43 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है। इनमें राजस्थानी श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और श्री देवेन्द्र झाझडिया भी हैं। श्री राठौड़ ओलम्पिक निशानेबाजी के रजत पदक विजेता और श्री देवेन्द्र पैरालंपिक के कीर्तिमान धारी है।

खेलों में सर्वाधिक 8 निशानेबाजों ने पुरस्कार पाया है तो आधा दर्जन एथालीटों ने भी बाजी मारी है एवं पांच पहलवानों ने भी दंगल जीता है। इनके अलावा 4 दिग्गज क्रिकेटरों तथा 3 हॉकी महारथियों और भारोत्तोलकों ने यह नामी गिरामी इनाम पाया है। यह विलियर्ड मुक्केबाजी, टेनिस और पाल नौका में दो-दो और शतरंज, जिमनास्टिक, टेबिल टेनिस में एकल विजेता ही है। इनमें विश्व विजेता का करिश्मा कई बार करने वाले विश्वनाथन आनंद जिमनास्टिक ओलम्पिक में जरा से अन्तर से पदक चूकी दीपा कर्मकार और टेबल टेनिस सिद्धहस्त मनिका बत्रा हैं। विलियर्ड में गीत सेठी और पंकज आडवाणी ने बड़ी टेनिस पर रंग-बिरंगी गेंदों को छड़ी से नचाकर अपनी श्रेष्ठता जताई है तो विजेन्द्र एवं बॉक्सर मेरीकॉम के फौलादी प्रहारों से विजयश्री का वरण किया है। काफी लम्बे समय से टेनिस खेल रहे लियण्डर पेस और ओलम्पिक की तैयारी में जुटी सानिया मिर्जा ने भी तमगा पाया है खेल रत्न का। पाल नौका में होमी डी मोती वाला और पी के गर्ग को भी खेल रत्न मिल चुका है। बेडमिन्टन में गुरु-शिष्या परम्परा में पुलेला गोपीचन्द और ओलम्पिक रजत पदक जीतने वाली पी वी सिन्धु के अलावा कांस्य जीतने वाली सायना नेहवाल है। हॉकी के स्वर्ण युवा में धनराज पिल्लई और जुझारु सरदारसिंह तथा महिला कप्तान रानी है। भारोत्तोलन की तीनों महिला प्रवीण मल्लेश्वरी, कुंजूरानी, मीरा चानू ने देश दुनिया में नारी शक्ति के तेवर दिखाये हैं। लोकप्रिय खेलों के लिटिल मास्टर सचिन पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी, वर्तमान में नेतृत्व सम्भाल रहे विराट कोहली के साथ पिच पर पहुंचते ही गेंद का कचूमर निकालने वाले रोहित शर्मा ने भी पुरस्कार पाया है।

कुश्ती में ओलम्पिक कांस्य विजेता साक्षी मलिक, हरियाणवी विनेश और सुशील के अलावा योगेश्वर तथा बजरंग ओलम्पिक तैयारी में दिनरात खून पसीना एक कर रहे हैं। एथलेटिक्स में दो दिव्यांगों देवन्द्र तथा मरियप्पन सहित महिला एथलीटों में भी पैराएथलीट दीया मलिक फर्राटा क्वीन ज्योतिमय सिकन्दर लम्बी कूद में माहिर अंजू बॉबी जॉर्ज तथा वीना मोल है। निशानेबाजी के सर्वाधिक 8 खेल रत्नों में महिला शूटर अंजलि भागवत, स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिन्द्रा रजत जीतने वाले राज्यवर्धन, कांस्य विजेता गगन नारंग, मानव जीत सिंह, रोशन सोढ़ी तथा जीतू राय भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।•

खेल	पुरुष	महिला	कुल
एथलेटिक्स	2	4	6
बैडमिन्टन	1	2	3
बिलियर्ड	2	0	2
मुक्केबाजी	1	1	2
शतरंज	1	0	1
क्रिकेट	4	0	4
जिमनास्टिक	0	1	1
हॉकी	2	1	3
टेनिस	1	1	2
निशानेबाजी	7	1	8
टेबिल टेनिस	0	1	1
भारोत्तोलन	0	3	3
कुश्ती	3	2	5
पाल नौका	2	0	2

छाया : डॉ. कमलेश शर्मा

वीर योद्धा महाराणा प्रताप

महाराणा प्रताप जयन्ती 13 जून

– गीता यादव
स्वतन्त्र पत्रकार

महाराणा प्रताप का जिक्र आते ही एक महान वीर योद्धा का चित्र आंखों के सामने उभरता है, जिन्होंने उस समय आक्रांताओं को चुनौती दी और उनके गलत इरादों को पस्त किया। प्रताप ऐसे शूरवीर थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा और आजादी के लिए ताउम्र लड़ते रहे। अपने जीवन में तमाम कष्ट सहते हुए भी उन्होंने पूरे देश के सामने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और एक सच्चे देशभक्त की मिसाल पेश की और भारत की धरती को गौरवान्वित किया।

महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। वह उदयसिंह और महारानी जैवंता बाई के बेटे थे। उन्हें बचपन में किका नाम से पुकारा जाता था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपने महान व्यक्तित्व से समकालीन राजनीति को नई दिशा देकर जिन मूल्यों की स्थापना की, निश्चित रूप से वे मानव जाति के लिए कल्याणकारी साबित हुए हैं। उनके जोश और होश ने मेवाड़ी सरदारों में नव चेतना और स्फूर्ति का संचार किया।

छाया : सौरभ

मेवाड़ की आन-बान और शान के रखवाले मेवाड़ी शेर ने अपने बुद्धि कौशल से दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर की रातों की नींद हराम करते हुए उनकी महत्त्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने में जो कामयाबी हासिल की, उनकी कीर्ति पताका को दोगुना कर दिया। स्वतंत्रता की जिजीविषा ने उस महामानव को सदा के लिए अमर बना दिया।

महाराणा प्रताप अपने कालखंड के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। जातीय जड़ता में जकड़े हुए मध्यकालीन युग में प्रताप ने अपनी सेना में अछूत समझे जाने वाले दलित लोगों को न केवल शामिल किया बल्कि उन्हें सेना की अगली कतार में चलने का गौरव भी प्रदान किया। इतना ही नहीं तमाम अवरोधों के बावजूद सामाजिक समरसता में एक कदम बढ़ाते हुए अफगान पठान हकीम खां के दल को अपने हरावल दस्ते की कमान सौंपी। बाल्यकाल से ही उन्होंने भीलों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उनके साथ पंगत में बैठकर खाना खाया। ढूंढने पर भी कोई ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है जिसमें प्रताप ने कभी किसी के साथ जाति, पंथ, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया हो। यह इंसानियत की सबसे बड़ी कसौटी है।

महाराणा प्रताप को स्थापत्य, कला, भाषा और साहित्य से भी लगाव था। वे विद्वान कवि थे। उनके शासनकाल में विद्वानों और साहित्यकारों को आश्रय मिला। उनकी उदारता और दृढ़ता का सिक्का शत्रुओं तक ने माना। इंसान तो इंसान जानवर भी उनसे प्यार करते थे। घोड़े चेतक ने उनके ऊपर जान न्यौछावर कर दी थी। अंग्रेजी हुकूमत से स्वाधीनता हेतु संघर्षरत अनेक महान् क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे महाराणा। उनकी मृत्यु 29 जनवरी, 1597 को उनकी राजधानी चावंड में हुई। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, साहस पराक्रम और त्याग का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।

हल्दी घाटी जहां अब खिलते हैं गुलाब

राजसमंद का हल्दी घाटी क्षेत्र जो कभी खून से लाल हुआ था, अब इस घाटी के गुलाबों की खुशबू देश-विदेश को महका रही है। यहां चैत्र महीने में गुलाब की खेती की जाती है, इसलिए इन्हें चैत्री गुलाब भी कहा जाता है। इन गुलाबों की खासियत यह है कि इन पर एक ही बार गुलाब के फूल आते हैं। इन गुलाबों से दवाइयां और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। •

मेरा गांव – मेरी जिम्मेदारी

मेरा आंगन, मेरा गांव
रहे स्वस्थ इसकी छांव

राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, उप–प्रधान, प्रधान, उप–जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उप–सभापति, सभापति, डिप्टी मेयर, मेयर, विधायक और संसद सदस्य से निवेदन

- शहर के साथ गांव में भी कोरोना का विकराल रूप हमारे सामने है
- बच्चों, युवाओं एवं गर्भवती महिलाओं में संक्रमण की तीव्रता चिंताजनक है
- मरीजों में हाई फ्लो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है

खतरा आपके द्वार पर है, लापरवाही अत्यन्त घातक है

- विषम चुनौतियों में जनप्रतिनिधियों का दायित्व और भी बढ़ जाता है
- समय की पुकार है कि आप अपने-अपने गांव और क्षेत्रों की पूर्ण जिम्मेदारी लें
- एक-एक जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के लिए लक्ष्मण रेखा खींचकर सुरक्षा चक्र बनाएं

अब यही लेना होगा संकल्प, नहीं है कोई विकल्प

- ☞ गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला निगरानी समितियां बनाएं
- ☞ सारे आयोजन, मेल-मिलाप बंद रखें
- ☞ हल्की खांसी, जुकाम, बुखार पर मरीज को आइसोलेशन में रखें, चिकित्सक को दिखाएं
- ☞ घर-घर सर्वे कराएं
- ☞ मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाएं
- ☞ स्वयं भी जागरूक हों, परिवार और समाज को भी जागरूक करें

शहरवासी भी गांव से आए मरीज की आगे बढ़कर मदद करें।

हम सभी जाति, धर्म, विचारधारा से ऊपर उठकर मानव मात्र के लिए आगे आएं।

समाज का प्रत्येक व्यक्ति, आमजन जिसके मन में मानव–मात्र के प्रति कल्याण का भाव है, मानवता की सेवा के लिए एक साथ मिलकर काम करें। यह मानवता का धर्म निभाने का समय है क्योंकि यह पता नहीं है कि यह महामारी कब–किसको संक्रमित करेगी।

सरकार का कोई भी प्रयास आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता।

आप सभी, आज से और अभी से प्रारम्भ करें यह अभियान 'मेरा गांव – मेरी जिम्मेदारी'।

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

हम भी निभाएंगे हमारी जिम्मेदारी

हनुमानगढ़ विशेष

‘राजस्थान सुजस’ राज्य सरकार का मुख-पत्र है। जून, 2021 के अंक से राजस्थान सुजस को हम प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही इस अंक को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए हनुमानगढ़ जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरूआत की जा रही है। जिले में विधायक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरपंच, उपसरपंच, वार्डपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद, सहकारी समितियों के व्यवस्थापक, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, राजकीय महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, समाज कल्याण छात्रावास, राजकीय पुस्तकालय, औद्योगिक संस्थान, होटल, जिला मुख्यालय के राजकीय कार्यालय, ब्लॉक स्तर के राजकीय कार्यालय, पुलिस, प्रशासन, न्यायिक अधिकारीगण, साहित्यकार, पत्रकार, व्यापारिक संस्थान, धार्मिक व सामाजिक ट्रस्ट, स्वयं सेवी संस्थाएं, गणमान्य नागरिकगण, आंगनबाड़ी केन्द्र, निजी विद्यालय, राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीएचसी, पीएचसी, एचएचसी, आयुर्वेदिक औषधालय आदि को राजस्थान सुजस पत्रिका भिजवाई जा रही है। इस पत्रिका का विस्तार हनुमानगढ़ जिले से आरम्भ किया जा रहा है। हनुमागढ़वासियों के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि जिले में आठ हजार 307 स्थानों पर राजस्थान सुजस इस माह से पहुंचेगी। इस कार्य में हनुमानगढ़ जिले के सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुरेश विश्नोई का सहयोग आशानुरूप रहा। श्री विश्नोई और उनके सहयोगियों को राजस्थान सुजस की ओर से हार्दिक धन्यवाद।

(डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा)
सम्पादक

हनुमानगढ़ : विहंगम दृश्य

– सुरेश विश्नोई
जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़

नोहर में खुलेगा नहरी पानी सुरक्षा पुलिस थाना

राज्य में पहली बार नहरी पानी की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस थाना हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में खुलने जा रहा है। गृह (ग्रुप-2) विभाग ने 1 जून 2021 को नहरी पानी चोरी रोकने के लिए अलग से पुलिस थाना खोलने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। थाना भादरा एवं नोहर विधानसभा क्षेत्र में नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना, नोहर के रूप में जाना जाएगा। नोहर विधायक श्री अमित चाचाण ने नहरी पानी चोरी का मुद्दा सरकार के प्रत्येक प्लेट फॉर्म पर उठाया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस संबंध में संपूर्ण पत्रावली सौंपी थी। नोहर विधायक श्री चाचाण मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए बताते हैं कि नहरी पानी चोरी रोकने को लेकर अलग से थाना खुलने के बाद भादरा एवं नोहर विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही सिंचाई पानी चोरी की समस्या का अब स्थाई समाधान हो सकेगा। गृह विभाग की ओर से नव स्वीकृत सिंचाई पुलिस थाने में 1 सीआई के अलावा 5 एसआई, 6 एएसआई, 8 कांस्टेबल के अलावा 40 कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए गए हैं नव गठित पुलिस थाना में 1 जीप व 2 मोटरसाइकिल भी स्वीकृत किए गए हैं।•

सौजन्य : सी.डेजर्ट रैडर्स क्लब, हनुमानगढ़

इंदिरा गांधी नहर के नीचे से गुजरती हुई घग्घर

मसीता वाली हैड, टिब्बी

कालीबंगा संग्रहालय

गोगामेड़ी मंदिर

गुरूद्वारा साहेब श्री सुखासिंह-मेहताब सिंह

ब्रह्माणी माता मंदिर

इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद पंजाब में पहली बार हुआ रिलाइनिंग का कार्य

करीब 300 क्यूसेक पानी सीपेज नहीं होने से प्रति दिन बचेगा

60 दिन की ऐतिहासिक नहरबंदी, 438 करोड़ खर्च और बदल गई इंदिरा गांधी नहर की 70 किलोमीटर की तस्वीर

70 किलोमीटर रिलाइनिंग से राज्य के 10 जिलों के लाखों किसानों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रयासों से इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद पहली बार पंजाब में रिलाइनिंग का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही 23 जनवरी, 2019 को चंडीगढ़ में राजस्थान, पंजाब और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इंदिरा गांधी नहर में रिलाइनिंग कार्य के लिए पहली बार 60 दिन (30 मार्च, 2021 से 28 मई, 2021 तक) की ऐतिहासिक नहरबंदी की गई। राजस्थान क्षेत्र में 238 करोड़ की लागत से 47 किलोमीटर और पंजाब क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर क्षेत्र में रिलाइनिंग के कार्य हुए, यानि कुल 438 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में रिलाइनिंग कार्य हुए। इससे इंदिरा गांधी नहर की 70 किलोमीटर की तस्वीर बदल गई।

रिलाइनिंग से ये होगा फायदा

इंदिरा गांधी नहर में रिलाइनिंग से करीब 300 क्यूसेक पानी का सीपेज प्रतिदिन कम होगा। नहर की लाइनिंग डैमेज होने के कारण बड़ी मात्रा में पानी का नुकसान हो रहा था। अब यह भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। इस बार लाइनिंग कंक्रीट से की गई है। पहले टाइल ईंटों से लाइनिंग व बैड बना हुआ था। घास उगने से लाइनिंग डैमेज हो जाती थी। वहीं मानसून अवधि में बांधों में पानी की आवक अच्छी होने की स्थिति में राजस्थान को अतिरिक्त पानी भी मिल सकेगा। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान की 16.17 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा के साथ-साथ 10 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। लिहाजा इसका फायदा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े 10 जिलों के लाखों किसानों को होगा।

इतिहास में सबसे लंबी 60 दिन की नहरबंदी

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इतिहास में सबसे लंबी 60 दिन की बंदी पहली बार की गई। इससे पहले 35 दिन से लंबी बंदी कभी नहीं की

गई थी। इस बार पंजाब क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर में 60 दिन की नहरबंदी की गई। पंजाब क्षेत्र में कार्य शुरू करने के लिए 29 मार्च को हरिके से पानी की आपूर्ति बंद की गई। पंजाब क्षेत्र में 60 दिन में 23 किलोमीटर रिलाइनिंग का कार्य किया गया। वहीं राजस्थान में प्रथम 30 दिवस आंशिक नहरबंदी की गई। इस दौरान पंजाब द्वारा 1800 क्यूसेक पानी पेयजल हेतु उपलब्ध करवाया गया। अगले 30 दिन पूर्ण नहरबंदी की गई। जिसके अंतर्गत राजस्थान में 28 दिनों में रिकॉर्ड 47 किलोमीटर रिलाइनिंग हुई। 28 मई 2021 को हरिके से इंदिरा गांधी नहर में पानी की सप्लाई 60 दिन बाद दुबारा शुरू की गई।

राजस्थान में 81 साइट पर हुए रिलाइनिंग के कार्य

इंदिरा गांधी नहर में रिलाइनिंग के कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से विस्तृत रूपरेखा प्रमुख शासन सचिव श्री नवीन महाजन के नेतृत्व में तैयार की गई। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता (उत्तर) श्री विनोद मित्तल के निर्देशन में 170 अभियंताओं ने राजस्थान (हनुमानगढ़) की 81 विभिन्न साइटों पर दिन-रात अलग अलग पारियों में कार्य किया। प्रत्येक साइट पर 2-2 अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई। सभी ठेकेदारों के साथ बैठक की गई। चीफ इंजीनियर उत्तर जोन हनुमानगढ़ और चीफ इंजीनियर गुणवत्ता

जयपुर की ओर से भी लगातार निरीक्षण किया गया। रिलाइनिंग के कार्य में लगभग 19.5 लाख सीमेंट बैग, 4 लाख क्यूबिक मीटर बजरी व रोड़ी का प्रयोग करते हुए विभिन्न 81 साइट पर 73 बैचिंग प्लांट स्थापित कर 150 पेवर व 300 ट्राजिट मिक्सरों आदि की सहायता से 3 लाख क्यूबिक मीटर कॉन्क्रिट की गई।

आईजीएनपी की क्षमता में आशातीत बढ़ोतरी

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता (उत्तर) श्री विनोद मित्तल बताते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 1957 में शुरू हुआ था। 1961 में जलापूर्ति शुरू हुई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्षमता 18 हजार 500 क्यूसेक है। पंजाब में निर्माण के बाद रिलाइनिंग नहीं होने के कारण आईजीएनपी जगह-जगह से डैमेज हो गई थी। जनवरी व फरवरी 2021 में 9100 क्यूसेक पानी से ही लाइनिंग धंस गई। ऐसे में पंजाब ने 7 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी चलाने में असमर्थता जता दी। अब जहां ज्यादा लाइनिंग डैमेज थी वहां कार्य हो चुका है। अब पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

पंजाब क्षेत्र में अगली नहरबंदी में होगा बचा हुआ रिलाइनिंग कार्य

इंदिरा गांधी नहर निर्माण के बाद पहली बार पंजाब क्षेत्र में रिलाइनिंग का कार्य हुआ। इस साल 23 किलोमीटर का कार्य हुआ। पंजाब में कुल 100 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग का कार्य होना है। बचा हुआ रिलाइनिंग का कार्य अगले साल, दो साल में नहरबंदी के दौरान पूरा किया जाएगा।

ऐतिहासिक नहरबंदी के दौरान पेयजल की नहीं आने दी समस्या

इंदिरा गांधी नहर के इतिहास में सर्वाधिक 60 दिन लंबी नहरबंदी होने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में कहीं भी पीने के पानी की समस्या नहीं आने दी गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री डॉ बीडी कल्ला, पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत और सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नवीन महाजन ने लगातार सिंचाई विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेकर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की। इसका परिणाम ये रहा कि राज्य के 10 जिलों के 49 शहरों, कस्बों व 7500 गांवों व ढाणियों व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न स्थानों पर स्थित आर्मी को पेयजल की कहीं भी समस्या नहीं आने दी।

कोविड 19 महामारी के कठिनतम दौर में हुआ कार्य

खास बात ये भी रही कि इंदिरा गांधी नहर में ऐतिहासिक 60 दिन की नहरबंदी और रिलाइनिंग का कार्य कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के बीच कठिनतम समय में संपादित किए गए। कोविड महामारी के प्रकोप

से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य किया गया।

राजस्थान में पूर्व में इंदिरा गांधी नहर में हुआ रिलाइनिंग कार्य

इससे पहले मार्च अप्रैल 2018 में 30 दिवसीय नहरबंदी के दौरान 7 किलोमीटर और वर्ष 2019 में 30 दिवसीय नहरबंदी के दौरान 23.06 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग का कार्य किया गया। इस वर्ष 2021 में 47 किलोमीटर का रिलाइनिंग का कार्य मात्र 28 दिन में किया गया है। जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। •

इंदिरा गांधी नहर रिलाइनिंग क्षेत्र व बजट एक नजर में

-पंजाब में 23 किलोमीटर रिलाइनिंग और 200 करोड़ खर्च

-राजस्थान में 250 करोड़ की लागत 47 किलोमीटर हुई रिलाइनिंग

-पंजाब में 60 दिन चला रिलाइनिंग का काम

-राजस्थान में 28 दिनों में हुई रिलाइनिंग

-300 क्यूसेक तक पानी की बचत होगी

-राजस्थान में 81 जगह चला काम

-170 अभियंताओं ने संभाला मोर्चा

राजीविका के माध्यम से कुलविन्द्र कौर बनी आत्मनिर्भर

हनुमानगढ़ जिले में राजीविका के माध्यम से बने स्वयं सहायता समूह के जरिए जरूरतमंद महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जिले के पीलीबंगा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान के गुरूनानक स्वयं सहायता समूह से पिछले 2 साल से जुडी हुई श्रीमती कुलविन्द्र कौर की 2 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के 2 साल बाद अब श्रीमती कौर ना केवल कपड़े के बैग बनाने की मास्टर ट्रेनर है बल्कि कपड़े के बैग की दुकान भी चलाती है। राजीविका की हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सुश्री साज़िया तब्बसुम बताती हैं कि श्रीमती कुलविन्द्र कौर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पति के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। लिहाजा शादी होने के बाद आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। तीन बच्चों को दो वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो गया। राजीविका के माध्यम से पीलीबंगा ब्लॉक में वर्ष 2019 में स्वयं सहायता समूह बनने की शुरूआत हुई। राज्य सरकार की इस पहल के द्वारा कुलविन्द्र कौर गुरूनानक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तथा वे गोलूवाला निवादान में समूह सखी चुनी गई। उनको माह के 2500/- रूपये मिलते थे। जिन्हे वे बचत करके आय वृद्वि गतिविधि में लगाना चाहती थी।

सुश्री साज़िया तब्बसुम बताती है कि कुलविन्द्र कौर को बचपन से ही कपडे से बैग बनाने की सिलाई का हुनर था। श्रीमती कौर को अपनी इस हस्तकला की प्रतिभा को निखारने का मौका राजीविका जिला हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आरसेटी के माध्यम से मिला। प्रशिक्षण के जरिए श्रीमती कौर ने अपनी प्रतिभा को इतना निखारा कि अब वे मास्टर ट्रेनर के तौर पर पहचानी जाती हैं। अब उनकी स्वयं की कपडे के बैग की दुकान है। जिसकी शुरूआत उन्होने समूह से दस हजार रूपये का ऋण लेकर की और आज अपनी आय वृद्वि की गतिविधि को सुचारू रूप से चलाते हुए ना केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। साथ ही अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करवा रही हैं।

पुष्पादेवी का हुआ मुफ्त इलाज

हनुमानगढ़ जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वार्ड नं 07 की रहने वाली 65 वर्षीय महिला श्रीमती पुष्पा देवी गर्ग पत्नी श्री सतपाल गर्ग की 17 मई को कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिजनों ने उन्हें 17 मई को टाउन स्थित निजी अस्पताल बेनीवाल ऑर्थो एंड मेटरनिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। सात दिन के इलाज के बाद श्रीमती पुष्पा देवी ठीक हो गईं और 24 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। लेकिन खास बात ये रही कि श्रीमती पुष्पा देवी के परिजनों को इलाज का एक पैसा नहीं देना पड़ा। सारा इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत मुफ्त हुआ।

दरअसल टाउन का निजी अस्पताल जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इम्पेनल्ड अस्पताल है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिला कलक्टर के निर्देशानुसार इस अस्पताल को कोविड स्पेशल अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। लिहाजा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों का यहां कोरोना का निःशुल्क इलाज हुआ। श्रीमती पुष्पा देवी के इलाज पर कुल खर्च 40 हजार रूपए आया। लेकिन गर्ग परिवार का जन आधार कार्ड बना होने और योजना में रजिस्ट्रेशन करवा चुके होने के कारण इलाज का एक पैसा नहीं देना पड़ा।

ई-मित्र चलाने वाले श्रीमती पुष्पा देवी के बड़े बेटे मोहित गर्ग मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताते हैं कि कोरोना काल में राज्य सरकार जो ये योजना लेकर आई है, इसका बड़ा लाभ आमजन को मिल रहा है। परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित हो जाए तो उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में इस योजना को शुरू करके आमजन को बड़ी राहत पहुंचाई है। उसके लिए हम उनका कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हैं।

लखवीर सिंह का हुआ मुफ्त इलाज

राज्य सरकार द्वारा 1 मई से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ हनुमानगढ़ जिले में आमजन को मिल रहा है। जिले की हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पक्का सहारणा के चक 3 यूटीएस के रहने वाले 24 वर्षीय युवक लखवीर सिंह का 22 मई को बाइक से गांव जाते समय कार से हुए एक्सीडेंट में पैर टूट गया। घुटने के नीचे बड़ा फैक्चर हो गया। परिजन उसे टाउन के इम्पेनल्ड हॉस्पिटल ले आए। जहां लखवीर सिंह का उसी दिन दोपहर बाद ऑपरेशन कर दिया गया। पांच दिन बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। लेकिन खास बात ये कि लखवीर सिंह के ईलाज के लिए उसके परिजनों का एक पैसा नहीं लगा। पूरा इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त हुआ।

दरअसल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जिले में दो अस्पताल इम्पेनल्ड है। लिहाजा लखवीर सिंह का पूरा इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बिल्कुल निःशुल्क हुआ।

खेतीबाड़ी करने वाले लखवीर के पिता श्री बिंदर सिंह बताते हैं कि जब अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। जन आधार कार्ड बना होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिला।

दरअसल श्री बिंदर सिंह के पास खेतीबाडी के लिए जमीन नहीं है। घर का गुजारा अन्य लोगों के खेतों पर मजदूरी करके करते हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना का बड़ा लाभ उन्हें मिला।

श्री बिंदर सिंह बताते हैं कि राज्य सरकार बहुत बढिया स्कीम लेकर आई है। लॉकडाउन चल रहा था लिहाजा पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे। ऐसे में बेटे के एक्सीडेंट होने पर ऑपरेशन और अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 50 हजार का खर्च उठाना पड़ता लेकिन सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात ने हमें उस स्थिति से बचा लिया। हम सरकार का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।

डॉ. प्रीतपाल सिंह सिद्दू ने भिजवाये 375 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

हनुमानगढ़ जिले के ढाबां निवासी और वर्तमान में अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय डॉ. प्रीतपाल सिंह सिद्धू ने संगरिया विधायक श्री गुरदीप सिंह की प्रेरणा से करीब डेढ़ करोड़ रुपए लागत के 355 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हनुमानगढ़ भिजवाए। जो जिले के लिए संजीवनी बूटी साबित हुए। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अमेरिका बेस कंपनी सोलर डायग्नोसिस के सीईओ डॉ प्रीतपाल सिंह की मां ढाबां सरपंच श्रीमती सिमरजीत कौर और उनके भाई श्री रमनदीप सिद्दू ने जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल की उपस्थिति में जिला प्रशासन को सौंपे। जिला कलक्टर के विशेष प्रयास और राज्य सरकार के सहयोग से 12 प्रतिशत जीएसटी में भी छूट मिली।

डॉ. प्रीतपाल सिंह सिद्दू के भाई और वर्तमान में ढाबां में रह रहे श्री रमनदीप सिद्दू बताते हैं कि अमेरीका में रह रहे उनके बड़े भाई को जब दिल्ली में लोगों के रोड़ पर ऑक्सीजन लगाने की स्थिति का पता चला तो उन्होने करीब सवा पांच करोड़ की लागत से 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजने का फैसला किया जिसमें से 335 हनुमानगढ़, 335 खालसा एड और 330 दिल्ली इंटरनेशनल सेवा समिति को भिजवाए गए। हनुमानगढ़ भिजवाए गए 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लागत करीब डेढ़ करोड़ रूपए है।

जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ना केवल हनुमानगढ़ बल्कि पूरे देश में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। अस्पताल में भर्ती हो रहे 60 से 70 फीसदी मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसे में डॉ. प्रीतपाल सिंह ने हनुमानगढ़ जिले को 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निशुल्क भिजवाए। उनसे मरीजों को बड़ी राहत मिली। कुछ समय बाद ही डॉ प्रीतपाल सिंह सिद्दू ने जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ श्रीमती प्रीति जैन को भी करीब 20 लाख लागत के 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे। जो कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हुए।

प्रतिक्रियाएं

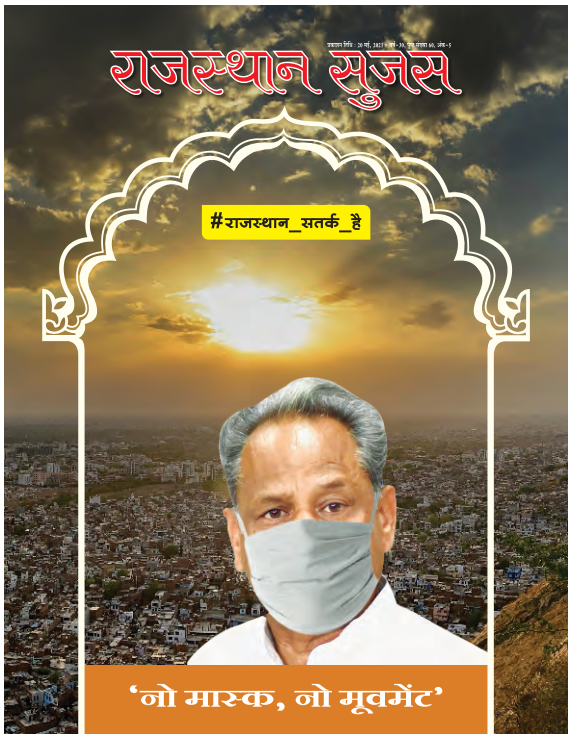

राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका राजस्थान सुजस महंगे मोटे चिकने कागज पर शानदार रंगीन चित्रों सहित छपती है और नियमित हम तक पहुंचती है। काफी समय से उसमें अधिकतर सरकारी प्रेसनोटों का ही फिर से प्रकाशन होता नजर आया है। मगर उसका नया मई माह का अंक जड़ता को तोड़ता प्रतीत होता है जो एक शुभ संकेत है। नई जानकारियां देते हुए विविध विषयों पर दिलचस्प लेख पढ़ कर आनंद आया तो जाहिर है जिज्ञासा हुई कि अभी इसका संपादक कौन है? इसकी जानकारी वाले पन्ने पर पाया कि इसके संपादक हैं डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा और उनके सहयोगी उप संपादक हैं आशाराम खटीक तथा कला संयोजक हैं विनोद कुमार शर्मा। अंक में पदम सैनी द्वारा लिए गए आवरण एवं फोटो फीचर के छाया चित्र भी प्रशंसनीय हैं। एक अच्छा अंक निकालने के लिए इस टीम को बधाई। विभाग के निदेशक इस पत्रिका के पदेन प्रधान संपादक होते हैं। प्रधान संपादक पुरुषोत्तम शर्मा ने संपादकीय में पाठकों से यह वादा किया है कि पत्रिका को अधिक रोचक व ज्ञानोपयोगी बनाने के लिए उनका प्रयास रहेगा, आशा बंधाता है कि राजस्थान सुजस के इस अंक जैसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस अंक को जितना पठनीय विभाग के सेवारत कर्मियों के आलेखों ने बनाया है उतना ही योगदान सेवानिवृत्त अधिकारियों का भी है जिन्होंने अपने अनुभवजनित लेखन से इस अंक का कलेवर संवारा है। वे हैं पूर्व उप निदेशक डॉ. देवदत्त शर्मा, देवी सिंह नरूका, एन के मिश्रा और पूर्व संयुक्त निदेशक ईश्वर दत्त माथुर। राजस्थान सुजस से ही यह भी जाना कि उसके प्रत्येक अंक की 60,000 प्रतियां छपती हैं।

– श्री राजेन्द्र बोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार

नए कलेवर के साथ रचनात्मकता का समावेश सराहनीय पहल है। सुजस की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं।

– श्री वेद व्यास, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी

सुजस का परिवर्तन काबिल ऐ तारीफ है। बधाई!

– श्री ओम सैनी, वरिष्ठ पत्रकार

नव उत्साह, रचनात्मकता के अभिनव प्रयासों के लिए सुजस संपादन टीम को बधाई।

– श्री प्रतुल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार

अछोर बधाई लोकेश जी की टीम को, गुरु बोराजी का भी आभार।

– श्री शुभेन्दु पटेल, वरिष्ठ पत्रकार

सुजस के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

– श्री बजाज कुमार बनज, वरिष्ठ पत्रकार

बहुत अच्छी पत्रिका है ''सुजस''। ग्लोसी पेपर पर फोटोज तो वाकई कमाल की होती है।

– श्री कैलाश मनहर, वरिष्ठ पत्रकार

अबकी बार काफी परिवर्तन है, कई लोगों के लेख हैं: अच्छे हैं, सुधार हुआ है।

– श्री राजेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

अच्छी पत्रिका है ''सुजस'' इस अंक के लिए पूरी टीम को बधाई

– कवि हलीम अन्या

सुजस लम्बे समय से आ रही है।... अच्छी पत्रिका है....

– श्री अनिल भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार

अच्छा हो कि ई-सुजस के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाए, जिससे राज्य सरकार का छपाई एवं डाक पर होने वाले खर्चा बचेगा और लोगों को डीआईपीआर की वेबसाइट पर सुजस उपलब्ध भी रहेगी।

– श्री अशोक भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

जोधपुर विकास प्राधिकरण की

ऐतिहासिक पहल

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री
के कर कमलों द्वारा
श्री शान्ति धारीवाल, मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
की अध्यक्षता में जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों का

भव्य शिलान्यास

जोजरी नदी में उपचारित जल प्रवाह हेतु
उचियारड़ा एवं विवेक विहार में
एसटीपी निर्माण कार्य
परियोजना की अनुमानित लागत
₹ 45 करोड़

65000 हजार वर्गमीटर में
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का
ऑडिटोरियम
बैठक क्षमता 1500 व्यक्ति
परियोजना की अनुमानित लागत
₹ 60 करोड़

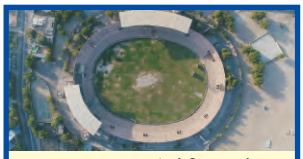

बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को
अन्तर्राष्ट्रीय मैच स्तरीय बनाने हेतु
अपग्रेडेशन/रेनोवेशन
अनुमानित लागत
₹ 20 करोड़

खेजड़ली कला ग्राम में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य अनुमानित व्यय ₹45 लाख	सड़कों के सौन्दर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य ₹ 702 लाख	पुरानी लाईटों के स्थान पर एनर्जी एफिसियेन्ट लाईट लगाने का कार्य ₹ 305.93 लाख	राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय चैनपुरा में स्वीमिंग पूल निर्माण कार्य ₹ 93.17 लाख

लोकार्पण

— जोधपुर शहर की सड़कों का सौन्दर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य ₹ 962.44 लाख —

- रोहिल्ला कल्ला से बुझावड़ तक
- मुख्य बाड़मेर रोड (एन.एच.) से गंगाणा होते हुए राजीव गांधी नगर योजना तक
- सिविल लाईन चौराहे से कमला मेहता चौराहा व केन्द्रीय स्कूल नं. 1 से होते हुए एयरफोर्स टेम्पो स्टैण्ड तक
- माता का थान अमर नगर व रूप नगर दधिमति नगर में सड़क निर्माण
- बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क से भदवासिया पुलिया तक स्टोन पेवमैन्ट का कार्य
- विश्वविद्यालय सर्किल से पीडब्ल्यूडी चौराहा होते हुए अंडर ब्रिज तक
- आयकर कॉलोनी इमरतिया बेरा श्री रूप कंवर के मकान से पावटा सी-रोड
- राजीव नगर ए, बी, सी, डी व अन्य गलियों में डामरीकरण
- वार्ड नं. 61 के रावत नगर में डामरीकरण
- गऊ घाटी स्थित प्रकाश आश्रम में परसाराम जी के मंदिर के गेट से नारू जी के मकान तक स्टोन पेवमैन्ट सड़क निर्माण
- पाली बाजार रिखबचन्द जी के मकान से मण्डोर स्कूल तक स्टोन पेवमैन्ट व सीवरेज का कार्य

— उम्मेद उद्यान में किये गये विभिन्न कार्य ₹ 319.20 लाख —

• अमृत योजना (हरित स्पेस) के अन्तर्गत उम्मेद उद्यान का विकास कार्य • उद्यान में अर्दन जोगिंग ट्रैक का निर्माण • पार्क में रि-कारपेटिंग

— जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में कौटिल्य कौशल नीति केन्द्र का निर्माण ₹ 298.00 लाख —

— सम्राट अशोक उद्यान परिसर स्थित ओपन एयर थियेटर में शेष विकास कार्य ₹ 170.45 लाख —

— किसान कन्या स्कूल, नागौरी बेरा में जेडीए द्वारा निर्मित अधूरे कमरों के शेष कार्य ₹ 14.08 लाख —

नवीन योजनाओं का शुभारम्भ

पाक विस्थापितों के पुनर्वास हेतु	मुख्य पाली रोड पर स्थित	जोधपुर के राजस्व ग्राम बासनी में अवस्थित
विनोबा भावे नगर आवासीय योजना	**ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना**	**महात्मा गांधी नगर आवासीय योजना**
कुल भूखण्ड 1700	कुल भूखण्ड 1391	कुल भूखण्ड 389

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

धरोहर

हनुमानगढ़
भटनेर दुर्ग

– गोपाल गुप्ता
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भटनेर किला। विलुप्त सरस्वती नदी और घग्घर नदी के मुहाने पर 52 बीघा भूमि पर फैला 52 बुर्ज और 6380 कंगूरे वाला भटनेर किला प्राचीन किलों में शामिल है। इसके निर्माण के समय इसमें 52 कुएं थे। वर्तमान में यहां एक टूटा हुआ कुआं है। इसकी स्थापना 295 ई. में हुई। भारत–पाकिस्तान सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले से सटे प्रदेश के नहरी इलाके के हनुमानगढ़ शहर का भटनेर किला जैसलमेर के राजा भूपत सिंह द्वारा स्थापित करवाया गया। जनश्रुति के अनुसार इस किले से पंजाब के भटिंडा तक भूमिगत सुरंग थी। सन् 1805 में बीकानेर के शासक सूरतसिंह ने इसे जाबता भाटी से जीत लिया। मंगलवार के दिन हुई फतेह के कारण जिले का नाम हनुमानगढ़ रखा गया।

प्रकाशक व मुद्रक-सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक- डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, 12, मित्र नगर, हवा सड़क, रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 29.22 रुपये/ 1,00,000 प्रतियां